

Vol. 223
No. 19

Saturday
27 August, 2011
5 Bhadra, 1933 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES
RAJYA SABHA
OFFICIAL REPORT
CONTENTS

Papers Laid on the Table-

Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee
on Social Justice and Empowerment - *laid on the table* (pages 1-2)

Matters raised with permission-

Pitiable condition of weavers in Uttar Pradesh (pages 2-3)

Kerosene lamp and stove blasts in various districts of Assam (pages
3-4)

Special Mentions-

Need to increase the amount of financial assistance to be given to
the widows under BPL in the country (page 4)

Need to increase the budget for laying of Nangal-Talwada Railway
line in Himachal Pradesh (pages 4-5)

Need to exempt the minority educational institutions from national
eligibility tests for entrance in MBBS and PG Courses (page 5)

Need to take immediate steps to expedite the development of
infrastructure in border areas of the country (page 6)

Need to take steps to ensure implementation of reservation for OBCs
in the University of Delhi (pages 6-7)

Statement regarding Government Business (pages 7-8)

Discussion on the Statement by Minister-

Re: Issues relating to setting up of a Lok Pal - *concluded* (pages 8-
134)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE : Rs. 50.00

RAJYA SABHA

Saturday, 27th August, 2011/5th Bhadra, 1933 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2010-11):—

- (i) Action taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies in respect of recommendations contained in Chapter-V of the Twelfth Report of the Committee (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Sixth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on 'Demands for Grants (2010-11)' of the Ministry of Minority Affairs; and
- (ii) Action taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies in respect of recommendations contained in Chapter-V of the Fourteenth Report of the Committee (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Fifth Report of the Committee (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2010-11)' of the Ministry of Tribal Affairs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Government Statement and Government Business. Zero Hour. Shri Rajniti Prasad. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): But, Sir, the agenda mentions about Private Members' Business. ...*(Interruptions)*...

प्रो . राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय ,

मैंने एक वशिष्ठाधिकार हनन का नोटिस दिया है। जैसी तरह से एम.पीज़ . को गालियाँ दी जा रही हैं , मुझे इस मामले को उठाने की इजाजत दी जाए।

श्री उपसभापति : इसे Monday को ले लेंगे। ... (व्यवधान) ...

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : सर, इसे Monday को उठाने दिया जाए , यह बहुत महत्वपूर्ण है।

جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : سر، اسے Monday کو اٹھانے دیا جائے، یہ بہت

اہم ہے۔

श्री उपसभापति : इसे Monday को लेंगे। ... (व्यवधान) ...

श्री उद्वनारायण पाणि (उड़ीसा) : सर, मेरे जिले में डेंगू के मामलों की जांच के लिए एक केन्द्रीय टीम गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उड़ीसा में डेंगू के कारण लोग मर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ पर डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम भेजी जाए। उड़ीसा में डेंगू के कारण 30 लोग मर गए हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : ठीक है। Shri Rajniti Prasad. ... (Interruptions) ...

DR. V. MAITREYAN: Sir, it is neither given in the Bulletin nor have we passed it out.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In extra-ordinary circumstances we are doing this!

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rajniti Prasad. He is not present. Shri Rama Chandra Khuntia. He is also not present. Shri Jugal Kishore. आपका विषय "Pitiable condition of weavers in Uttar Pradesh" है। आप बोलिए।

Pitiable condition of weavers in Uttar Pradesh

श्री जुगल कशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 284.93 लाख हैक्टेयर है। प्रदेश का लगभग 73.06 लाख हैक्टेयर खेती बाढ़ से प्रभावित है। जो देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ... (व्यवधान) ... वह लगभग 21 प्रतिशत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के साक्ष्य 58.72 लाख हैक्टेयर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदियाँ गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, ताप्ती आदि, से वर्षाकाल के समय बाढ़ से ...।

श्री उपसभापति : आपका सबजेक्ट है "Pitiable condition of weavers in Uttar Pradesh". बुझकरों के बारे में है। आपने

बुसकरोँ के ऊपर नोटिस दिया है।

श्री जुगल कशोर : सर, यह मैंने काफी पहले दिया था।

श्री उपसभापति : यह वही है, जो आजके लिये एडमिट हुआ है।

श्री जुगल कशोर : सर, यह बहुत पहले का है।

श्री उपसभापति : यह आज का है। जिसके बारे में आप बोझ रहे हैं, वह एडमिट नहीं हुआ है।

श्री अवतार सहि करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : आप बुसकरोँ पर बोझ दीजिए। बुसकरोँ के भी बहुत मसले हैं।

†[]Transliteration in Urdu Script.

श्री उपसभापति : आपवीबर्स के बारे में बोलिए।

श्री अवतार सहि करीमपुरी : आप बुझकरो के भी बोल दीजिए।

श्री उपसभापति : जो एडमिट हुआ है , आप उसी पर बोलिए।

श्री जुगुल कशोर : उपसभापति महोदय , मैं उस पर भी आ रहा हूँ मान्यवर , मैं इस पर भी बोलना चाह रहा हूँ।

श्री उपसभापति : बाढ़ पर उत्तर प्रदेश के बारे में हो गया है करीमपुरी जी , दूसरे पर... (व्यवधान) ...

श्री अवतार सहि करीमपुरी : सर, बुझकरो के ऊपर बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति : आपका नोटिस बुझकरो के ऊपर है आप उस पर बोलिए और वही एडमिट हुआ है।

श्री जुगुल कशोर : उपसभापति महोदय , उत्तर प्रदेश में बुझकरो की जो समस्या है , वह बड़ी भीषण समस्या है हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मऊ है , आजमगढ़ है , बनारस है , यहां की बनी हुई साड़ियां , यहां के बने हुए कालीन भारत में ही नहीं , बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध हैं वहां पर बुझकरो को काफी समस्याओं के सामना करना पड़ रहा है , चाहे बजिली की समस्या हो या सब्सिडी की समस्या हो। उनको सब्सिडी भी नहीं दी जाती है महोदय , उनकी समस्याओं के नदिन के लिये भारत सरकार को सोचना चाहिए। वहां बहुत बड़े पैमाने पर बुझकर रह रहे हैं , आज उनके खाने -पीने की समस्या पैदा हो रही है।

उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये , केन्द्र से भारत सरकार को भी प्रतिनिधि या मंत्री वहां जाता है , वह उनके लिये पैकेज का ऐलान करता है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज तक उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया गया है और न ही उनको कोई पैकेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीमित साधनों के चलते , उनकी समस्याओं को सुलझाया है और उनकी बजिली की दरें कम करके , उनको सब्सिडी दी है। उनको केन्द्र सरकार से जो मदद मंजुरी चाहिए , वह मदद उनको नहीं मिली है। इसलिए मान्यवर , मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनकी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं , उनको विशेष पैकेज देकर राहत प्रदान की जाए।

Kerosene lamp and stove blasts in various districts of Assam

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Thank you very much, Sir. The incidence of kerosene lamp and stove explosions is spreading like anything in Assam. The incidence of kerosene lamp and stove explosions is taking place in Dhubri, Barapeta, Bongaigaon, Kaimajong, Karbi Anglong and Kamrup districts of Assam and it is spreading to other districts day by day. Till now more than 20 persons died and more than 100 persons injured. Most of them are BPL and minority people. Out of that, most of them are women. Those families which are affected have no electricity facility. Most of them can't afford the electricity facility. They use kerosene oil for their kitchen stove and lighting the lamp. Various district authorities have passed a ban order on the use of kerosene. But the authorities did not make any alternative arrangement for the benefit of the BPL people so that they can get light or prepare their food.

Sir, the local authorities of the Petroleum Ministry or the PSUs who are looking after the production and distribution of kerosene are not taking this issue seriously. I, therefore, urge upon the Government and the concerned Ministries to take this issue seriously and make an inquiry into the matter, to send a high level expert group to assess the situation and to give adequate compensation to those families which are affected by these explosions. Thank you.

SPECIAL MENTIONS

Need to increase the amount of financial assistance to be given to the widows under B.P.L. in the country

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): उपसभापति महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार के माध्यम से दरिद्री रेखा (बी.पी.एल.) के नीचे आने वाली वधिया महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के तौर पर एकमुश्त 10000 रुपए की राशि दी जाती है। यह योजना सालों से कार्यान्वित है। जब से यह योजना कार्यान्वित हुई है, तब से इस योजना के अंतर्गत वधिया महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर 10000 रुपए की राशि दी जाती है। आज तक इस राशि में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज देश में महंगाई आसमान छू रही है। इस महंगाई का सामना करते हुए गरीबों के लिए तो जीमा दूधर हो गया है। दरिद्री रेखा के नीचे आने वाली जिन वधिया महिलाओं के लिए योजना निर्मित की गई है, उन्हें पहले ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सखि से पति का साथ उठने के कारण वे परि वार का भरण-पोषण कैसे करें, उनके सामने यह अहम सवाल बना रहता है। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए 10000 रुपए की यह राशि अत्यल्प है।

इस योजना के माध्यम से दरिद्री रेखा के नीचे आने वाली वधिया महिलाओं को दी जाने वाली राशि में कई गुना बढ़ोतरी होने से ही इन महिलाओं को कुछ आधार मल्लिगा।

महोदय, उपरोक्त वक्षि की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मेरा सरकार से आग्रह है कि राष्ट्रीय परिवार आर्थिक सहायता

योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करके ,
वधिवा महिलाओं को पर्याप्त राशि प्राप्त कराने की एक योजना
तैयार कराई जाए।

Need to increase the budget for laying of Nangal-Talwada

Railway line in Himachal Pradesh

श्रीमती बमिला कश्यप सूद (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति
महोदय , वर्ष 2005 में स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी ने
हिमाचल के दोरे पर हिमाचल सरकार से वादा किया था कि नंगल-
तलवाड़ा रेल लाइन का कार्य 2008 तक पूरा कर दिया जाएगा और रेल
मंत्रालय ने भी इस रेल लाइन हेतु रेल बजट के अलावा 270 करोड़
रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने का वादा किया था , परंतु अभी
उना से अम्ब -अन्दौरा तक मात्र 44 किलोमीटर रेल लाइन ही बन
पाई है तथा शेष 39 किलो मीटर रेल लाइन तलवाड़ा तक अभी बननी
बाकी है।

दूसरी बात , मैं रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगी
कि हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2010-11 वस्तीय वर्ष का

रेलवे बजट 50 करोड़ रुपये था, जिसे घटाकर 38 करोड़ कर दिया गया और 2011-12 के लिये 23 करोड़ बजट रखा गया था, उसको भी घटाकर 10 करोड़ किया गया, यानी 13 करोड़ की यहां भी कटौती की गई। महोदय, हमने तो सोचा था कि हिमाचल प्रदेश सीमा से लगता एक पहाड़ी क्षेत्र है तथा पर्यटन की भी यहां अपार सम्भावनाएं हैं, इसके प्रत्येक जिले को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जबकि हिमाचल प्रदेश में आने-जाने का एकमात्र साधन केवल सड़क ही है और हवाई यात्रा की भी सम्भावना नहीं है, तब हिमाचल प्रदेश के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? मान्यवर, यदि रेल यातायात नहीं देंगे तो हिमाचल का विकास रुक जाएगा।

अतः आपके माध्यम से मेरा रेल मंत्री जी से वशिष्ठ अनुरोध है कि 2012-13 के वित्तीय वर्ष के लिये हिमाचल प्रदेश का रेलवे बजट बढ़ाया जाए और नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन और बलिसपुर-पेम्बुबल्ली रेल लाइन जल्दी से जल्दी बनाकर तैयार की जाए। धन्यवाद।

श्री अनिवाश राय खन्ना (पंजाब): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ।

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ।

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूँ।

Need to exempt the minority educational institutions from national eligibility tests for entrance in M.B.B.S and P.G. Courses

श्री रामविलास पासवान (बिहार): उपसभापति महोदय, भारत सरकार / एम.सी.आई. ने एम.बी.बी.एस. एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला हेतु राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। केंद्र / राज्य सरकार के साथ-साथ सभी निजी वित्तीय सहायता प्राप्त / वित्तिरहित, अल्पसंख्यक एवं गैर-अल्पसंख्यक चिकित्सा संस्थानों को इसके दायरे में रखा गया है, परंतु एम्स, नई दिल्ली एवं पी.जी.आई. चंडीगढ़ को इस चयन प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है।

यह निर्णय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 30 (1) द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त उन अधिकारों का अतिक्रमण है, जसिके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को उनके इच्छानुसार शिक्षण

संस्थान खोलने एवं उसके प्रबंधन का पूर्ण अधिकार प्रदत्त है।

डा॰ अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 (1) द्वारा पूर्ण एवं सुरक्षित अधिकार इसलिए दिया जा रहा है ताकि भविष्य में बहुसंख्यक समुदाय इस अधिकार को छीन न ले।

संविधान संशोधन द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह नज़ी शक्ति संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करे, परंतु अल्पसंख्यक संस्थाओं को इससे वंचित रखा गया। पुनः केन्द्रीय शक्ति संस्थान (आरक्षण एवं नामांकन) अधिनियम, 2006 के दायरे से भी अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर रखा गया।

सरकार को यह नज़ी उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की व्याख्या एवं इससे संबंधित कई मामलों में दिये गए महत्वपूर्ण फैसलों के विपरीत है।

अतः संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनी फैसलों के आलोक में अल्पसंख्यक संस्थानों को राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा के दायरे से मुक्त रखा जाए, ताकि वे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत सुरक्षित महसूस कर सकें।

**Need to take immediate steps to expedite the development of
infrastructure in border areas of the country**

SHRI GOVINDRAO ADIK (Maharashtra): Sir, I would like to raise the serious issue regarding the Border Road Infrastructure Development. The border roads, which are being constructed, are important roads not only from security point of view in the country, but they are equally important for the development of the bordering areas and for the benefit of the people residing in those areas.

Though, a lot of hue and cry has been created regarding development of infrastructure in border areas, it has been noticed with a concern that this development is far from satisfactory. Hence, there is an urgent necessity to take corrective measures urgently for creating required infrastructure in the bordering areas.

It has also been felt that there are lots of procedural hurdles like forest and wildlife clearances, which have already affected various projects adversely. Since the subject-matter is under jurisdiction of various Ministries, there is always apathy and non-co-operation with each other. The delay in granting various clearances just reflect the Central Government in helplessness, and it is also felt that the Government is playing with serious National Security issues. Hence, corrective measures are required to be adopted to accelerate the developmental growth in border areas.

I would also like to mention here that it is a matter of great concern that huge costs are required to be incurred for obtaining the forest and wildlife clearances, which is almost equal to the cost of the project itself in some cases. Moreover, there is a need to change the total approach since a majority of the population residing in these areas are deprived of even basic needs. Hence, projects for uplifting their living status, which have been pending for a long time, should be given priority.

I, therefore urge upon the Government to take immediate steps to accelerate the infrastructure development in the border areas by appointing a single authority, which may expedite the matter and take necessary steps by co-ordinating with different departments for getting the clearances.

SHRI RUDRA NARAYAN PANY (Orissa): Sir, I associate myself with this Special Mention.

SHRI KAPTAN SINGH SOLANKI (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with this Special Mention.

**Need to take steps to ensure implementation of reservation for
O.B.Cs in the University of Delhi**

श्री अली अनवर अंसारी (बहिर) : महोदय , दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत का सबसे बड़ा केन्द्र दूरीय विश्वविद्यालय है। इसके लिए संसाधन सरकार देती है , लेकिन समाचार पत्रों और केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के पत्र से जाहिर हुआ है कि इस विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण पर अमल नहीं किया जाता है।

ऐसा स्नातक , स्नातकोत्तर , एमफिल और पीएचडी कोर्स में हो रहा है। आरटीआई से प्राप्त सूचना से यह जानकारी मिली है कि 2010-11 में विश्वविद्यालय के 30 कॉलेजों में कुल मिला कर 54% ओबीसी सीटें खाली रखी गई , जम्हिले बाद में जनरल कैटेगरी के छात्रों से भरा गया। कुल मिलाकर 7000 ओबीसी सीटें खाली रखने और बाद में जनरल में कनवर्ट कए जाने का अनुमान है।

यह संविधान के 93वें संशोधन और केन्द्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम , 2006 का उल्लंघन है , जिसके तहत केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में 27 फीसदी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। यह तब कथि जा रहा है जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओबीसी कोटा लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से फंड भी लयि है।

हैरत की बात है कि जहां हाई कोर्ट के जज के फैसले के आधार पर जेफनयू ने ओबीसी कोटा पूरी तरह लागू कथि है , वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसी जज के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देकर ओबीसी आरक्षण को उलझा दयि है। ओबीसी के खलिफ यह मुकदमा (LPA 21/2011) दिल्ली विश्वविद्यालय , सरकारी पेसे से लड़ रही है।

इसके अलावा केन्द्र सरकार के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) स्तर पर आरक्षण नहीं दयि जा रहा है। आरटीआई से जानकारी मिली है कि 25 केन्द्र रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के 2563 पदों में सर्फि 4 पर ओबीसी , 11 पर एसटी और 25 पर एससी है।

मानव संसाधन वक़िस मंत्रालय को उपरोक्त मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करके संवैधानिक प्रावधानों और कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (बिहार) : महोदय , मैं इनके वशिष उल्लेख का समर्थन करता हूँ।

श्री वी. हनुमंत राव (आंध्र प्रदेश) : महोदय , मैं भी इनके वशिष उल्लेख का समर्थन करता हूँ।

प्रो . अनिल कुमार साहनी (बिहार) : महोदय , मैं भी इनके वशिष उल्लेख का समर्थन करता हूँ।

श्री अवतार सहि करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : महोदय , मैं भी इनके वशिष उल्लेख का समर्थन करता हूँ।

प्रो . राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय , मैं भी

इनके विशेष उल्लेख का समर्थन करता हूँ।

DR. GYAN PRAKASH PILANI (Rajasthan): Sir, I also associate myself with this Special Mention.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we all associate ourselves with this Special Mention.

STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJEEV SHUKLA): Sir, I beg to announce that the Government Business in this House for the week commencing 29th August, 2011, will consist of:-

1. Further consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:-

(a) The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill, 2011; and

(b) The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2011.

2. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok

Sabha:—

(a) The Institute of Technology (Amendment) Bill, 2011;

(b) The National Institute of Technology (Amendment) Bill, 2011;

(c) The Customs (Amendment and Validation) Bill, 2011;

(d) The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram, Bill, 2011; and

(e) The Educational Tribunals Bill, 2010.

3. Consideration and passing of the following Bills:—

(a) The Copyright (Amendment) Bill, 2010;

(b) The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010;

(c) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2010;

(d) The Seeds Bill, 2004; and

(e) The Pesticides Management Bill, 2008.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, at 12 o'clock, the hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, will be making a statement on the issues relating to setting up of a Lokpal, and there will be a discussion on the issue.

The House is adjourned till 12 o'clock.

The House then adjourned at twenty-one minutes past eleven of the clock.

The House re-assembled at twelve of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair

DISCUSSION ON THE STATEMENT BY MINISTER

Issues relating to setting up of Lokpal

श्री राजनीति प्रसाद (बहिर) : सर, हम एक अहम मुद्दा उठाना चाह रहे हैं: ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आप ज़रा एक मिनट बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ... Hon.
Shri Pranab Mukherjee to make a statement on issues
.... (Interruption) ...

श्री राजनीति प्रसाद : सर, यह बहुत महत्त्वपूर्ण है... (व्यवधान)...

श्री राम कृष्ण यादव (बहिर) : सर, यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप ज़रा एक मिनट बैठ जाइए। ... (व्यवधान)...

श्री राजनीति प्रसाद : सर, पार्लियामेंट के लोगों को 'मौगा' कहा गया, 'चोर' कहा गया, 'बेईमान' कहा गया। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : देखिए, आपको यह सवाल ज़ीरो ऑवर में उठाना चाहिए था। आप बैठ जाइए प्लीज़। ... (व्यवधान)...

श्री राम कृष्ण यादव : सर, लोग अपमान कर रहे हैं... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आप ज़रा बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ... राजनीति जी, आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ... प्लीज़ ... (व्यवधान) ...

श्री राम कृष्ण यादव : सर, इसका क्या मतलब है? ... (व्यवधान) ... क्या हम चुप रहेंगे? ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आप ज़रा बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ... Rajnitiji, please resume your place. ... (Interruptions) ... आप ज़रा बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ... आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब बोलिएगा। ... (व्यवधान) ... राजनीति जी, प्लीज़ बैठ जाइए। Hon. Shri Pranab Mukherjee.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman Sir, I rise to make a statement on issues relating to Lokpal on which a vigorous debate has been going on both inside and outside the Parliament.

At the outset, I will like to, once again, request Shri Anna Hazare to end his fast in view of the appeal made by the Prime Minister in his statement in the other House, in view of the Resolutions adopted by the leaders assembled at an all political party meeting. I do hope, Shri Hazare will respond and end his fast.

Mr. Chairman Sir, I seek your indulgence to recount the sequence of events which has brought us to where we are today. On 5th of April, 2011, Shri Anna Hazare went on an indefinite fast. Interlocutors between his representatives and those of the Government discussed and he gave some conditions; those conditions were accepted; on the 8th April, 2011, the Government constituted a Joint Drafting Committee

consisting of ten members, five...(Interruptions)...

श्री वीर पाल सहि यादव (उत्तर प्रदेश): सर, हद्दी में स्टेटमेंट की कॉपी नहीं आई है।

श्री सभापति: आप एक मिनट बैठ जाइए। यह अभी आ जाएगी। ... (व्यवधान) ...

श्री राजपाल सहि सैनी (उत्तर प्रदेश): सर, यह हद्दी में क्यों नहीं आई? ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: यह अभी आजाएगी। ... (व्यवधान) ...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We will see if we can circulate it during the day.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सर, हमें इसकी कॉपी हद्दी में भी दखिवा दीजिए।

श्री सभापति : नरेश जी, आपको इसकी कॉपी मल्लि रही है। ... (व्यवधान) ...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : या तो अंग्रेजी को मातृभाषा मान लीजिए।

श्री सभापति : देखिए, इसका हब्दी में interpretation चल रहा है, आप हब्दी में सुन सकते हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, यह प्रश्न नहीं है। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आपको इसकी कॉपी हब्दी में मल्लि जाएगी। ... (व्यवधान) ... आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ... आप थोड़ा सब्र कीजिए। ... (व्यवधान) ...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, अगर वह मंत्री जी बांग्ला में बोलने लगे, तो ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आपको यह थोड़ी देर में मल्लि जाएगी। ... (व्यवधान) ... आप बैठ जाइए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : सभापति जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं बाहर प्रणब बाबू को टेलीविजन पर सुन रहा था। प्रणब बाबू ने कहा कि सारा विश्व इसको देख रहा है और सारा देश भी देख रहा है। लोकपाल वधियक को लेकर लोग आन्दोलित हैं। सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन सारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (गुजरात) : सर, गुजरात के हाई कोर्ट में ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : प्लीज ... (व्यवधान) ... प्लीज ... (व्यवधान) ...

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : सर ... (व्यवधान) ... हाई कोर्ट में अपील की गई है ... (व्यवधान) ...

प्रो. अलका कृत्रिय (गुजरात) : सर, मैं कहना चाहती हूँ ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : देखिए, प्लीज ... (व्यवधान) ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, मेरा इतना कहना है ... (व्यवधान) ... देखिए, मेरा इतना कहना है कि मैं समझता हूँ कि आज इसका हब्दी अनुवाद नहीं हुआ है। पर, आगे से सदन को और सदन की कार्यवाही को इस तरह से न चलाया जाए। हब्दी अनुवाद भी हर वक्त उपलब्ध होना चाहिए।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, आजके लिये हम इसको भूल जाते हैं और आजइस पर चर्चा शुरू की जाए।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Mr. Minister, you please now proceed with your statement. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Chairman, Sir, I am sorry that the Hindi translation is not available for the use of the Members. It was decided at late night yesterday because we were discussing with the leaders of opposition of various political parties. The situation was moving out of hand. A crisis has been created. It was decided that I will make a statement in both the Houses. The entire exercise was over around 11.00 p.m. in my office yesterday. Therefore, it was not possible. I agree that there is a lapse. But as I started my observations in the other

House that there are occasions when we shall have to rise, when we shall have to keep in mind that not all but on occasions the issues which we discuss here or in the other House draw the attention of the entire nation. Substance is important; format is also important; form is also important. But sometimes it may happen. I regret that there has been a lapse on my part. That will be corrected. Shortly, the Hindi translation will be given. But let us carry on the discussion.

I would like to seek the indulgence of this House, which more than often I have sought, Sir, because I think, since 1952, when this House was constituted, till today, I have the record that I have the privilege of serving this House for the longest period. I do not know somebody else may break that record. ...(*Interruptions*)... Though I have left this House, but the House is kind enough, and indulgent enough to bear with my requests, bear with my lapses on so many times. I am deeply grateful for that. I would like to recollect the chronology of the events with which I started, that what has led us to the situation where we are today.

Sir, as I mentioned, on the 5th of April, Shri Anna Hazare sat on fast. We did not want him to continue on fast because from day one there was no doubt in the mind of the Government that the issues on which Shri Anna Hazare and his colleagues were agitating are genuine issues, are not partisan issues, to eradicate corruption and to have an effective institution like Lokpal to tackle it. There are no two opinions on it. I am not going into the history of the Lokpal Bill as to how many times it came before the Parliament. In the course of reply, I may have to return to it. But right now, I would like to confine myself with some of the chronological events. So, on 8th of April, we appointed the Joint Drafting Committee, consisting of ten members – five nominated by Shri Hazare, including himself; and five nominated by the Prime Minister, with me as the Chairman and Shri Shanti Bhushan as the co- Chairman. The Government representatives were all Ministers. Shri Hazare ended his fast on 9th April, 2011. The

Joint Drafting Committee met nine times from 16th of April to 21st of June. In the first meeting of the Joint Drafting Committee on 16th April, 2011, preliminary discussions were held to draft the legislation for the Lokpal. During the second meeting of the Committee, 40 basic principles and the Statement of Objects and Reasons were circulated by Shri Anna Hazare's team, which formed the basis of discussions in the subsequent meetings. There were extensive deliberations on the basic principles wherein the scope and vision of the proposed Lokpal were discussed. Some parts of my observations will not be in the statement and I am making it extempore to clarify but I will authenticate the full statement which I am making and lay it on the Table of the House. Please excuse me for that because I seek to clarify this particular point. Then out of 40 basic principles, 20 were agreed, there was no problem. Seven were agreed with just legalistic language to be

put in. There has to be legal language as it would be the part of the law. And on seven other issues there was agreement in principle but it required further discussions. That accounts for 34 of the 40 basic principles. But six issues were there where there was serious divergence of views. I will narrate those six issues. The six major areas of divergence of views were:-

1. Should one single Act be provided for both the Lokpal in the Centre and Lokayukt in the State? Would the State Governments be willing to accept a draft provision for the Lokayukt on the same lines as that of the Lokpal?
2. Should the Prime Minister be brought within the purview of the Lokpal? If the answer is in affirmative, should there be a qualified inclusion?
3. Should Judges of the Supreme Court and High Courts be brought within the purview of the Lokpal?
4. Should the conduct of Members of Parliament inside Parliament, their right to speak and right to vote in the House, be brought within the purview of the Lokpal? Presently such actions of the Members of Parliament are covered by article 105(2) of the Constitution.
5. Whether articles 311 and 320(3)(c) of the Constitution notwithstanding members of a civil service of the Union or an All India Service or a Civil Service of a State or a person holding a civil post under the Union or State, be subject to enquiry and disciplinary action including dismissal and removal by the Lokpal and Lokayukt, as the case may be?
6. What should be the definition of the Lokpal, and should it itself exercise quasi-judicial powers also or delegate these powers to its subordinate officers?
7. As these issues were of significance and affecting the larger areas, I decided to write to the Leaders of some political parties and State Chief Ministers. On 31st May, 2011, I wrote to the Presidents of various political parties and the Chief

Ministers of States soliciting their views on six contentious issues. Responses were received from 25 Chief Ministers and six Party President and Leaders. I would just like to state a few lines extracted from their observations. I would just like to state only a few lines extracted from their observations. BJP President in his letter dated 2nd June 2011 stated and I quote, *"Expecting political parties to give their views to a drafting committee comprising of Civil Society representatives for acceptance or otherwise would be upsetting the constitutional propriety where parties, parliamentarians and the Parliament have the last word They are the decision makers and not suggestion*

givers ... " The General Secretary of CPI said that "as a political party, they will most certainly state their views and suggestions during the discussion on the Bill within the Parliament." The President of the BSP, expressed her inability to respond to the issues raised as no BSP representative had been included in the discussion of the JDC. She also stated that in parliamentary democracy, the Bill has to be examined by the Parliament and the Standing Committee where detailed discussions are held. The National General Secretary of the Samajwadi Party in his letter stated that Government was holding a direct discussion with the so called representatives of the Civil Society in the JDC. On the other hand the leaders of the political parties have been sent a questionnaire. This was not acceptable to the Samajwadi Party and hence they will not send any reply. The Joint Drafting Committee, as I mentioned, met nine times and concluded its deliberations on 21st June, 2011 and both sides exchanged their drafts for the Lokpal Bill. Both these drafts were forwarded to the Government for further action.

8. To solicit the views of various political parties, after this meeting, a meeting of all political party meeting was convened on 3rd July 2011, During the discussions, the representatives of various political parties emphasized that and I am just mentioning two points:-

The supremacy of the Constitution of India has to be maintained, Institutions of democracy cannot be undermined and the checks and balances visualized in the Constitution cannot be adversely affected, Laws have to be made by the Parliamentarians who are elected representatives of the country. Few nominated members of the Drafting Committee cannot have precedence over elected members of the Parliament.

9. At the end of the meeting, on the conclusion of this meeting. it was unanimously resolved and I quote "Government should bring before the next session of Parliament a strong and effective Lokpal Bill, following the established procedures". Mr. Chairman, Sir, Government exactly did the same. Whether it is strong or effective it is for the judgment of this hon. House.

10. This meeting was followed by an informal discussion by some of our colleagues along with some of the leaders of some political parties and their informal suggestions were also incorporated in the Bill which was sent to the Standing Committee after it was introduced in the House.
11. In pursuance of the directions of the All Party Meeting, the Government worked on the draft Lokpal Bill prepared by the Joint Drafting Committee and after following the formal process of inter-ministerial consultations and Cabinet approval, the Bill was introduced in Parliament on 4th August, 2011.

12. Unfortunately, even before the Bill could be introduced in the Parliament, Shri Anna Hazare's representatives restarted the agitation by burning copies of the draft Lokpal Bill. Shri Hazare also declared that if the Jan Lokpal Bill is not passed by the Parliament by 15th August, 2011, he would proceed on indefinite fast with effect from 16th August, 2011.
13. The Prime Minister, through his Independence Day Address, on 15th August, again implored Shri Hazare to abstain from the fast. This appeal was ignored.
14. On 16th August 2011, Shri Anna Hazare has again proceeded on fast. In view of his deteriorating health and Government's increasing concern for Annaji's condition, hon. Prime Minister wrote a letter to him on 23rd August 2011, making a fervent appeal for ending the fast.
15. To carry the negotiations forward, the Prime Minister directed me and Shri Salman Khursheed to hold discussions with the representatives of Shri Anna Hazare. We did so. A meeting was held on 23rd August, 2011, and it was clarified to Shri Anna Hazare's representatives that:-

Lokpal Bill is now before the Standing Committee. All options are open before the Standing Committee to consider not only the Bill introduced by the Government but the Jan Lokpal Bill as well as other versions sent by eminent members of Civil Society.

In deference to the wish expressed by Annaji, the Government is prepared to request the Speaker Lok Sabha – since the Bill originated from there – to formally refer the Jan Lokpal Bill to the Standing Committee for its consideration along with everything else.

About time and speed, the Government can formally request the Standing Committee to try, subject to its discretion, fast tracking their deliberations to the extent possible.

I explained to Annaji's representatives that Lokpal Bill alone cannot root out corruption. We need multi-layered laws to deal

with corruption at various levels. In addition to the Lokpal Bill, we are willing to strengthen the Judicial Accountability Bill and the Whistle Blowers Bill. We are also working on a Grievance Redressal Bill to tackle corruption at local level.

16. I again asked Annaji's representatives to convey our earnest request to him to end the fast and give us the space required to proceed in the matter.
17. At this stage, Annaji's representatives made the following demands. As it was in a

written form, I am bodily reproducing it exactly in the same languages as it was given to me:-

"If the Government can agree to introduce Jan Lokpal Bill (after removing those items on which we have differences) after clearing by the Ministry of Law within four days and also provide a commitment that the Bill will not be referred to the Standing Committee and will be discussed and passed (with minor amendments adopted by Parliament) during this session of Parliament (even if it is extended), we can then hopefully persuade Annaji to stop this fast.

(Above to be a written commitment with time lines)."

Mr. Chairman, Sir, when the meeting was over, it was around 10.15 at night. But, immediately, I contacted the hon. Prime Minister. He was kind enough to call the meeting of the Cabinet Committee on Political Affairs. I explained what transpired. And the Cabinet Committee on Political Affairs deliberated and took a decision and authorised me to convey this decision to them next day. As all of you are aware the next day an all-India and all-political party meeting was scheduled to be held. Therefore, I decided that I will also place, for information and to seek suggestions, in the all-party meeting what had transpired between me, Shri Salman Khurshid and the representatives of Shri Anna Hazare. Annaji's representatives also insisted upon the inclusion of following substantive issues, as a part of the Jan Lokpal bill: Public Grievances and Citizen Charter; Lok Ayukta; and the Lower bureaucracy. I will come to these three items a little later because these are the three items which have assumed importance, now, because we are told that Shri Anna Hazare may take a decision on how we, the Members of Parliament, collectively respond to these issues. Therefore, I raise these issues as I think it would be proper to seek your considered views on those issues. At the conclusion of the meeting, Annaji's representatives were informed, on the same day. At the conclusion of All Party Meeting held on 24th August 2011, the following unanimous resolution was passed; and, as I mentioned, I briefed the all-party meeting - who are present here;

they will bear me out – in detail what transpired between me and the representatives of Shri Anna Hazare. I am quoting the resolution adopted by the all-party meeting, “This meeting of all political parties in Parliament requests Shri Anna Hazare to end his fast. The meeting was also of the view that due consideration should be given to the Jan Lokpal Bill so that the Final Draft of the Lokpal Bill provides for a strong and effective Lokpal which is supported by a broad national consensus.” In a late evening meeting held with Annaji’s representatives on 24th August 2011, I conveyed the inability of the Government to accept the conditions put forward by them on 23rd August, 2011 and as referred to by me earlier.

The Prime Minister made a statement in the other House on 25th August, 2011 reiterating our Government's commitment to the passage of a strong Lokpal Bill. The Prime Minister also stated that he would welcome the Members of the House to discuss the Lokpal Bill before the Standing Committee, the Jan Lokpal Bill as well as other draft Bills and views of members of Civil Society which have been brought to the attention of the Government. I believe that the entire House is committed to the eradication of corruption at all levels.

Mr. Chairman, Sir, our Government is committed, therefore, to bring an appropriate legislation as well as put in place mechanisms that will reduce discretion and bring transparency in the functioning of public offices as well as take strong measures against those who indulge in corruption. Apart from other issues, the three issues that we need to discuss – and which have assumed importance, as I stated earlier are as under, I am placing these for the consideration of my distinguished colleagues in this House: (i) Whether the jurisdiction of the Lokpal should cover all employees of the Central Government? (ii) Whether it will be applicable through the institution of the Lok Ayukta in all States? (iii) Whether the Lokpal should have the power to punish all those who violate the 'grievance redressal mechanism' to be put in place? I will request my distinguished colleagues to have an objective discussion on it and consider all these issues. If there be a broad consensus on these issues, Mr. Chairman, Sir, on behalf of the Government, I can assure you that we will be part of the consensus-making and not consensus breaking. We will go with the spirit of this House and the spirit of the other House. Therefore, my most fervent appeal to my colleagues in this House would be that this is very crucial, please give your considered views on these issues.

The specific issues raised by Shri Anna Hazare are important. They deserve our serious consideration. In case a consensus emerges at the end of the discussions, the Standing Committee will, in the course of their deliberations, take into account their practicability, implementability and constitutionality. For everything that we do, must be consistent with the principles enshrined in our Constitution.

I believe that the Government has amply demonstrated that it is

sensitive to the Shri Hazare's Movement; common man's concern about corruption. It has also requested Shri Anna Hazare Ji to give up his fast by assuring him that all these issues raised by him will be discussed by the Standing Committee. In the House, when we finalize the Lokpal Bill, all these will get adequately reflected.

Before I conclude, Mr. Chairman, Sir, I would like to make an appeal to my colleagues. As I mentioned earlier, sometimes, debate of this House and of the other House draws attention of the people at large. What we are saying and what we are doing today is catching attention of

people all over the country because people are anxious about what is going to happen and whether the impasse will be resolved or not. An expectation has been raised. Therefore, my respectful submission would be, let us rise to the occasion. Let us not indulge in triviality and scoring of brownie points here and there. If, collectively, this House leads to a process of consensus-building, on behalf of the Government, Mr. Chairman, Sir, I would like to reassure you that we will be part of consensus-making and not consensus-breaking. We will like to go with the wishes of the House as reflected by the observations of the Members in a collective manner. With these words, I thank you, Sir, for giving me this opportunity.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Hon. Members, if the House agrees we can allocate 4 hours for issues relating to setting up of a Lokpal. ...*(Interruptions)*...

श्री शक्तिनन्द तकिरी (बहिर) : सर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: No; no. ...*(Interruptions)*.. One at a time. ...*(Interruptions)*...

श्री शक्तिनन्द तकिरी : सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: One at a time please. ...*(Interruptions)*... I would like to know the views of the hon. Members. ...*(Interruptions)*...

श्री शक्तिनन्द तकिरी : सर, इस पर सभी सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त मौका मल्लिना चाहिए। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि...*(व्यवधान)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, it is a very important subject. ...*(Interruptions)*... It is a very important issue and we request, Sir, that there should not be any time-limit; by evening we should finish it.

But we should get all opportunities to ventilate our views on this subject and there should not be any time limit for this.

MR. CHAIRMAN: We would still need to allocate time to parties and Members. ...*(Interruptions)*..

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, six hours may be allocated. ...*(Interruptions)*... You can suspend the lunch hour...*(Interruptions)*...

श्री शिवानन्द तकिरी : हम इसके लिए छः घंटे का समय भी पर्याप्त नहीं मानते हैं। उस हाउस में सात घंटे का समय तय हुआ है। अगर सात घंटे में भी बात पूरी नहीं होती, तो time extend किया जा सकता है। ... (व्यवधान) ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, इसके लिए time extend करें, ... (व्यवधान) ...

श्री शिवानन्द तकिरी : यदि छः घंटे में बात पूरी नहीं होती है, तो छः घंटे को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण वषिय है। ... (व्यवधान) ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, आप lunch hour suspend करिए और छः घंटे का discussion शुरू करिए।

MR. CHAIRMAN: All right. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): May I suggest something, Sir?
...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Yes please. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: Mr. Chairman, Sir, my first suggestion is to please extend it from four hours to six hours. The second suggestion is that make it extendable. Allocate time according to six hours.
...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Is there a general agreement on this - six hours and extendable? ...(Interruptions)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, kindly cancel the lunch hour. This is a very important issue. There should be a detailed discussion on this in the House. Initially, seven hours may be allocated. If necessary, cancel the lunch hour. During the lunch hour also, we can discuss it. ...(Interruptions)...

श्री सभापति : पासवान जी, आपभी बताइए।

श्री रामविलास पासवान (बहिर): सर, मेरा यह आग्रह है कि यह historic debate है, यह ऐतिहासिक क्लषण है, हम इसमें victim हो जाते हैं, बड़े-बड़े दलों को तो पूरा समय मल्लि जाता है, हमें तो point रखने के लएि तीन या पांच मल्लिट ही दएि जाते हैं। इसके लएि time का कोई बंधन नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ऐतिहासिक क्लषण है, मेरा आपसे यही आग्रह है।

MR. CHAIRMAN: All right. I have got the sense of the House. Hon. Members, we will start with six hours, extendable, and there will be no lunch break. Now, I call the first Member, the hon. Leader of the Opposition.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, we have just heard a detailed Statement from the hon. Finance Minister on the entire background of the negotiations, leading up to the present situation. We have also just witnessed a great amount of enthusiasm in this House, with a very large cross-section of Members wanting to participate in this debate. This, Sir, itself is an evidence of the sense of responsibility which Members of Parliament really have in

responding to the challenges as they emerge before the country. Sir, in the last two weeks, on events arising out of Shri Anna Hazare's fast, this is, actually, the third debate. The first one, I must concede, was confrontationist on the day when Shri Anna Hazare was, unfortunately and regrettably, arrested by the Government. In the second debate earlier this week, we debated with a great sense of maturity, as to how to deal with this larger problem of corruption and graft in Indian society. It was a little less confrontationist. Today, really, the maturity of all of us and our democracy is on trial. There is a popular agitation or movement

going on in the country, which has sent to us a message, very loud and clear, that people of this country are no longer willing to accept the present *status quo*. The present *status quo* is that corruption in many areas has almost become a way of life. People in higher positions have a tendency to get away. There are cover ups. They have various instruments and technicalities available to them, where accountability norms are not very high. And, there are lesser areas of society where the average man has to confront with corruption really almost as a way of life. We discussed all these areas two-three days ago and therefore I don't intend to repeat them.

Sir, in the course of this entire agitation and the debate that it has thrown up in the last few weeks, we have also heard some not-so-complimentary statements made about Parliament and MPs. I would only urge my colleagues that our sense of maturity must compel us not to be provoked by anyone of them. It is our actions and how we respond to them which will be the best response of Indian democracy to all these statements which are made.

When we decide it – and today we are not legislating, we are only deciding the basic parameters of what should be the kind of integrity-institution in India, which is the Lokpal, and, we are also deciding as to which are the areas which must come within its scope and which should be kept outside – I think we must be guided by two basic principles. The first is, the time has now come to raise the bar of accountability in Indian society. Routine structures have not succeeded till date. They have not responded to the enormity of the challenge that we face. And, the second is that when we think in terms of a scheme as to how to deal with it, we don't overreact or go in for knee-jerk reactions where we find solutions which are not consistent with our constitutional scheme. Therefore, even though I don't think that in this case we are legislating in haste, we must remember that we must be guided predominantly by two vital considerations which are: the need for probity and the need to coexist with the constitutionalism as far as India is concerned.

Sir, the whole concept of a Lokpal was first borne out when the Administrative Reforms Commission in 1966 had recommended the

establishment of a Lokpal and a Lokayukta Bill. In fact, it is very little known that at that time the Bill was actually introduced in 1968 by none other than Shri Y.B. Chavan and while introducing the Bill, the Statement of Objects and Reasons was that the efficiency and integrity of public services should be kept in mind. So, this whole question of Citizens Charter or public grievances is not a new concept which is being brought into the system today. This was a part of the concept which was recommended by the Administrative Reforms Commission way back in 1966, and, in the 1968 Bill – 1st May, 1968 to be precise – which Mr. Y.B. Chavan introduced, this concept was very much there. It had two concepts and that perhaps may help Mr. Pranab Mukherjee to find an answer to the questions he has raised before us. Public grievances were a part of it; the concept of Lokayukta in the States was also a

part of that 1968 Bill. It is not something which has now been taken out of the hat and suddenly we are confronted with it. In fact, in the report which Mr. Pranab Mukherjee himself authored in 2001 as the Chairman of the Standing Committee, there is an important Preface which I must read to my distinguished colleagues here. It says, "The term "Lokpal" – and I am quoting from the Report – is the Indian version of "Ombudsman." Ombudsman is a Swedish term meaning 'one who represents someone else.' In other words, the term means, 'a grievance-man.' Ombudsman is an official who is appointed to investigate complaints against administration. More specifically, he is an officer who investigates complaints of citizens of unfair treatment meted out to them by Government Departments and suggests remedies thereof, if he finds that the complaint is justified." Now, 'ombudsman' was a Scandinavian concept and, coincidentally, on 3rd April, 1963, then an Independent young Member of the Lok Sabha, Dr. L.M. Singhvi, in the course of his participation in a debate for having an ombudsman in India, attempted to find out what the Indian equivalent could be, and this word 'Lokpal' was added to our vocabulary, the Hindi vocabulary, by Dr. L.M. Singhvi who translated this word. Now, it is a coincidence that his very distinguished son, Dr. Abhishek Manu Singhvi, now has to prepare the final draft of this Bill. I am sure, he will keep in mind the great heritage, not only his personal, but also of this concept, and strengthen this Bill in order to maintain this very strong heritage as far as this Bill is concerned. In fact, the senior Dr. Singhvi defined the term 'Lokpal' or the 'Lokayukta', which he had coined, as 'the Indian model of ombudsman for the redressal of public grievances'. Now, that answers one of the questions we have squarely raised today, as to what should be the width of the activities as far as the Lokpal in India is concerned.

Now, this Bill, which was first introduced by Shri Y.B. Chavan, was actually passed by the Lok Sabha in 1969 – this fact is mentioned very rarely in our present discourse – but because of the split in the Indian National Congress then, the Lok Sabha was dissolved soon thereafter and the Rajya Sabha could not pass this Bill. Otherwise,

this country would have had, but for that split of 1969, a Lokpal Act way back in 1969-70, and the entire series of events which have taken place in the last few months would have been really unnecessary because we would have gone about strengthening this institution from day to day.

Sir, I said that we must not legislate in haste. I do not think we are legislating in haste. We worked on nine different drafts of this Bill in 42 years. Democracy cannot be so lethargic a system that it takes 42 years to really develop a consensus as to what a Bill should be. We have almost discussed and debated every aspect of the Bill. Whether the Prime Minister must be covered by the Lokpal or he must not be covered by the Lokpal, and so on, are areas which we have sufficiently covered and, I think, the time has now come when this whole concept of Lokpal

at the Centre, as an effective institution, and Lokayukta in the States became a hard reality as far as India is concerned.

Sir, before I come to the specifics, I think, today's debate is not, and should not, be on generalities. The Finance Minister, in his opening statement, has said that earlier there were six questions which he had posed to political parties and now there are three questions which need to be addressed by each one of us so that the sense of the House can be taken. Therefore, the need for today's debate is not that we express ourselves in generalities and just say, 'India needs a Lokpal and it must be a strong and effective Lokpal'. When it comes to the specifics and the nuts and bolts of what those provisions of the Lokpal should be, we skip that part of the debate. I think, today, all of us have to respond to this challenge which the Indian society is posing before us, and that is the strength of Indian democracy. We have to respond to each one of these questions which have been raised, not merely by the civil society but by the people at large today. We must not unnecessarily get into a position that there is the situation of Parliament versus civil society.

Sir, there are two basic principles that we have to keep in mind when we legislate. In any developing society, in any mature society, there will be a role for civil society. They are hard realities; they will exist. Some of them may take positions which seem a little excessive which may not be implementable. But then we must realize that their role is one of being a campaigner or a crusader or a flag-bearer on several issues. They rise, try and compel the decision-makers to change their views and come on track with their kind of opinion. We have the option of agreeing with them; we have the option of not agreeing with them. The second principle we have to bear in mind is - and nobody can dispute this - that Indian Parliament is supreme when it comes to law making. Laws cannot be made anywhere else except in the Indian Parliament. So, even when pressure groups build up pressures in the society, we must concede to them the right to build up pressures but not be provoked by them; we must not lose our sense of rationality as to what we are to accept and what we are not

to accept and we must legislate keeping in mind the basic principles and the values of Indian society both from our conditions, both from our administrative experiences, experiences of our democracy as also our constitutional values. And this is what we are going to endeavour today. What we must not do is to engineer a kind of a confrontation either between Parliament and civil society or Government and civil society. The maturity of Indian polity is that we must not allow ourselves to get provoked and, therefore, we must still keep all rationality in mind and, therefore, legislate accordingly as far as these principles are concerned. Sir, there are several questions that hon. Finance Minister had raised, and I hold his statement. I first come to the original six questions that he had raised.

One of the questions he says is, "Should a single Act provide for a Lokpal in the Centre and Lokayukta in the States?" I think you have to answer this question keeping two factors in mind. There is a need for a strong Lokpal in the Centre and there is a need for a strong Lokayukta in the State. The appointment of Lokayukta in States will not be made by the Centre. It will only be made by the mechanism as far as the States are concerned. So, that mechanism must be a State mechanism. Under no circumstances must Centre be seen as appointing or interfering in the Lokayukta of the States. Now, the recent incidents have actually brought a bad name to the institution of Lokayukta where in one of the States we find that the elected Government is completely bypassed and a Lokayukta is appointed. ...(Interruptions)... Once these kinds of events take place, then a question will arise in various minds 'Is someone going to use or misuse the institution to fix his political opponents?' Once we succeed in conveying that – and recent events have conveyed that – that probably will lead to the death of the Lokpal institution even before it is created because its credibility will be gone and the purpose of its creation will be defeated. So, we must refrain from doing that and not treat this as an adversarial exercise. What is a Lokpal or a Lokayukta supposed to do? When a complaint comes that some public servant or a Minister or a civil servant has indulged in a misconduct, he has to examine the evidence. He then has to peruse the evidence and decide whether it is a case of misconduct, whether it is a criminal offence or an offence which involves an administrative action. This requires assessment of evidence. Assessment of this evidence can be done by people who have a fair mind. Anybody whose appointment is brought in with a motive or anybody who is not well-versed in the art of assessing evidence, whose investigative or judicial or quasi-judicial abilities are suspect will not be able to do that. Therefore, when we appoint these, we must bear in mind that you need it in both the places. Your Government....

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would like to add that the responses which we got from various Chief Ministers, not all, say that they would like to have their own law of appointing the Lokayukta. I would like to be

clarified by an eminent lawyer like Shri Arun Jaitley whether we can make a Central law which will have its overbearing effect on the State, or, whether we can make a model law which the State may accept or may not accept. But, here, I entirely agree with you that Lokayukta or Lokpal will have to be established by the laws made by the Legislature – in case of Centre, by the Parliament; in case of State, by the State Assemblies. If you kindly clarify it, I will be happy.

SHRI ARUN JAITLEY: I think this debate is going to be more candid and upfront than most debates we have had in the Parliament. It is a question which is concerning

us also because here, there is a conflict between two principles which arise. The first is that we need higher standards of probity. But, while trying to achieve that, do we compromise with the federal structure? That is the conflict. How do we reconcile it? And, I must straightaway say that I share this concern with the hon. Finance Minister. Various groups of civil society, including members of team Anna, have met us and had detailed discussions with us. Now, if Lokayukta of the State is going to have some powers in the criminal law, their view is that under List-III, which is the Concurrent List, Entry 1 and 2, these powers may actually be with the Centre. But, then the Lokayukta's powers are not only restricted to that. It may also go across to taking action against the civil servants and employees of the State Government. So, when you deal with employees of the State Government, who makes a law – the Central Legislature or the State Legislature? Therefore, when I put this question to them, they were also concerned with this fact that we don't want to create a law which may tomorrow be struck down as violation of a federal polity in India because under List-II, Entry 41, State Public Services and State Public Service Commission is entirely within the domain of the States. Therefore, any antecedent fact to the State Service, which is action against them, inquiries against them, which the Lokayukta of a State may do, they fall within the domain of the State Legislature. Therefore, one possible option is that you can legislate on areas where the Central Legislature has jurisdiction. Where you find that the Central Legislature has no jurisdiction, you have two options – either you leave that part to the States or under article 252, with the consent of two States, the Central Legislature can bring an enabling law. It will be binding on those two States, and then, every other State, which passes a Resolution accepting it, it will be applicable to those States. It will become a model law which will be applicable to each one of the States. So, it is an enabling law under article 252 which can be really brought in by the Central Legislature. Both options are available to you. Therefore, when you negotiate with various groups in the civil society, with opposition

parties and finally, when Dr. Singhvi's Standing Committee goes into this, I am sure they will have the best of legal advice as to what areas fall within the Central domain and what falls within the State domain so that we are not compromising, in any way, with federalism. But, at the same time, we are able to lay down the highest norms as far as the accountabilities are concerned.

The second question you have raised before the political parties is whether the Prime Minister should be brought within the purview of the Lokpal. Now, we have heard sufficiently both the arguments. The first argument was that India is too large a country. The Prime Minister holds a very sensitive position. The Prime Minister must be kept out of the Lokpal purview because the Prime Minister will be only accountable to the

1.00 P.M.

Parliament and the Parliament is always entitled to remove the Prime Minister. But, there are two drawbacks in this argument. The first drawback is that under ordinary law, both your Prevention of Corruption Act, Indian Penal Code and all other penal laws apply to the Prime Minister as much as they apply to any citizen of India. So, any public servant is bound by them. The Prime Minister is also under the purview of those laws. An ordinary police officer, where a complaint is made, or a CBI officer, today can investigate an offence against the Prime Minister. When you are creating a special procedural mechanism of a Lokpal, you want to suspend the operation of the substantive law, Indian Penal Code or Prevention of Corruption Act, by saying that this procedure will not apply to the Prime Minister.

That probably does not have much merit and the Government's draft, therefore, must be seriously reconsidered. The Government's draft must be seriously reconsidered because when you say that the Prime Minister will be held accountable only after he ceases to be the Prime Minister, then, the crux of your argument will be that if we find that there is a Prime Minister who is guilty of corruption, we must continue to suffer because of him and hold him accountable only when he ceases to occupy his office. Now, I don't think that the world's largest democracy can afford an experimentation of this kind, and, therefore, a more rational approach on which a larger consensus is emerging today is, you hold the Prime Minister within the purview of this law. People have suggested that there is 2001 Bill formulation, which was approved by Shri Pranab Mukherjee as the Chairman of the Standing Committee. There are several functions of the Prime Minister, which should really not be a matter of scrutiny, namely, his functions relating to intelligence, his functions relating to public order, his functions relating to national security. Maybe, tomorrow, you can include his functions relating to foreign policy. Now, I don't have a complete list as to what can be included and what can be excluded. It is for the Standing Committee to really work on it. You can keep some areas out where larger public interest is involved in keeping them out but today it will be very difficult to sustain an argument that the Prime Minister must only be held responsible after he ceases to be the

Prime Minister.

You asked us as to what should be the mechanism for Supreme Court and High Court judges. At the moment, there are two mechanisms for Supreme Court and High Court judges. One is the in-house mechanism, which is a mechanism which has worked in some cases; not worked in some cases, and, the alternative mechanism is impeachment. We have discussed this two weeks ago in the course of proceedings for removal of a Judge of a High Court, where I had mentioned, and, I see that as a popular sense of the House, that there is a need to create a National Judicial Commission both to deal with grievances and complaints and also to deal with matters of appointments.

The Government's approach, which appears from your statement, is that you want a Judicial Accountability Bill. The civil society is saying that if you want it, please strengthen it. Now, whether you call it a National Judicial Commission or the Judicial Accountability Bill, we have to bear in mind one basic principle that the executive must not interfere in the independence of judiciary. But, at the same time, the task of appointing Judges and judging Judges cannot be left to Judges alone, and, therefore, your original Bill, as was introduced in the Parliament by Mr. Moily, the erstwhile Minister, left it to the Judges alone. Therefore, the present system, which is the in-house mechanism, will become a statutory mechanism. It won't improve the situation. So, unless you are able to seriously consider, and, I suggested to my friends in the civil society who had met us, that it is an important institutional reform, which is required. Therefore, this reform may not be possible in four or ten days. If you have a Lokpal Bill and the House shows concern, we must seriously think of a mechanism like the National Judicial Commission itself, and, I must say in all fairness to the flexibility and approach which the members of this group, including the Team Anna, had, on each one of the issues when we shared our concern with them, their response was quite reasonable.

Similarly, on the conduct of Members of Parliament, on the one hand, you need to check graft and corruption, but on the other hand, you cannot interfere with the primary of the House. And, therefore, there is a Constitutional mandate in article 105 that if an MP misconducts within a House, a Member of Parliament is liable for action. After all, have we not removed from Membership the Members who have taken Rs. 5,000/-? We removed eleven Members who took only Rs. 5,000/-. Had it been a case of a Government servant, somebody would have said that it was a very small offence; we could reduce his rank or give him some other punishment rather than throwing him out of his job. Sir, we removed elected representatives for compromising to the extent of Rs. 5,000/-, and, therefore, there is no presumption that the House, when it comes to the probity in relation to the in-house conduct, does not take action.

As far as any impropriety outside the House is concerned, surely, no Member of Parliament can claim any immunity under Article 105. Therefore, the response really would be to a major issue that we include conduct outside the House, as it is included today, and any law we make should be subject to the provisions of Article 105. You said, "What happens to Government servants? Who has a right to take action because of Article 311"? I have put to the members of the civil society who met us and I got an impression that they are agreeable that the powers of the *Lokayukt* or the *Lokpal* could be powers of recommending action. Ultimately, protection of Article 311 is that there is a procedure prescribed by which a person holding a civil post in the Union or the State can be removed. There is a procedure prescribed as to who can do it. Now,

that Constitutional provision cannot be violated by the Lokpal Act. Therefore, the Lokpal Act is necessarily subject to those Constitutional requirements. There is a serious question and I would only urge that a cross-section of opinion should be examined by this ... (Interruptions) ...

श्री रामविलास पासवान : सर, चूंकि हम लोगों को अभी जन-लोकपाल का बिल नहीं मिला है, लेकिन आपने संसद सदस्यों के संबंध में यह बिल्कुल सही कहा कि जो भीतर का मामला हो, उसमें interfere नहीं हो सकता है और जो बाहर का मामला हो, उसमें interfere हो सकता है। इस जन-लोकपाल बिल में अन्ना हजारे जी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अरुण जेटली : मैं इस संबंध में यह स्पष्ट कर दूँ कि जब उन्होंने इसे आरंभ में बनाया था, तो सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों परिस्थितियों में लोकपाल को अधिकार -क्षेत्र दिया था। जब शायद उन्होंने सरकार से बात की और वरिष्ठ के लोगों से भी बात की, तो संविधान की धारा 105 में जो एक सीमा है कि सदन के भीतर जो होता है, उसका नर्णय बाहर की कोई एजेंसी नहीं कर सकती, उसके बारे में हम लोगों ने उनको बतलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो तर्क है, वह कोई अपना नजि वचिर नहीं है, बल्कि वह संविधान के ऊपर आधारित है। मैं केवल यह कहूँगा कि मुझे इस सुझाव पर उनका response काफी उत्साहजनक लगा। ... (व्यवधान) ...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ।

श्री सभापति : नरेश जी, देखिए आपकी जब बारी आएगी, तब आप बोलिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, मैं एक चीज़ यह जानना चाहता हूँ कि इन्हीं दोनों सदनों में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें बहुत -से माननीय सदस्यों से प्रश्न पूछने के संबंध में कुछ लेब -देब की बात हुई थी। तब सदन की कमेटी ने 11 लोगों की मैम्बरशिप समाप्त कर दी थी। ... (व्यवधान) ... फिर यह शंका क्यों पैदा हुई कि एमपीज़ पर बाहर कोई एक्शन नहीं होगा, लोकपाल के अंतर्गत ही होगा ? ... (व्यवधान) ... एक्शन लिया कि नहीं कमेटी ने ? ... (व्यवधान) ...

MR. CHAIRMAN: Nareshji, please.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, we have made the suggestions and we have tried to persuade, because this is not an adversarial issue, that any Lokpal Bill must necessarily be compatible with Constitutional values. Therefore, it can't violate Article 105; it can't violate Article 311. This is the reasoning. I am sure, they are also very mature people, they understand the significance of what we are saying. ...*(Interruptions)*...

Sir, the sixth question which you had raised was: Can quasi-judicial powers be delegated? Now, this is the question which will require a serious examination. I am sure, there are going to be mixed opinions on this because delegation of quasi-judicial and judicial power ordinarily does not take place. But whether it can, in an inquiry process, take place or not; or the power of inquiry can be delegated to the special officers created, this is an area which can be a matter of legislative drafting and which can be worked out.

Sir, you have, towards the end, said that the object of the discussion today is to really address us on three basic questions which are available. I don't think anyone of us should really shy away from responding to those questions because we have a freedom of expression as far as this House is concerned. Our object, while addressing those questions, has to be two-fold - the first has to be that India must get a strong and effective *Lokpal* and the second is that the current political impasse must get over and Shri Anna Hazare should be requested and persuaded to give up his fast. Whether all employees of the Central Government should be covered by *Lokpal* or should be split into two? I think it is a procedural matter. It is not such a major matter that it can break our options to a breaking point. The fact is that all employees and all public servants must be accountable. When we want even the Prime Minister of this country to be accountable, why must we really say that because somebody within the Government is a junior employee should not be accountable? Now what will be that accountability mechanism? You have various options. We have said that please bring them within the *Lokpal*. Some other civil society groups - I got some papers from them - have suggested that if you want a vigilance mechanism, put it under the administrative control of the *Lokpal*. They suggested an alternative mechanism yesterday. Various kinds of flexibilities are available to you. But the overall overarching supervision of the *Lokpal* would remain there with regard to all employees of the Central Government. And we think there is considerable merit in accepting that suggestion.

As far as the option of Lokayukta institution in the States is concerned, I have already said that if you find that some areas are not within the domain of the Central Legislature, you can have an enabling law and leave the option with the States.

The last question is: Do we need a grievance redressal mechanism? Sir, we certainly do need a grievance redressal mechanism. आम आदमी की शिकायत होती है कि मैंने राशन कार्ड की दरखास्त दी, लेकिन मुझे 6 महीने के बाद भी राशन कार्ड नहीं मिला। मैं ट्रांसपोर्ट डफ़्टमेंट जाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है।

अब कई राज्यों ने, जैसे मध्य प्रदेश है, बहिर है, अपने यहां कानून बनाए हैं। उस दबि सतीश जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश ने यह व्यवस्था शुरू की है, पंजाब ने शुरू की है। महोदय, कई राज्यों ने अपने यहां सटिजंस चार्टर और आम आदमी की grievances से नष्टिने के लिए कानून बनाने आरंभ कर दए हैं और अगर कोई अधिकारी उस चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसे कसि प्रकार की पेनल्टी लगेगी यह भी उस कानून में लखि हुआ है। मैं मानता हूं कि एक के बाद एक राज्य इस प्रकार का कानून बना रहे हैं, इसलिए अगर केन्द्र भी इस बारे में सोचे तो यह प्रशासन की दृष्टि से अच्छा कदम होगा। It will be a good step to say that every department of the Government has a charter. This is how grievances of the citizens are to be addressed. If somebody applies for a ration card or a licence or some other permission, 15-30 days should be the period under which it should be disposed of. And if somebody does not dispose of his application within that period, then he will be taken to task for

it. It will improve the quality of administration and governance. There is no reason why it can become a politically adversarial group amongst any one of us or between us and the members of the civil society who are suggesting it. It is a step towards good governance and we must really come out with a procedure which is fair and which appears to be effective.

Sir, there are many other small issues which have been raised. The Government in principle has accepted it. In fact, Shrimati Jayanthi Natarajan headed the Standing Committee which had recommended whistleblower's protection. They want whistleblowers to be given protection under the Lokayukta or the Lokpal. I don't think in principle there can be any difficulty as far as this factor is concerned. There is a grievance that punishment to complainants is very harsh. अगर उन के खिलाफ कोई आदमी शिकायत दाखलता है और वह अधिकारी भ्रष्ट साबित होता है तो उस को सजा हो जाती है, लेकिन उस अधिकारी की सजा कम है और अगर complaint गलत नकिलती है तो उस आदमी की सजा ज्यादा है। यह बात तो उन की जायज है। मुझे लगता है कि इस कानून को बनाने में कहीं-कहीं कोई oversight हुई है जसि के बारे में हम सब को दोबारा सोचना चाहिए।

There is one subject where I want to sound a little discordant note. We are creating an institution where we say that the Prime Minister should be included in it, every Chief Minister should be there, and every Minister should be there. And MPs, Secretaries of the Government of India, and the Cabinet Secretary would be covered by this law. There is a suggestion that the authority will be entitled to tap phones of these people if it receives a complaint. I think in the last few years, we have been making a mockery out of our democracy by really making phone-tapping in this country to be virtuous. How can somebody tap the Prime Minister's phone? The argument is that it is being tapped because there may be an evidence of bribery. Well, there are thousands of conversations which Ministers or the Home Minister or the Finance Minister or a Chief Minister may be having with the Prime Minister. He may be discussing something with the Secretary, RAW. He may be discussing something with the Director, IB. He may be

discussing something with regard to other serious matters with the Army Chief or the Foreign Secretary. Are we going to create institutions which are now entitled to start tapping phones of even the Prime Minister, Ministers and other senior functionaries? We have a judgment of the Supreme Court which is a very well considered judgment. We have provisions in the Indian Telegraph Act that only to the extent it involves national security or it involves prevention of commission of some serious offence, you can do it. I think this power should be exercised with great caution because in the process of creating an anti-graft institution, we should not compromise with any tenets of Indian democracy which allows institutions to start interfering to this effect. When members of the civil society met us, I conveyed to them that this is one area where I would beg to disagree

with them even while supporting them on most other areas that they have said and they must seriously reconsider a proposal where an authority which covers the Prime Minister and other senior functionaries of the State is not entitled to start bugging their telephones. We can't make a virtue out of this and this is one area where I am sure the drafting committee will make a serious issue.

Finally, Sir, I have two points. You have asked us on these three specific questions in order to resolve the impasse. I think, there is considerable merit in including the entire bureaucracy. There is considerable merit in either enabling or otherwise, subject to the legal advice you get, going ahead with establishment of Lokayukta in the States. And there is also considerable merit – in fact, there is far greater merit – in having a grievance charter or a mechanism as far as the country is concerned.

Finally, Sir, one great strength of Indian democracy is that we have protests, we have crisis, we have confrontations, but then, we also have a great sense of resilience. We show an extraordinary amount of maturity in resolving every crisis and emerging stronger out of any crisis. I am sure that today would be a very important day for us when we show and display that sense of resilience and are able to resolve these issues which are confronting us. Thank you very much.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI ASHWANI KUMAR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for affording me an opportunity to participate in a debate which by all accounts is indeed historical.

Sir, the day is historic because it is a significant step in the processes of our democracy that enables us to turn back from a situation of confrontation. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Mr. Ashwani Kumar, could you please yield? Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister is yielding. I am making a request. We have agreed for a six-hour debate which is extendable. Now, that may go on to eight or nine hours and we will be sitting here. This is a very important issue on which, in my opinion, Members would be present. There are many medical reasons and other reasons

where Members would like to have something to eat. So, please have a break for just half-an-hour for lunch so that people will not get disrupted. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Is there an agreement on this?

SHRI S.S. AHLUWALIA: Up to 2 p.m.

MR. CHAIRMAN: After Mr. Ashwani Kumar has spoken.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, we can meet at 2 o'clock.
...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: He has started his speech. Let him finish.
...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: We can meet at 2 o'clock when he will continue his speech. ...(Interruptions)...

श्री रामविलास पासवान : सर, इनको बोलने दीजिए , उसके बाद आधे घंटे के लिए एडजर्न कर सकते हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : वे कम से कम आधा घंटा बोलेंगे।

श्री सभापति : वे ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मेरा कहना है कि लंच के बाद वे कॉन्टीन्यू करें , क्योंकि वे आधा घंटा या चालीस मिनट बोलेंगे।

श्री सभापति : वे स्टार्ट कर चुके हैं।

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I am going to take twenty minutes.

MR. CHAIRMAN: Okay, this is a fine compromise. He is asking for 20 minutes. That should be all right.

SHRI ASHWANI KUMAR: Thank you, Mr. Chairman, Sir. I started by saying that this is indeed a historic day for more reasons than one. It is historic because the highest forum of India's democracy recognises a huge national resonance and the Government sharing that resonance on the issue of corruption has decided to take this important step to debate complex issues of Constitution, complex issues of a legal architecture that will create an Ombudsman and the complex processes of democracy in action. Sir, this is also historic because we are eventually going to be testing the endurance of our Constitutional law.

Sir, I wish to raise the level of this debate beyond the nuts and bolts of legality. I will comment on those but, I think, the overarching structure of my intervention today is going to be whether the resilience of our democracy is subserved by this debate, whether the supremacy of the parliamentary institutions in the matter of law

making is reestablished and reinforced and whether our Constitution and our system of governance recognizes competing diverse values of the Constitution all of which must be harmonized, preserved and protected. It is a debate which will at times tilt on the windmills in favour of one Constitution imperative and sometimes in favour of another.

The genius of this House today is to find that middle ground where we will protect the first principles of our Republic, as indeed we are duty bound in this House today and also to determine that our law making and our parliamentary processes are not seen to be at variance

with the national conscience on the issue of corruption. That, Sir, is really the contour of the debate we have before us. Sir, at another level this debate is about the manner in which we go about law making. In the land of the Mahatma, we cannot reduce ourselves to irrelevance, the legitimacy of the means.

The end objective of fighting corruption is shared by each one of us in common. There is never a debate about the need to have an effective institution to combat and control corruption. The issue, Sir, is what are the processes that we adopt? Will those processes become precedents for the future? If so, will these be healthy precedents? Will the edifice of our Constitutional morality be subserved and secured by what we do in this House today? That, Sir, is the umbrella in which this debate has to take place.

I am grateful to the Leader of the Opposition who has tried to raise larger issues in a spirit that is merited where the issues which arise in these debates are concerned.

Sir, as students of law, we were told that the first principle of the Constitution is that Constitutions are established to be bulwark against the impulses of transient majorities. This principle has been repeatedly affirmed by the highest court of this country. First, in the Kesavanand Bharati case and thereafter in a number of cases, where, they say that certain features of the Constitution owe no apologies to the transient impulses of the momentary majorities. In elections Governments are voted to power; Governments are voted out of power. But certain fundamental principles of a nation which are so sacrosanct, which are so non-negotiable have consciously, deliberately, advisedly and in my respectful submission rightly placed outside the purview of legislature power lest the legislation is construed as a negation of the fundamental principles of the Republic.

Sir, parliamentary democracy today stands embedded as an integral component of the basic structure of the Constitution. Nobody disputes that the ultimate sovereignty of the people of India is something that vests with them and in their hands which they exercise after every five years, as Winston Churchill said, by using a small pencil and

marking a tick on a ballot paper. That is how this sovereignty of the people of India, the true custodians of the conscience of this country is exercised in a system that we the people of India have given unto ourselves.

But this power, the unbroken power of the people, under the Constitution, has been diffused and broken into three wings of Government – the Legislature, the Executive and the Judiciary. Each wing performs its functions. So far, in 67 years, we may not have had a perfect system of governance, and there can be fallibility; we could have made mistakes; much more needs to be done, and that is why we are debating the contours of the new Anti-Corruption Law. But, on the whole, Sir, this system has served the country well. That is why I am delighted,

I am gratified and my head bows to the collective wisdom of this House that if there is one issue on which there is complete unanimity, that issue is that lawmaking is the domain and the exclusive domain of both the Houses of Parliament and that law-making cannot be effectuated under a banyan tree or a peepal tree, by scores of people sitting under it. The day we allow ourselves to regress into that kind of coercive legislation, that, Sir, would be the death knell of all that we have nurtured to create and to consolidate us further.

Sir, I do wish to make a point which I feel very strongly about it. I have never, for a moment, doubted the innate wisdom of the people of India. But we also know, Sir, that emotions do sometimes, get the better of our judgment and that is true for the best amongst us and that is why, Sir, as someone very, very learned and very knowledgeable in this area, -and I know that the Vice-President and Chairman would have read this many, many times, W.G. Summers, said. Talking about the need to balance absolutes and the need to move away from extremes and because democracy is a song of moderation; it shuns extremes and because it is not the peak but a plateau that is *dessideratum* of democratic discourse, he some people tend to convert their beliefs, and strongly-held beliefs, into doctrines which they say are immutable. And my difficulty with the discourse that is going outside the Parliament is that one set of people howsoever, lofty may be their ideals. Believe that what they believe should be the nature and contour of the law and this is almost a doctrine that admits of no compromise. W.G. Summers, writing, in 1962, in a very famous treatise on "Modern Government", said, "Doctrines are the most frightful tyrants to which men ever are subject because doctrines get inside of man's own reason and betray him against himself." This, Sir, is the overarching theme of my intervention. I ask this House, Sir, to consider the proposals made in all the Bills, and I have no doubt in unhesitatingly admitting that all the people who are going to speak here in this House today, and all the people who have brought forward their versions of the Bill in the form of the proposed Bills, articles and views openly expressed, are certainly actuated by the highest and most lofty ideals of fighting corruption. But where do we draw the balance? Where do we draw the line? After so many months and weeks of

a very agonizing public debate that threatens the very basis on which our system of governance is founded, we have been able, Sir, to identify, as has been done in the Statement of the hon. Finance Minister, five or six areas of divergence and, Sir, these are very narrow areas, but are complex areas. As the Leader of the Opposition, in his characteristic and moderative speech has laid the foundation of further negotiations and consideration of the various aspects with a view to finding a common ground, I would like, Sir, to very briefly share my perceptions on these five-six areas of divergence. And, Sir, when I give my views, I must say that these are my personal views; my Government may have a view which might be slightly different, but I am sharing this perception, and I do hope.....

SHRI S.S. AHLUWALIA: As a Minister.

SHRI ASHWANI KUMAR: No. I am speaking in various capacities, as a Member of this House, Sir. I, therefore, say that as far as point No.1, "Should one single Act be provided for both the Lokpal at the Centre and the Lokayukta in the State?", is concerned, the answer came from the Leader of the Opposition himself. He showed Article 242. These are mechanisms. But the fact of the matter is: Are we, today, going to be seen, if not actually doing, to be doing something which the States that are integral components of our federal structure may find fault with? Can this House be privy to a legislation which, at the worst, has many shades of grey? Can a law on the issue of corruption be faulted by the Supreme Court of India on the touchstone of the integrality of the federal structure? The federal structure has also been determined by the Supreme Court to be part of the basic structure of the Constitution and completely inalienable. No attempt, therefore, must be made, with most lofty ideals in mind, which would raise doubts about our intentions, as far as the integrity of our federal system is concerned. There is no doubt that we need a Lokpal for Central Government employees and we need a Lokayukta in the States.

The question is: Who will make the law? I would humbly submit, Sir, let us not, in our desire to hasten through this legislation, ignore the extremely delicate and complex possible questions on constitutional law. It is not, by any means, clear that this House can, indeed, legislate with respect to the employees of the State Government.

The second question is about the Prime Minister being within the ambit of the Lokpal. Sir, we all know that the Prime Minister is *primus inter pares*; he is not only first among equals, but also, in fact, the key-stone of the Cabinet arch. When Dicey wrote his treatise on modern Government, he said, the Prime Minister is the key-stone of the Cabinet arch. Do we subject PM to vexatious, frivolous and *mala fide* inquiries, investigations and litigations at a time when he might be in the conduct of exercising international treaty making powers or

when he might be in the middle of waging war to defend our borders or, as anyone here would see, the Prime Ministerial office is an office that is at the centre of everything that is required to be done to sustain the unity and integrity and inviolability of our Government? Therefore, in the face of the fact that we have mechanisms where Prime Ministers have been prosecuted, where officers serving under the Prime Minister's Office, maybe, the CBI, in turn, have gone and prosecuted them, I would only hasten to add, please reflect on what we should do with reference to his office. The suggestion that, perhaps, the Prime Minister could be excluded while he is Prime Minister but included when he is not, does not appeal to me at all. You can't keep the Damocles' sword hanging on the Prime Minister's head for acts done in his capacity as Prime Minister but to

be investigated later when he ceases to be the Prime Minister. He will be disabled in his defence and this is applicable to all Prime Ministers. Our Prime Minister has gone from pillar to post saying that he would like the Office of the Prime Minister to be under the Lokpal Bill. So, there is difference, as far as Government is concerned, on this issue. But I am raising a point that when we say that you can have the Prime Minister under the Lokpal after he demits office, it does not really advance the argument of the case. You might either have him entirely under the Lokpal. Why do we make this exclusion? That is something for your consideration in House. Since we are not making a law here, it is an issue on which there is a very strong view on either side of the aisle and, I think, these considerations need to be kept in mind.

Sir, as far as the conduct of the Members of Parliament is concerned, it is well known that we have a very effective mechanism under the Constitution which has proved to be effective. In a way, I am privy to the fact that we did expel eleven of our Members for taking Rs. 5,000 or Rs. 11,000. It is recognition; it is an expression of the sensitivity of the representatives of the people sitting in this House that they would not condone the slightest infraction of the principles of public probity and morality that they took the most harsh action against their own brethren. Therefore, Sir, we have a sufficiently adequate, a sufficiently effective constitutional mechanism in place. I don't think we should have a contrarian or a supplementary legislative framework in the Lokpal Bill on this issue.

Sir, articles 311 and 320 (3) of the Constitution relate to the Central Government employees. We have 37 lakh Central Government employees. It could be even more. My figures are 37 lakh. Do we imagine; can we imagine an alternate system over and above and in addition to the system in place, to police and discipline, by way of disciplinary inquiries and punishment and so on and so forth, these many people? Whose case is it, Sir, that there should be no protection to any civil servant? After all, we know that wild allegations can also be made against civil servants. They must have protection.

Article 311 does nothing but give them that elementary sense of protection. One can always believe that one's suggestion is better than what has held sway till now. Your view is as good as mine. I venture only to add that we need very seriously to ponder whether this Lokpal Bill, as proposed in the Jan Lokpal mechanism, can effectively achieve the purpose for which the suggestion is made. I have grave doubt as a lawyer, as a citizen, as a Parliamentarian, as someone who has been in the Government for a while. I have grave doubts as to the functionality, the efficacy and the purpose of bringing almost everyone under this regime irrespective of the constitutional mandate in articles 311 and 320 (3) and this provision in Bill is, doubtless, going to be challenged in the court as an infraction of a

constitutional safeguard. I can tell you, Sir, one will not be surprised if the Supreme Court were to say, well, this is clearly a transgression on the Constitution and by legislation you cannot transgress the Constitution.

Sir, I need to make this point. The reason is that we must understand the limits of our own jurisdiction. Parliament is supreme, no doubt, in law making. But it is subject to the fetters of the basic structure doctrine imposed by the court on the law-making power. The Parliament, Sir, when I say, reflects the broken sovereign power of the people of India in the exercise of law making function, is premised on the basis that this power is circumscribed by the parameters of the Constitution. The creature of the Constitution, and this is a jurisprudential dictum, cannot so exercise this power as to negate the basis of its creator. This principle alone must caution us against legislation rushed through in haste or under the pressure of people outside the Houses of Parliament.

The fourth point has been made. As far as the exercise of quasi-judicial powers and the delegation thereof to subordinate officers is concerned, is against the elementary principles of law that quasi-judicial powers such as the one you exercised when you impeached Justice Sen, cannot be delegated. The reason you don't have a whip on these issues is that these are quasi-judicial powers and everyone has to apply one's mind. Therefore, how can a Lokpal, exercising quasi-judicial functions have the authority to delegate his powers to administrative subordinates? On first principles, this is clearly against the constitutional scheme. Sir, I have two more points to make and then I will conclude.

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र): मेरा केवल एक ही मुद्दा है कि ये आपके नज़ी वय़ार हैं या आपकी पार्टी के वय़ार हैं ?... (व्यवधान)...

श्री अश्विनी कुमार : आप इसको जैसे मर्जी interpret कर लीज़िए।

श्री सुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): फ़रि अन्ना जी का अनशन तो टूटेगा नहीं ... (व्यवधान)...

श्री राजनीति प्रसाद : सभापति जी... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : राजनीति प्रसाद जी, बैठ जाइए ... (व्यवधान) ...

SHRI ASHWANI KUMAR: I have said nothing contrary to what has been said. I have a submission to make on the two Bills; we have the Jan Lokpal Bill and the official version. An argument was made by the Leader of the Opposition that when the junior-most employees of the Government can be brought under the purview of the Lokpal Bill, why is it that the high constitutional functionaries, including the Prime Minister, cannot be brought under the Lokpal Bill. It can be so. That is the proposal of the Government's Bill. But please ponder, because today that is a proposal; there is no finality to the structure of the law. After the sense of the

House is established, after deliberations in the House, these deliberations and summaries will go to the Standing Committee, which will exercise its constitutional functions, will apply its mind and then the matter will again come to the House, when we can finalise it. I am putting a query for the consideration of the distinguished Members of Parliament. The only difficulty that one has is, you kindly look at clause 8 of the Jan Lokpal Bill and the structure, functions and powers of the Lokpal. It has 14 or 15 paras. And it says, "Lokpal shall be deemed to be a disciplinary authority or an appointing authority for the purpose of imposing penalties under the CCS (Conduct) Rules." How can you be an appointing authority under the Constitution, and, say that somebody else is the appointing authority? How do you become a disciplinary authority if the mandate of Article 311 cannot be abrogated? Further, it says, Section 197 of the Criminal Procedure Code, that is, the obligation to obtain sanction for prosecution, shall be deemed to have never existed or deemed to have been granted automatically to the Lokpal institutions. I know the argument against the prior requirement of sanction. But the Supreme Court has already given protection against the abuse of powers and refusal of sanction. If we have those principles in mind, I don't think we need to flounder or tinker with the integrity of the established structures that we have, even while they have subserved the objectives for which they were intended. So, that is the difficulty. You cannot take a provision out of the Jan Lokpal Bill in isolation and ask, What is wrong with it? You cannot also consider the official draft of the Lokpal Bill and ask, What is wrong with it? Of course, these are two proposals at this point of time before the House. The finality is yet to be arrived at, and I have no doubt that considering the wisdom of this House we shall be able to do it. We cannot really erect our own prejudices into legal principles, or, even our own preferences, howsoever laudable they may be, into legal principles. Legal principles and constitutionalism are intended to survive for centuries and to guide succeeding generations. It is not as if today one Government is in power and it can tinker with the

Constitution, and tomorrow, another Government comes and it can tinker with the Constitution. That is not the intention. That has never been the case.

Sir, the questions, that are important, have been answered. I must say that because my theme is the Constitution, - that is the theme which, I think, each Member in this House shall have - the Constitution, unlike the law, unlike the statute, is not only a legal document; it is also a mode of life, the way of life. It embodies the relationship of free citizens in a free State for the fulfillment of their fundamental needs. And if this be our conception and understanding of the time-tested Constitution, I appeal to this House, by all means, have a strong and effective Lokpal. We must have it. We have said so from every forum. And I repeat here, on behalf of my

party, my Government and myself, that we have to have an effective Lokpal Bill. But let it not be said by posterity that we rushed into law making without applying our conscious mind to every single aspect; which must fairly receive our attention.

To conclude, I must say that I am distressed about what I saw was going on at Ramlila Maidan. Anna Hazareji is a crusader in the cause of corruption, which all of us share. It is a national cause. It is not one individual's cause. But the kind of guidance which he has received is a matter on which we must ponder.

Lastly, about judges, there is a constitutional mechanism in place.

The Judicial Accountability Bill must come forward. We need an effective mechanism to correct aberrations in the Judiciary. Judiciary cannot claim itself to be the custodian of all wisdom, of all morality. I do not subscribe to that view at all and the Judges, despite the constitutional function that they exercise, must be amenable to some mechanism which is fair, transparent and objective.

Sir, I would conclude by saying,

“कुछ अनदेखी मझधारें थीं, कुछ माझी थे अन्जान बहुत,
कुछ अनपरखी पतवारें थीं” – advisers of Hazare –
“नदिया तो वही है, नाब वही, अब तुम ही कहो क्या करना है,
अब कैसे पार उतरना है।”

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned for 45 minutes to meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at forty-five minutes past one of the clock.

The House re-assembled, after lunch, at thirty minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री उपसभापति : श्री सतीश चन्द्र मश्री।

श्री सतीश चन्द्र मश्री (उत्तर प्रदेश) : मामनीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है। ... (व्यवधान) ...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, हमारे नेता बोल रहे हैं और अभी कोई कैबिनेट मन्निस्टर बैठे नहीं हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : बैठे हुए हैं। ... (व्यवधान) ...

कार्मिक, लोक शकियत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं यहाँ बैठा हूँ ... (व्यवधान) ...

श्री सतीश चन्द्र मश्रा : वे बैठे हैं ... (व्यवधान) ...

श्री वी. नारायणसामी : मैं यहाँ बैठा हूँ ... (व्यवधान) ...
आप इधर देखते ही नहीं हैं ... (व्यवधान) ...

श्री सतीश चन्द्र मन्त्रि : उपसभापति महोदय , सबसे पहले तो मैंने जो बात आज पहले भी कही और कल हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष , माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी कही है कि जहाँ तक भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम है , तो उस मुहिम में बहुजन समाज पार्टी हमेशा साथ है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए , यह बहुजन समाज पार्टी का सोचना है। इस दशा में जो भी कार्य आगे बढ़ेगा , उसमें हमारी पार्टी हमेशा साथ रहेगी। लेकिन , इसके साथ-साथ बहुत से महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं , जो खास तौर से आजकी इस डिस्कशन से नकिले हैं। एक यह है कि इसको खत्म करने के लिए जो कानून बनेगा , तो एक केन्द्र में बनना है और एक प्रदेश में बनना है। आज जो जन लोकपाल की बात हो रही है , जो लोकपाल की बात हो रही है , वह केन्द्र में बनाने की बात हो रही है , क्योंकि जहाँ तक स्टेट की बात है , तो वहाँ पर लोकायुक्त है। अगर हम उत्तर प्रदेश वगैरह को लें तो वहाँ पर लोकायुक्त पहले से है। लोकायुक्त सफ़ि नहीं है , बल्कि लोकायुक्त के effective provisions भी हैं। उसका नतीजा हम सब लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने जो रिपोर्ट्स दीं , अपनी सलाह दीं , उनके तहत अभी हास ही में एक कैबिनेट मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया और इसके पहले भी एक ने दिया। इस तरह , जहाँ तक लोकायुक्त का प्रश्न है , वह हमारे यहाँ स्टेट में already है और हम लोगों का यह मानना है कि यह हर स्टेट में होना चाहिए। गुजरात में यह क्यों नहीं है , यह समझ में नहीं आया , लेकिन हर स्टेट में यह होना चाहिए।

सर, इसके साथ-साथ जब हम लोग लोकपाल बिल की बात करते हैं , जसि पर आज चर्चा है , लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल पर , और जसिके लिए आज यह पूरा सदन बैठा हुआ है , तो इसमें हम लोगों का मत यह है कि हम लोग संविधान , जसि संविधान की रचना डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने की , इस संविधान की रचना वर्षों बैठ कर की गई , इसके लिए कमेटी बैठी , उसमें एक-एक क्लॉज पर डिस्कशन हुआ , उसके बाद एक नर्षिय आया और तब संविधान की रचना की गई , उस संविधान के जो basic principles हैं , उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम इस तरह की व्यवस्था नहीं बना सकते कि constitution में जो provisions हैं , उनको दरकिनार करके हम ऐसे provisions बना दें जो कि ultra vires of the constitution हों और जसिका असर यह हो

कि वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाए। अगर हम इस बिल को देखें , यह बिल जो बना है , इस बिल में , चाहे हम सरकारी बिल देखें या जन लोकपाल बिल देखें , जन लोकपाल बिल के बारे में आज हमारे Leader of the Opposition ने कई बातें ऐसी रखी , जिन पर मैं बाद में आऊंगा , लेकिन जन लोकपाल बिल के कई versions हैं। हमने परसों कंप्यूटर से इंटरनेट से जो नक़िला है , वह जन लोकपाल बिल version 1.8 है। जन लोकपाल बिल का यह version हमें परसों इंटरनेट से प्राप्त हुआ था। इसके पहले 1.7 तक के और भी कई versions होंगे। ... (प्रवधान) ... आप कह रहे हैं कि अब इसका version 2.1 भी आ गया है , लेकिन हमारे पास इसका version 1.8 है , जो परसों नक़िला गया है। सर, आज जो बिल बन रहा है , वह चाहे स्टेट का हो या सरकार का हो या जन लोकपाल बिल हो , इसमें यह देखने को मिल रहा है , एक ऐसा प्रवधान बनाया जा रहा है कि उसे कई powers दी जा रही हैं और इनमें से कुछ पॉवर्स ऐसी हैं , जो बड़े एक्शन लेने के लिए हैं। हम लोग फ़िर से यह देख रहे हैं कि लोकपाल का constitution बनाया जा रहा है उसमें प्रवधान है कि लोकपाल में कौन-से लोग रहेंगे और उनकी क्या qualifications होंगी ? लेकिन उसमें यह कहीं पर भी नहीं रखा गया कि scheduled caste, scheduled tribe, backward class और minorities को इसमें रखा जाए। इसमें ऐसा प्रवधान होना चाहिए , जिसके अंतर्गत इसमें इनको भी रखना अनिवार्य हो क्योंकि अगर

अनिवार्य नहीं होगा, तब यह discretion होगा जहां पर अनिवार्यता रही है, वहां पर भी इन वर्गों के साथ में हमेशा से धोखा होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है और जब अनिवार्यता नहीं होगी, तब तो यह मामला लेना चाहिए कि ऐसे में तो इनको किसी भी तरीके से इसमें नहीं डाला जाएगा। जब इनको नहीं डाला जाएगा, तो उनका हस्ति कैसे सुरक्षित होगा? उनका हस्ति सुरक्षित नहीं रह सकता। हम लोग यह बात कोई हवा में नहीं कह रहे हैं। हम लोग यह देख रहे हैं और हर स्तर पर देख रहे हैं। अभी तक employment में reservation है। आप reservation खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है, लेकिन इसको खत्म करने का दूसरा तरीका निकाल लिया गया। आज जतिने भी पब्लिक सैक्टर कॉर्पोरेशन्स हैं, जतिने PSUs हैं, जतिने नगर निगम हैं या जतिनी नगर पालिका हैं, उनमें आजकी तारीख में अगर देखें, तो धीरे-धीरे या तो वे uprivatise हो गए हैं या जहां पर इनको employment मल्लिता था और जहां पर reservation compulsory follow करना पड़ता था, उसको avoid करने के लिये यह तरीका निकाला गया कि उसमें प्रइवेट आदमियों से काम करा लिया जाए या contract पर काम करा लिया जाए। जब contract पर काम करा या जाता है, तो उसमें reservation की कोई बात ही नहीं रहती है, Contractor ने जिसको लगा दिया, उसी से काम ले लिया।

यह बात दूसरी है कि उत्तर प्रदेश में इसको बाध्य किया गया। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें यह बाध्यता की गई है कि चाहे contracts हों या contract appointment हों, उनमें भी यह insure करना पड़ेगा कि reservation हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन, देश में तो यह नहीं हो रहा है, और प्रदेशों में नहीं हो रहा है। इस तरीके से जहां-जहां भी नर्णिय लेने की बात है, जहां-जहां भी उच्च स्तर पर कोई नर्णिय लेने की बात होती है, वहां धीरे-धीरे इन लोगों को हटाने का काम चल रहा है।

मैंने पछिली बार भी इस बात को कहा था कि जुडिशरी भी ले लें, जिसके अंतर्गत हायर जुडिशरी, highest जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट है। हमने आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण भी दिया था कि जहां 160 Honorable Judges की vacancy है, उनमें एक भी scheduled caste का व्यक्ति उनको नहीं मल्लि और आज एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं है, तो इन वर्गों का ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में जो भी बैठते हैं, हम लोग यह मानते हैं कि वे सबको

एक समान देखेंगे , लेकिन आप जहां पर नर्णय लेने की शक्ति दे रहे हैं और किसी को नर्णय लेने के लिए बैठा रहे हैं , तो यह अनिवार्य होना चाहिए कि आप उन लोगों का भी ध्यान रखें। जब मैंने इस बारे में पूछा कि इसमें इनका appointment क्यों नहीं हुआ , तो कहा गया कि circular issue है। Circular है कि इनका भी ध्यान रखिए। केन्द्र सरकार से पूछा गया कि आखिर आप लोग क्यों नहीं बाध्य करते हैं , तो उन्होंने कहा कि यह circular है , इसके तहत उनको भेजना चाहिए। उच्च न्यायालय में जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि circular बाध्यकारी नहीं होता है। हमें तो उसको देख कर जैसा समझ में आता है , वैसा भेजते हैं। Lower Judiciary से जो प्रमोट होकर आते हैं , उसमें भी ये लोग नहीं हैं। इस तरीके से हम लोकपाल जैसी संस्था बनाने जा रहे हैं , जिसमें जन लोकपाल बलि के मुताबिक 20 से ऊपर सदस्य होंगे। इसमें अगर हम यह condition नहीं डालते हैं कि आप इसमें reservation रखिए या कम से कम इसमें यह तो लिखिए कि इस-इस category के लोग इसमें होंगे तब तक इनको इसमें नहीं रखा जाएगा। चूंकि यह बात इसमें नहीं है , इसलिए यह अफसोस की बात है। मैंने पछिली बार भी यह बात कही थी और अब फरि दोबारा इस बात को रफ़ीट कर रहा हूँ। कि इसको लाना बहुत जरूरी है। वरना , धीरे -धीरे जैसे कि employment से आपने Privatisation करके Reservation आपने हटा दिया है आखिर आप इन लोगों को कहां ले जाएंगे ?

यह सबको मासूम है कि इस देश में अगर कोई सबसे गरीब है, तो इसी category में से है, Scheduled Caste और Scheduled Tribes है। फरि आगे चल कर जब आप उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और इस पर अगर वे weapon उठा लेते हैं, तो आप कहते हैं कि ये लोग नक्सलाइट हो गए और आप उनके ऊपर दूसरे तरीके से दमन करते हैं। लेकिन, अगर तब आप इस तरीके से इनको कबिरे करते जाएंगे, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? वे कहाँ जाएंगे? चाहे नौकरी हो, चाहे बजिनेस हो, आप उनको हर जगह से अलग करते हैं। यह बात दूसरी है कि उत्तर प्रदेश में जब इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो यह condition जोड़ी गयी कि 20 लाख पुष्प तक के contracts scheduled caste की category के लोगों को ही दिये जाएंगे। इस पर हाई कोर्ट में challenge हुआ और उच्च न्यायालय ने उसको uphold किया, लेकिन आज इस तरीके से उत्तर प्रदेश में Scheduled Caste काफ़ी लोग, एक-दो नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में employment में आए। लेकिन, केन्द्र सरकार क्या कर रही है? इस बारे में कुछ करने के बजाए वह हर तरीका निकालने की कोशिश हो रही है कि इनको किसी तरीके से दबाया जाए। अब ऐसा कामून बना दीजिए, जिससे कि संबिधान ही कबिरे हो जाए।

अब अगर हम जन-लोकपाल बलि, जसि पर आजयहाँ चर्चा रखी गयी है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें हम लोग आजयहाँ accept कर लें, जैसा कि बाहर कहा जा रहा है कि हम पार्लियामेंट से यह उम्मीद करते हैं कि रात के 12 बजे तक बैठें या जितने बजे तक बैठें, ये जो हमारा जन-लोकपाल बलि है, इस पर आप मुहर लगा कर भेज दीजिए। हम लोग अन्ना हजारे जी की बहुत इज्जत करते हैं। हम लोग उनकी इस मुहिम को भी appreciate करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार की बात उठायी, जिसकी वजह से आजकेन्द्र सरकार इस बात के लिए बाध्य हो रही है कि हम लोकपाल बलि लाएँ, लेकिन उसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि तरीका क्या होना चाहिए। अगर हम वह तरीका अपनाते हैं जो constitution से हट कर है, तो वह कोर्ट में ultra vires तो डिक्लेयर होगा ही, साथ ही यह मैसेज भी जाएगा कि अगर constitution से हट कर इस तरह की बात उठती है तो भी हम कामून बना सकते हैं।

हमारे सामने जो जन-लोकपाल बलि का version है, इसमें जो बातें इन्होंने कही हैं, उनके अनुसार इसमें मैम्बर्स ऑफ

पार्लियामेंट , हाई कोर्ट जजेज और सुप्रीम कोर्ट जजेज को
 इन्क्लूड किया गया है। हम यह नहीं कहते कि जुडिशरी की
 accountability नहीं होनी चाहिए। उसकी accountability होनी
 चाहिए। आजके वातावरण में तो जुडिशरी की accountability बहुत
 ही जरूरी है और उसके लिए एक effective method और mode होना चाहिए ,
 लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जन-लोकपाल बिल में जो
 प्रोविजंस डाले गये हैं , अगर हम उनके तहत जुडिशरी को ले आते
 हैं , तो यह बिल्कुल ही ऐसा प्रो वजिन बन जाएगा , जिसमें शायद
 जुडिशरी ही ठप हो जाएगी। क्योंकि आपने उनको पाबर्स दी है और
 कहा है कि हम हर उस एक्शन के खिलाफ कम्प्लेंट ला सकते हैं और
 यह cognizable complaint हो जाएगी चाहे अगर आपने नर्षिय देने में
 देरी कर दी। इसमें जूडिशियल प्रोसिडिंग के संबंध में लखि
 है कि अगर complainant को यह लग रहा है कि malafides हैं , तो
 complaint हो सकती है। इस तरह की complaints होने के बाद
 कार्रवाई क्या होगी ? उनके खिलाफ लोकपाल को search, seizure और
 arrest warrant की भी पावर है। इसके साथ ही , transfer और
 suspension की पावर भी है। Transfer and suspension में एक ही जगह
 exemption दी गयी है। वह exemption जुडिशरी को नहीं दी गयी है ,
 उसका तो transfer भी कर सकते हैं और suspension भी कर सकते हैं।
 जन-लोकपाल बिल में केवल प्राइम मनिस्टर साहब के ऊपर एक लाइन
 लखि कर कृपा की गयी है

कि suspension और transfer वाला प्रोविजन उनके ऊपर apply नहीं करेंगे। यह इसमें लिखा हुआ है कि transfer और suspension के संबंध में इनके ऊपर हम रियायत दे रहे हैं। इसमें search and seizure की पावर दी गयी है। इसमें contempt of court की वही पावर दी गयी है, जो उच्च न्यायालय के पास है। अगर जुद्धिरी के किसी व्यक्ति ने इनके हस्ताक्षर से जजमेंट में डलि कर दी या इनको लगता है कि mala fide है अथवा यह लगता है कि उनकी सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है, तो इस प्रोविजन के तहत complaint होगी और complaint होने के बाद, suspension and transfer तो है ही, अगर उनको यह लगता है कि बुलाने के बाद वे ठीक से behave नहीं कर रहे हैं, तो contempt की भी बात है। Contempt की पावर में पूरी सजा दे सकते हैं, जो उसमें देखी हो। Finally, अगर वे यह पा लेते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है और complaint prove हो जाती है, तो दस साल और उससे ज्यादा के लाइफ टर्म की सजा है। मजिस्ट्रेट्स को और ज्वायंट सेक्रेटरी से above को लाइफ टर्म की सजा दे सकते हैं। सिर्फ यह कह देने से कि हमारे जन-लोकपाल बलि को पास कर दीजिए से हम पास नहीं कर सकते, हम लोगों को यह देखने की भी जरूरत है कि जन-लोकपाल बलि में क्या लिखा हुआ है।

यह खुशी की बात है कि आजलीडर ऑफ दि अपोजिशन ने बहुत-सी बातें कहीं। I really appreciate that because he intervened in the matter, it appears so, and he had consultations with the persons who have prepared this Jan Lokpal Bill. They have met him and he has tried to put, according to him, certain sense on them and they have realized that. There are several provisions in this which they feel that they cannot be accepted, for example, the service matters of State employees. The Leader of the Opposition has said that they have appeared to have agreed that they will not be able to violate article 311 or article 320 of the Constitution. There cannot be Lokayukts in view of the provisions in the Constitution where it provides that the State will have the power over the employees within the State's jurisdiction. So, there are several other things, which were said by the Leader of the Opposition, on which they have agreed. They have also agreed on judiciary and other things. If that is so, then what

are we discussing today? Why is not there a third version which should have come today or the last version which should have come today after consultation with the Leader of the Opposition? Suppose, they are not listening to anybody else, at least, they have listened to him. So, if good sense prevailed that there are certain provisions which they themselves agree – as has been said by the Leader of the Opposition today – that these things require to be reconsidered, as we think that they have to be reconsidered. If that is so, then, there should be a latest version of the Lokpal Bill, which should be before us and which should show that these are the provisions which are now finally agreed by them and that maybe forwarded to the Standing Committee. But, as I learnt the Jan Lokpal, as it is, has been sent to the Standing Committee for consideration. Is there an agreement on various issues, including the three issues which have been raised today and that is whether the jurisdiction of the Lokpal should cover all the employees of the Central Government?

Now, this, as I could understand after hearing, this question was probably not agreeable, they say every employee should be there. Now, if every employee has to be there, we don't agree with this. Why? एक Class 4 employee जोकि चपरासी है, महोदय, यहां बताया गया कि 38-39 लाख employees हैं और अगर सब employees को दायरे में लेते हैं तो जो सब से lower level का Class 4 employee है, आप उस को भी जन लोकपाल बलि में लाएंगे ? Will it be feasible? Will this be practical? Therefore, अगर आप को corruption रोकना है, इसे रोकना जाना चाहिए और रुकना चाहिए तो हम लोगों का मत है कि आप ऊपर से उस लेवल तक आइए जहां का control नीचे रहता है। अगर उन के ऊपर आप अपना कंट्रोल रखेंगे, उन के ऊपर लोकपाल रहेगा तो वे नीचे के लेवल पर कंट्रोल करने के लिये अपने आप बाध्य होंगे वरना अगर हम Class 3, Class 4 तक के employees को भी इस में ले आते हैं तो यह बिल्कुल ही impracticable और अव्यावहारिक होगा। इसलिए हमारा मत है कि इस के अधीन सारे employees को नहीं लाया जाना चाहिए। दूसरा सवाल यह कि Institution of Lokayukta in all States होना चाहिए ? मैंने अभी आप के सामने यह बात रखी कि जहां तक लोक आयुक्त की बात है, एक बलि बनाकर यह कहा जाए कि लोक आयुक्त यही बलि adopt करेंगे, यह जो suggestion है, वह अलग चीज़ है। प्रश्न यह है कि अगर लोक आयुक्त बनाने की पॉवर स्टेट गवर्नमेंट को है तो उसे वह पॉवर exercise करनी चाहिए। अगर उस में आपको लग रहा है कि कोई गलत provision है, या इस provision को effective बनाना है तो स्टेट को सजेशन दीजिए जसि से कि वह वहां पर implement हो सके और आप का सजेशन कंसीडर किया जा सके। लेकिन यह कहना कि एक जन लोकपाल बलि जो हम बना रहे हैं, जसि में हम ने सारी पॉबर्स इस तरह की दीं, जसि के बारे में हमें खुद को भी नहीं मालूम है कि ये सही हैं या गलत हैं, जसि के बारे में आज भी उन्हीं लोगों के बीच में confusion बना हुआ है और दोबारा a learned person like Mr. Arun Jaitley, who is the Leader of the Opposition, told them the discrepancies, probably of their Bill and they have agreed that there are so many discrepancies. So, therefore, first let there be a Lokpal Bill for the Centre and then think over about the other States. First get one which we are not getting for the last 42 years. One after the other, attempts have been

made to get it and we are always failing into it. So, let us achieve that and then decide to tread into the field of the States, which would not be advisable at this stage, specially looking into the fact that the Lokayuktas are already into existence. As I said, maybe in some places like Gujarat, it was said that it is not there. गुजरात में भी हो गया।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : नहीं , गुजरात में कोर्ट ने without consulting the ruling party on the recommendation of the Opposition leader किया है।

श्री सतीश चन्द्र मश्री : जो provisions Act में हैं , उस के तहत लोक आयुक्त दिया ?

श्री एस.एस. अहलुवालिया : यह सात साल तक गवर्नर के पास पड़ा रहा।

श्री रामविलास पासवान : वह तो लोकपाल भी करेगा ? लोकपाल स्टेट गवर्नमेंट से consult करेगा ?... (व्यवधान) ...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

श्री उपसभापति : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: On whether the Lokpal should have the power to punish all those who violate the Grievance Redressal Mechanism should be put in place, I may bring to the notice of the House that yes, Grievance Redressal Cell should be there and they should be effective. So far as the State of Uttar Pradesh is concerned, it is already there. उन्होंने उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून बना दिया है और वह वहां पर enforceable भी है, उस पर वर्क हो रहा है। उसमें अगर वॉयलेशन हो रहा है तो ऐक्शन हो रहा है, उसके रजिस्ट्रार बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसलिए यह कहना कि लोकपाल में ही यह हो सकता है, ऐसा नहीं है। जहां तक इसका सवाल है, इसका अलगसे ऐक्ट बन सकता है और बनाना चाहिए - उत्तर प्रदेश राज्य में बना है, इसी तरह से सेंटर में भी बनना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए, जिससे लोगों की जो शिकायतें हैं, हर स्तर पर उनकी जो शिकायत आती है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, वह सुनी जा सके। महोदय, वे तीन मुद्दे, जिनके बारे में आज मुख्य रूप से डिस्कशन रखी गयी थी, उनके संबंध में मुझे यही कहना है। इसके साथ-साथ मैं फरि से एक बार यह कहना चाहूंगा कि जहां तक जन लोकपाल बिलि है, इसमें, I am sure, those persons are reasonable persons. They have considered this once again in their meeting with the hon. Leader of the Opposition. They should come out with a new version of the Bill. It should not be the Government version. Then, Sir, any Bill has to go before the Standing Committee. The procedure provided under the Constitution for passing of any Bill has to be followed. We cannot bypass that. We cannot do merely because a large number of people say, 'no, this should be passed. This should be sent to Parliament...' - So, it is sent to Parliament - '...asking it to put a stamp, pass it and send it back to us.' That is not justified. The procedure has to be followed. Why I am emphasizing for following the procedure is, a detailed clause-by-clause consideration of the Bill would take place in the Standing Committee. When the Committee scrutinizes the Bill, there would be several recommendations for amending the original Bill.

Now, with regard to the latest version, they themselves have admitted and agreed, when they met the hon. Leader of the Opposition, that there are several issues on which there is a need for reconsideration. If that is so, how a Bill can be passed in this manner? How can they say, 'this has to be passed in such and such fashion, otherwise, Shri Anna Hazare it would not be permitted to break his fast?' This is very unfortunate. A person of 74 years of age – everybody respects him; the entire nation respects him – leading such a big movement resulting in consideration of their demands by this House. We have to see whether the objective is being achieved. The objective would be achieved only when the provisions of the Government's version, Jan Lokpal's version and other versions are considered threadbare by the Standing Committee by following the prescribed procedure. After

that a final draft will emerge and then we in both the Houses – will have an opportunity to discuss and consider clause-by-clause and then this can be made into an Act, so that it does not become unconstitutional. Simply if we make an Act, without following the due process of law, tomorrow it will be declared as *ultra vires*. It is not going to help anybody. It will not help even to those who are agitating, including Shri Anna Hazareji. He also does not want that a Bill be passed in haste by Parliament and tomorrow it is struck down by the hon. Supreme Court. It will not, in any way, satisfy Shri Anna Hazareji. So, therefore, we have to look into it very cautiously. We have to follow the procedure laid down under the Constitution written by Dr. Bhimrao Ambedkar. At the same time, I once again appeal to the Central Government that it should, in its own draft, at least, reconsider their demands. The civil society people should also reconsider that they should not and cannot ignore SC/ST/OBCs and the Minorities class. If you continue to do this, it will not help in any manner the nation in the long run and it will bring out several other issues and several other problems which will be more harmful than merely getting a Lokpal. Thank you.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir.

We are once again discussing this issue. This is the third occasion in the last few weeks. But, I am not complaining. I am only saying that the gravity of the situation and the urgency and importance of the situation is making us discuss it on the third occasion in the last few weeks. This seriousness of the situation – what is happening outside is that Shri Anna Hazare is on hunger strike for 12th day – demands us that this august House rise to the occasion, like we have risen in the past when we were considering the Impeachment Motion and on various other occasions, to seriously address this issue and to resolve the impasse that is there in the country today.

This is absolutely essential for our future and its constitutional order. Therefore, in that spirit, I would like to suggest some constructive points. First of all, I join this entire Parliament and

the entire country in seeking the withdrawal of the fast by Shri Anna Hazare so that normalcy can be restored, and that should be on the basis of certain assurances that they have sought from the Parliament. Representatives of team Anna also came and met us. They made those three points that were raised by the hon. Finance Minister this morning. And, we have given them the opinion which I would like to articulate here. But there are two issues that actually concern us here. One is the question of the Lokpal itself and the second is the three conditions that they have put. Before coming to that, I have stated this earlier also, but I want to take a minute of your time to talk about the 'civil society' and the 'uncivil' or 'non-civil society'. I have raised it a number of times. If you look back at the etymology of the term 'civil society, what I can

remember and what I can recollect, it was the German philosopher Hegel who first coined this term 'civil society' to describe the evolution of modern society. And, that civil society was to embrace all the juridical, political and all the other structures. That is how the concept of 'civil society' emerged. Karl Marx, who had said that Hegel was standing on his head and that he had to be turned on his feet, had said that 'civil society' is correct, but the anatomy of the civil society is to be sought in political economy. The economic conditions of the people are the one that finally determined quality of that civil society. In this august House, you have hon. Members, like, Shri Shyam Benegal and Shri Javed Akhtar. Are they 'uncivil society'? Let us not divide our society in terms of civility and uncivility. We are all parts of that civil society. And, as a part of that civil society, it is our responsibility to make sure that some things, which are wrong in our society, are to be corrected.

Therefore, let us take the first issue of Lokpal. Correctly pointed out, this was in 1968 when Late Morarji Desai headed the Administrative Reforms Committee. He made the recommendation of the 'Lokpal' and the 'Lokayukta'. We keep forgetting that. ...(*Interruptions*)... The recommendations came in 1968 and the first Bill was also brought in 1969 itself. But this had lapsed because the Lok Sabha was dissolved and, therefore, it did not come to the Rajya Sabha. We all know the history. After this, the Bill was presented to Parliament for nine times. What I am trying to State here is that it is not that we are unaware of this process, or not that we are creating this institution of Lokpal in a great hurry, but after applying mind for 40 years, which means, four decades, which the Parliament has gone through. That has delayed this. And, I think, unfortunately delayed this. I would like to convey to the entire country, through you, that this august House and the Indian Parliament, and including us, our party, the Left Parties, have consistently been advocating for a Lokpal. In the time of the V.P. Singh's Government, after the Bofors incident, we all said that the Lokpal institution must be created and that must include the Prime

Minister too. In 1996, when the United Front Government came, the Common Minimum Programme was drafted. We had a role to play in that, and I personally too had a role to play in that. And, two of the others, who had a role to play in that, are today the members of your Union Cabinet - the current Home Minister and the current Petroleum Minister - also jointly drafted that. They were both parties to that draft. What did we say in the Common Minimum Programme? I quote, "The United Front is committed to provide a corruption-free administration. A Bill to set up Lokpal will be introduced in the first Budget session of the Eleventh Lok Sabha. The Bill will cover the office of the Prime Minister as well. All Members of Parliament will be required, by law, to declare their assets annually before the Lokpal."

3.00 P.M.

We were party to this draft. In 2004 when the UPA-I Government was formed, we were party to the draft where we insisted that the Lokpal should be institutionalised and that came in as part of the Common Minimum Programme. So, the Left has been, consistently supporting and wanting this Lokpal, but for various reasons it has not happened, and it did not come about. But, now, Sir, the issue has become an issue of national concern. The hon. Prime Minister saluted Shri Anna Hazareji the other day in the other House saying that you brought this into public discourse and the whole country is now seized of this matter, which is very good. It is on the basis of that feeling we must recognise two things. One is that it has become such a popular issue where people are expressing themselves as a manifestation of the disgust they have against the unfolding of scams that have been coming in the last few months. Scam after scam is coming up and the entire political class is being blamed saying that it is because of you that this sort of corruption in high places is taking place.

Secondly, Sir, we must, I think, in a self-critical way accept the fact that as Parliament; as august House, whenever these issues came up, we also did not rise to the occasion to tackle them immediately. One whole session was wasted on whether we should have the JPC or not. Whenever these issues came up, the Parliament did not intervene. But when the CAG gives a report, when the hon. Supreme Court or the CBI proceeds, only, then, action is taken. What is the message we have sent to the people? It is that we are not interested. We are not interested or we are not competent. And, therefore, only when the other authorities take initiative on this matter, we will act. That, I think, in retrospect, we must self-critically accept, is a very big mistake on our own part as the Parliament. You have created this sort of feeling among people that Parliament is not serious and, therefore, these public protests and public actions were given certain credibility.

Once we accept that, Sir, then, we should now come down to the issue of these nine drafts that have come of the Lokpal. For 40 years

deliberations have taken place. We cannot lose another moment in not establishing the Lokpal. Therefore, on the Jan Lokpal, I have around nine points to make. I will just put down those points. One is that the Lokpal should be established. But the first point is that the selection process for the Lokpal has to be broad-based and not only Government-loaded. It also has to reflect the social inclusiveness of our society.

Second, the Prime Minister has to be brought under the purview of the Lokpal with the required safeguards.

Third, it is a fact that during these 40 years of discussion on Lokpal the situation in our

country has also changed, and we have moved towards neo-liberal reforms. A new situation has arisen, and, I think, in that background, the definition of corruption has to change. The definition of corruption will have to be widened to include wilfully giving any undue benefit to any person or entity or obtaining any undue benefit from any public servant in violation of laws and rules. This widening of the definition is necessary. It is not only for pecuniary gain that an individual makes, but by an act of that individual in authority, the nation loses; the national Exchequer loses. Therefore, it is not only the acts of commission, but the acts of omission should also be brought into this ambit. That is how we will have to safeguard ourselves.

As far as the Judiciary is concerned, I think, there is now an agreement that there should be a separate mechanism and that the National Judicial Commission should be established. We have been asking for that for many years. I think that should be brought about as soon as possible.

As far as the question of Members of Parliament inside the House is concerned, — Article 105 makes it clear — if there are instances of Members acting inside the House under charges of corruption, we are ready to discuss it. For example, we have seen the cash-for-votes case. Outside, of course, they will be part of the Anti-Corruption laws and Acts that we have. They have no protection there. But inside Parliament also, we are willing to discuss how that should be brought about. If necessary, we are willing to discuss provisions of Article 105 and see if they need to be amended. But the point is, no act of corruption expressed even inside the House can also be avoided and very correctly it was pointed out. In the Lok Sabha, we took action against Members of Parliament. Even here also we took action against our hon. Members. We are vigilant. But if public confidence has to be given, that Section can be strengthened or that opinion can be conveyed that this will be done. Then, sixth point relates to Lokayuktas at State level. Sir, I will come to this later when I

respond to those three questions. But I think the question of Lokayuktas will have to be taken up on the basis of what we have done in the past. What we have done in the past on a number of issues, Sir, I think we should take all this as a process of maturation of Indian democracy. You had the Panchayati Raj Institutions formed in various States. A full 11 years after the Left Front Government instituted that in West Bengal, we had the 73rd and 74th Constitutional Amendments. When the States went through that experience, many States did that. Karnataka did that, Madhya Pradesh did that, many States did that and, then, you came up with a Central law. If felt necessary, you amended the Constitution. You did that with the Right to Information Act. Finally, you brought in a Central law in which you gave a direction that such Commissions should be there in every State. So, in that

learning process, as I said the other day, you are now coming to a situation where it is, perfectly, possible. We have done that in the past. Prepare a model Bill, send it to the States for their consideration and their Assemblies' deliberation and let them institute the Lokayuktas. So, it has to be mandatory that Lokayuktas will be there, but, how, what, that privilege of the State Legislatures and our Centre-State relations is something which is inviolable. That we cannot violate. So, let that be the procedure. That must be done.

My seventh point relates to whistle blowers. For the protection of whistle blowers, the existing Public Interest Disclosure Bill and Protection of Information Bill need to be strengthened and passed expeditiously.

Now, I come to the question of Citizens' Charter. Again, we are, actually, talking of it as though this is something new that we have brought about. There are Right to Services Act that have been passed by five States in our country already. They are Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Punjab and Uttar Pradesh. They are proposed in Jharkhand, Kerala and Rajasthan. I was surprised to see, Sir, - the hon. Chairman of the relevant Committee is not here at this moment - the other day, on the Internet, the draft Electronics Services Delivery Bill. It was also written that citizens may send their responses to Abhishek80.gov.in by 4th of May, 2011. It is in the public domain. In public domain, there is a Bill of 2011 called Electronic Services Delivery Bill. The scope of the Bill, actually, says, that every competent authority of the appropriate Government shall publish (i) all the public services of the Department/Agencies or Body which have to be delivered through electronic mode - that is the mode that all of us, surely, should move to; this applies to all; then, (ii) the date by which these services shall be made available; (iii) the manner of delivery of such services and their service levels and this is most important (iv) the grievance redressal mechanism available to any person aggrieved about the outcome of any request made by him for such service... This is there. Your Bill is in public domain. You are discussing it. I do not know why the Government is not even referring to the fact that this mechanism has already been

proposed by this very Government. You already have a mechanism that you have proposed. It is there in the public domain. Either the left hand of the Government does not know what the right hand is doing, or, the Government itself is not realizing that what it is, actually, doing. So, such a mechanism has already been suggested by it. So, if it can be brought into the framework of the Lokpal saying that such a mechanism is there, very good. You can bring it. But the point is that such a mechanism is, absolutely, necessary.

Finally, Sir, there has to be some provision in the Lokpal Bill to take steps against corporate companies and business houses which indulge in corrupt practices. Is corruption the prerogative only of public servants? I have said earlier that you have a nexus. You have the nexus, Sir, of

corrupt politicians, corrupt bureaucrats, corrupt corporate houses and I am sorry to add, certain sections of the corporate media. You have this nexus that is coming up. But the Lokpal should have the authority and power to also move against these other sections; it cannot be only for one particular section. ...(*Interruptions*)... Therefore, Sir, on the three specific issues, as I said earlier, suggested by Team Anna, they wanted an assurance from Parliament. Yes, on the question of the Lokayuktas, we agree that they should be established. But it can be done through a model Act from the Centre and the federal principles of our Constitution, cannot, as I said earlier, be violated.

Second, a reference to a separate law for Citizens Charter and redressal of grievances can be made under the provisions of the Lokpal, but a separate law, as I mentioned earlier, a sort of separate law like the Right to Services Act, must be created.

SHRI V. NARAYANASAMY: There is one clarification on that. For Citizens Charter and public grievances redressal mechanism, there is going to be a separate Act. This suggestion came from all the hon. Members. But how can it be brought within the ambit of Lokpal Bill? Can you give some suggestion on that?

SHRI SITARAM YECHURY: No, no; that is not to be brought within the ambit of the Lokpal Bill legislatively. The point is that the Lokpal legislation that you bring about can make a reference that you will have such a mechanism through a separate law. We have done this in the past. We have done this with the RTI regulation. We have given this thing. ...(*Interruptions*)...

Sir, the final question that has come up is the question of the lower bureaucracy. Lower bureaucracy, at all levels, must be under the Lokpal. Now, I for one, Sir, fully support that bureaucracy, at all levels, must be under its purview. But we will have to look at the constitutionality and the practicality of the issue. Today, Sir, you tell me – the hon. Judiciary is there; I don't want to cast any aspersions personally on anybody; that's not my idea at all – how many cases are pending in our country waiting for justice to be delivered? There are crores of cases, if you take the lower courts. Lakhs of

people in our country are in judicial custody not because they have committed a crime, but because the case whether they are guilty or not has not yet been processed. Now, you have such a backlog of the delivery of justice and you want that 1,46,00,000 employees should be covered only by one authority. Is that possible, Sir? So, I think, a serious thought must be given to it. While we say, 'yes, everybody 'must be' accountable, 'must be' brought to book', but practicality has to be seen in that 'must be'. That practicality, how you would do it, ...

SHRI RAJNITI PRASAD: Are you supporting civil society Bill?
...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: I am saying, 'I want a new Bill.' The Government Bill is not adequate. I have many differences with Jan Lokpal Bill. So, I want a combination of the best of all these Bills and a new draft should be brought here, and, in that new draft, the three points that Anna Hazareji has raised, I am addressing those three points. All three, according to me, are acceptable. But how is it to be done? That has to be within the framework of our Constitution. Secondly, Sir, as far as all the lower level bureaucrats are concerned, the lower level bureaucrats, I think, must be made accountable. But you understand the practicality. I gave the example of Judiciary. But there are also Articles 311 and 320 of our Constitution. They talk how they are protected. They are protected from harassment by higher bureaucrats. They see how they cannot be harassed by all this. ...*(Interruptions)*...

SHRI MOHAMMAD SHAFI (Jammu and Kashmir): What about time-lag?

SHRI SITARAM YECHURY: I am coming to that. So, as far as this is concerned, Sir, I think, that we can have a way. For the lower bureaucracy, the existing vigilance machinery, which is there to oversee them, can be brought under the supervision of the Lokpal. You already have an existing vigilance machinery. That can be brought under the supervision of the Lokpal. If the existing machinery is not delivering, then the Lokpal can be approached. But the question is, you cannot bring everybody under one institution and one authority at the country-level. It is just not feasible. It is just not possible. Therefore, Sir, what we will have to suggest in my opinion is that this august House must convey to Anna Hazareji and this entire agitation that is going on outside that 'on all the three points that you have raised, the House gives you the assurance that it agrees with these points.' ...*(Interruptions)*... We agree with these points, with all three points. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान : अभी तो आप वरिध में बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)* ...

श्री सीताराम येचुरी : आप सुझ ही नहीं रहे हैं , चलिए मैं आपको बताता हूँ , हमारी सहमति उन खयालों पर है , उन मुद्दों पर है , जो उन्होंने तीस बातें उठाई हैं उन्होंने कहा है कि

सभी मुखाज़िम्मों को आपको लोकपाल के तहत लाना है, स्टेट्स में लोकायुक्त हो और तीसरी बात उन्होंने कही है कि redressal के लिए एक सटीजन चार्टर हो। ... (व्यवधान) ...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : येचुरी जी, आप यह clear कर दीजिए कि आप कह रहे हैं कि स्टेट में लोकायुक्त हो, तो यह स्टेट की मर्जी से हो कि वह लोकपाल के अंतर्गत आए? दूसरी बात यह है कि सभी कर्मचारियों को इसके अंतर्गत लाने से पहले इस पर उनकी राय ली जाए या न ली जाए? अगर कल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तब क्या होगा?

श्री सीताराम येचुरी : यह बिल्कुल सही बात है।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : कर्मचारियों के फेडरेशन ने इसे support किया है।

श्री सीताराम येचूरी : पहले तो मैं इस बात को दोहरा दूँ कि जहाँ तक स्टेट्स के अन्दर लोकसंयुक्त का सवाल है, हमने यही कहा है कि सेंसर से एक मॉडल एक्ट बना कर भेजा जा सकता है, जिसके आधार पर राज्य सरकार और राज्य की लेजिस्लेटिव असेम्बलीज़ उसे consider करके अपने हिसाब से उसको लेंगे, लेकिन हर राज्य को लेना होगा। कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वगैरह-वगैरह, ये बाह्य वे लोग तय करेंगे। यहाँ संघवाद, जो हमारे संविधान की बुनियाद है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों की बात है, हमारे संविधान में आर्टिकल 311 और आर्टिकल 320 के तहत उनके अधिकार की गारंटी दी गई है। उस गारंटी का उल्लंघन नहीं हो सकता। चूँकि उस गारंटी का उल्लंघन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा यह कहना है कि एक ऐसा mechanism बने कि मुलाजिमी के लिये आज जो vigilance की mechanism है, अगर उससे justice नहीं होती है, तो लोकपाल में अपील हो सकती है या इस तरह की बातों के बारे में हम सोच सकते हैं। यह दूसरी बात है।

जहाँ तक तीसरी बात है, Citizen's Charter और Redressal की, हमने बताया कि इसके लिये सरकार का ही एक कानून तैयार पड़ा हुआ है, उसके बारे में सलाह-मशविरा हो रहा है, तो उसको आप जोड़ें।

ये तीनों मुद्दे वशिदास्पद मुद्दे हैं। इन तीनों मुद्दों पर हमारी संसद की जो राय बनेगी, वह राय यही है कि हम इन तीनों मुद्दों को in principle मानें। लेकिन इन्हें कौन-कौन से तरीके से लागू करना है, वह हमारे संविधान के तहत होगा। उपसभापति जी, हमारे पास जो संवैधानिक व्यवस्था और ढाँचा है, अब इसको समझना जरूरी है कि हमारे उस संवैधानिक ढाँचे का उल्लंघन किसी भी ढंग से नहीं हो सकता। याद करिएगा कि जब बाबरी मस्जिद गरिने के बाद चार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का यह नर्णय आया कि 'The fundamental features of our Constitution cannot be violated'. अगर किसी सरकार के पास majority भी हो, तो Constitution के fundamental features को you cannot violate. You cannot change the fundamental features even if you have a majority. Now, that is the sacrosanctness of our Constitution.

Federalism is one of those fundamental features; secularism and democracy are fundamental features, as the Supreme Court has defined. That is why, I am pained to hear, Sir, that a former Law Minister, who was also the co-Chairman of the Drafting Committee, said that there were times when the Parliament passed a Bill and made a law within four hours. Yes, we did, Sir, and the whole country paid the price for it. It passed a law during the period of Emergency, abrogating democratic rights, and for that the entire Parliament, the entire country, paid the price. We all corrected ourselves, and the system itself corrected us, to make sure that such abrogations do not take place. That is why, Sir, we must now realize that the Constitution of India is the social contract between the Indian people and the Indian State. That social contract is inviolable; it cannot be violated. It is on that basis that we will have to convey this assurance from this House to Shri Anna Hazare and everybody else outside that all the three points that he has raised will be incorporated in the Lokpal, but it will be within the framework of

our Constitution, that Constitutionality will be maintained and all the three points will be incorporated.

Finally, Sir, there is a genuine fear that just as you brought the Bill nine times in the last 42 years, this time too, you would do the same thing. Now, we have to give that assurance...

SHRI V. NARAYANASAMY: We too share the responsibility. It is not only you.
...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: I am saying 'we' in the sense of the Parliament. We have brought it nine times in the past and again, we would all be doing the same thing, and nothing will come out of it! Now, that fear that people have is a genuine fear. That fear needs to be addressed, and that is what I meant when I began by saying that we must rise to the occasion. I think, we must rise to the occasion and say, 'yes, this is the learning process; yes, for the last 40 years we have been discussing it; yes, on many issues, various States have taken initiatives when a Central legislation was formulated, whether it was the Panchayati Raj or the RTI'. On this also, many States have the Lokayuktas and we are discussing the Lokpal. Now in the concept of the Ombudsman, that we were talking about earlier, the question of institutionalizing this Lokpal is something that will not be delayed any further. It will be done at the earliest. For that, the process has begun. I think, Sir, this unqualified assurance must be given to Anna Hazare and the people outside. This unqualified assurance we must give to ourselves to improve our democracy and, like I said earlier, we should assess the process of maturation of our democracy a little more in the process and enact an effective Lokpal and a strong Lokpal which is neither the Government draft today, nor the Jan Lokpal draft today. Let us incorporate all good points and make a new law that will give us a good stage in the future for better accountability, better transparency and better administration.

श्री शविनन्द तिवारी (बहिर) : उपसभापति महोदय , धन्यवाद।
अभी हमें जागरूकता दी गई कि लोकपाल का मामला 42 वर्षों से
पेंडिंग है , लेकिन हमें लगता है कि इस बार लोकपाल का बिल

जरूर पास होगा , एक ठीक - ठाक बलि पास होगा। अभी सीताराम येधुरी जी बोल रहे थे तो इन्होंने कहा कि... (व्यवधान) ... अरे भाई , बोलने दो , नश्चिंत रहो , लोकपाल पास होगा। तुम तो एमए पास हो , हम तो बीए पास भी नहीं हैं , मैट्रिक भी ठेल - ठाल कर पास की है ... (व्यवधान) ... बाहर लोग जो बोल रहे हैं कि अनपढ़ लोग चले गए हैं , उसमें भी हम हैं। तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो ... (व्यवधान) ...

मैं यह कह रहा था , सीताराम येधुरी जी ने कहा कि यह बलि पास हो , लोकपाल बने , ताकि नॉर्मलिसी स्थापित हो सके। हम लोगों ने 42 वर्षों तक, और 42 वर्ष ही क्यों , 1946 में पहली दफा हिन्दुस्तानियों की सरकार बनी और पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री बने , 65 वर्षों तक हम लोगों ने इंजिनियर किया। कसि चीज़ का इंजिनियर किया ? नॉर्मलिसी का इंजिनियर किया। ऐसा नहीं है कि अन्ना हजारे साहब की जान बचाने के

लखि हम लोग इतने बेचैन हैं या सरकारी इतनी बेचैन हैं और सरकार रात भर जाग रही है, कोई रास्ता खोजने का प्रयास कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश में अगर भूख से कोई मरता है, तो सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है। एक नशिमानन्द जी थे। हरिद्वार में गंगा को बचाने के लखि उन्होंने जाम दे दी, लेकिन सरकार पर या हम लोगों पर कहीं भी हील-डोल नहीं हुआ।

उपसभापति महोदय, यह ढोंगी लोगों का देश है। गंगा को हम मां कहते हैं। उस मां को बचाने के लखि उस आदमी ने अपनी जाम दे दी, लेकिन किसी के काम पर जू तक नहीं रेंगी। इस देश में 46% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और हर साल कतिने ही लोग भूख के कारण मरते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं होता है।

सरकार बेचैन क्यों हुई? वह इसलिए बेचैन नहीं हुई कि अन्ना हजारे जी उपवास पर हैं। सरकार को अंदाज़ नहीं था कि अन्ना हजारे जसि मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, उस मुद्दे से इस देश की जनता वधिलित है। लोगों के मन में एक बेचैनी है, लोगों के मन में गुस्सा है, इसका अंदाज़ सरकार को नहीं था। अगर इसका अंदाज़ सरकार को होता तो सरकार ने अन्ना हजारे को इस बार के अनशन पर बैठने के पहले गरिष्ठितार नहीं किया होता। अगर सरकार को इस बात का अंदाज़ होता, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ता से उस बूढ़े आदमी को * नहीं दखिवाई होती। इनको अंदाज़ नहीं था, इसीलिए यह हुआ ... (व्यवधान) ... और जब इनको अंदाज़ हुआ ... (व्यवधान) ... उस पर भी हम आएंगे, अभी बहुत समय है, आप बैठ जाइए ... (व्यवधान) ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप उन्हें बोलने दीजिए, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? ... (व्यवधान) ...

श्री शविनन्द तवारी : हमें भी तो * सुबनी पड़ी है, आप ही को नहीं सुबनी पड़ी है। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : * शब्द एक्सपंज कर दीजिए।

श्री शविनन्द तवारी : मैं यह कह रहा था कि जब सरकार को अंदाज़ हुआ, तब सरकार के अन्दर बेचैनी हुई कि नहीं साहब, अब तो मामला हाथ से बाहर जा रहा है और तब सरकार की आंख से रातों की नींद गायब हो गई।

उपसभापति महोदय , आखिर क्यों आज तक लोकपाल नहीं बना ? क्या इस देश में भ्रष्टाचार नहीं था ? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भ्रष्टाचार नहीं था ?

आजकल पटना से एक अखबार नकिलता है - 'टेलेग्राफ' ... 'टेलेग्राफ' एक पुराना अखबार है और उसके पटना एडिशन में 21 अगस्त को हमने वेंकट कल्याणम जी का एक इंटरव्यू पढ़ा , जो 90 वर्ष के हैं , चेन्नई में रहते हैं और वह महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार के बारे में 1947 के सितम्बर महीने से शिकायतें आनी शुरू हो गईं। गाँधी जी के यहाँ रोज भ्रष्टाचार की शिकायत से सम्बन्धित 80 चिट्ठियाँ आती थीं , लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि पंडित नेहरू जी ने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसी पार्लियामेंट के बारे में जक्ति किया है। उन् होंने यह कहा है कि 'I remember, once, a Member of Parliament asked Nehru, "What was he doing to curb corruption?" Nehru replied, "The hon. Member should

*Expunged as order by the Chair.

not complain, should not worry about little corruption here and there." To this, the Member replied, "Sir, a little corruption is little pregnancy. It keeps on growing and that is what has happened." उस समय भी corruption था। हमें याद है, देश की आज़ादी के बाद ही, सन् 1948 में जीप स्कैंडल हुआ था। आप Public Accounts Committee की उस समय की रिपोर्ट देख लीजिए और साथ में जो audit report है, उसको भी देख लीजिए। जवाहर लाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और Public Accounts Committee की रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया और इतना बड़ा फरेब हुआ कि संसद में सवाल उठा, सवाल Order Paper पर आया और उसके बाद गायब कर दिया गया। इस ढंग का काम हुआ है। क्यों नहीं लोकपाल बना? मुद्रा कांड में टी.टी. कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। मुद्रा कांड की बात कसिने उठायी थी? फरिज गांधी ने क्यों नहीं लोकपाल बना? दुर्गादास की डायरी है। मुझे लगता है कि सब को पढ़नी चाहिए - 'from Curzon to Nehru'. उसमें आप पढ़िए। हमारे देश के सबसे पहले वस्ति मंत्री जो थे, 1952 में बने थे, उन्होंने लोकपाल की जरूरत की बात उठाई थी। राजेन्द्र बाबू देश के राष्ट्रपति थे। राजेन्द्र बाबू ने प्रधान मंत्री, जवाहर लाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी कि यह सवाल जरूरी है और हम लोगों को Ombudsman जैसी संस्था बनानी चाहिए। इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, पंडित नेहरू की? पंडित नेहरू की यह प्रतिक्रिया हुई कि राजेन्द्र प्रसाद जी हमारे खिलाफ हैं और इनकी नीयत हमारे प्रति ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। बहुत दुखी होकर राजेन्द्र बाबू ने दुर्गादास को कहा कि corruption का जो मामला है, वह कांग्रेस की coffin में लास्ट कील होगा। उन्होंने यह कहा। यह हालत रही है। आज abnormal स्थिति पैदा हो गई, जिसके बारे में सीताराम येचुरी जी कह रहे थे। हम लोग बहुत बेचैन हैं, राजनीति प्रसाद बेचैन हैं, राम गोपाल भाई बेचैन हैं कि हम लोगों को * दी जा रही है * दी जा रही है, ओमपुरी जी का भाषण मैंने भी सुना। मैं इस सदन से अपने घर गया और मैंने टेलीविजन चालू किया तो उस पर ओमपुरी जी का भाषण आ रहा था। उसके बाद अखबार में हमने एक रटियर्ड महिला पुलिस अधिकारी के बारे में पढ़ा। ये बुद्धिवादी लोग हैं। ये बहुत बेचैन हैं कि पार्लियामेंट में कैसे-कैसे लोग

पहुँच गये हैं ? कहा जा रहा है कि ये कौन लोग हैं ? अनपढ़ लोग हैं , अनपढ़ लोग हैं सचमुच , इनकी बेचैनी हम समझते हैं आप पार्लियामेंट की composition को देखिएगा और जो भी Assemblies हैं , उनकी composition को देखिएगा। 1977 तक आप इसी पार्लियामेंट की बनावट को देखिए। 1952 से लेकर 1977 तक इस देश के पार्लियामेंट में upper castes या ऊँची जातियाँ का बर्चस्व रहा। 1952 में ऊँची जातियों के 64 परसेंट लोग थे। 1977 के बाद इसमें परिवर्तन आया। आप 1977 का साल देख लीजिए। 1977 वह वर्ष है , जिसमें कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ , कांग्रेस की पराजय शुरू हुई। कांग्रेस की पराजय से ही OBC के जो लोग हैं और जो backward community के लोग हैं , इन्होंने upper castes को overtake किया। OBC के लोगों की संख्या 1952 में सिर्फ 12 परसेंट थी। इसके बाद 1957 के इलेक्शन में 14 परसेंट , 1967 के इलेक्शन में 17 परसेंट और 1991 में 24 परसेंट और 2004 में 30 परसेंट OBC के लोग आए। इस parliamentary democracy ने हमारे समाज में एक हलचल पैदा की , हजारों वर्षों का जड़ समाज , जाति -व्यवस्था पर आधारित समाज , पैदाइश के आधार पर किसी को बड़ा और किसी को छोटा कहने वाला समाज , और बाहें छोड़ दीजिए , रामविलास पासवान जी यहाँ बैठे हैं , जो हमारे बहुत पुराने मंत्री हैं ये 1969 में MLA बने

*Expunged as order by the Chair.

थे, उसके पहले से मैं इनको जानता हूँ। इस देश में जो * हैं, जो दलित हैं, उनको पैदायशी अछूत कहा गया। 1970 में पटना में विश्व हिन्दू धर्म सम्मेलन हुआ था। डा. कर्ण सहि जी उसके अध्यक्ष थे। पुरी के शंकराचार्य भी पटना गए थे और तब उन्होंने कहा था कि “* are born untouchables.” * पैदायशी अछूत हैं। मैंने शंकराचार्य पर... (व्यवधान) ...

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): सर, * शब्द हटाया जाए। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: * शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसको हटा दीजिए। ... (व्यवधान) ... इसको नकिल दीजिए, नकिल दीजिए। ... (व्यवधान) ...

श्री शविनन्द तिवारी: सर, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि * are born untouchables. इस तरह की खबर चली और हमारे जैसे आदमी के मन में बेचैनी हुई। हमने कहा कि लोकतंत्र तो बराबरी के अधिकार पर आधारित है। एक मुसहर का वोट और एक ब्राह्मण का वोट, दोनों के वोट का मान बराबर है, तो फिर यह आदमी कैसे कह रहा है कि * पैदायशी अछूत है। हमने इसको लेकर शंकराचार्य पर Untouchability (Offences) Act के मुताबिक मुकदमा किया और रामविलास जी हमारे गवाह थे। हमको लगता है कि जद्दिगी में पहली दफा “शविनन्द बनाम शंकराचार्य” के मुकदमे में देश भर के अखबारों में इनका नाम छपा। हमने देखा कि उस समय क्या स्थिति थी, हमने कतिनी * सुर्खी और कांग्रेस की सरकार बात करती है कि हम दलितों के, scheduled caste के हमदर्द हैं। इसी पार्लियामेंट में उस मुकदमे को लेकर सवाल उठा था, उस समय वाई.बी. चव्हाण साहब गृह मंत्री थे, संसद में बेचैनी हुई और लोगों ने कहा कि किसने अधिकार दिया कि एक खास समुदाय के बारे में यह कहा जाए कि वे पैदायशी अछूत हैं? वाई.बी. चव्हाण साहब ने सदन में आश्वासन दिया कि पटना में जो मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे में सरकार मदद करेगी, लेकिन हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली। यह देश ऐसा है।

आज उसी तबके के लोग 1967 के बाद समाजवादी आंदोलन के जरिए 1977 के बाद पार्लियामेंट में जीत करके आ रहे हैं। ये जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो अपने आपको काबिल समझते हैं। अपने आपको सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा समझते हैं, उनकी छाती में जलन हो

रही हैं , उनकी छाती पर सांझ लोट रहा हैं और उनको यह लग रहा हैं कि यह अनपढ़ कैसे चला जा रहा है। दुसाध का बैठा , * का बैठा , नाई का बैठा , हज्जाम का बैठा , यादव का बैठा , कैसे जीत करके पार्लियामेंट में जा रहा है। हम जो अभिजात्य लोग हैं , Elite लोग हैं , हमको जगह नहीं मंजूर रही हैं , ये सब फालतू लोग वहां जीत कर जा रहे हैं। यही कारण है। यही लोग बोल रहे हैं , इसलिए हम राजनीति प्रसाद जी को कहेंगे , हम रामगोपाल भाई को कहेंगे कि बैचैन होने की जरूरत नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा react करने की जरूरत नहीं है और न Privilege Motion ले आने की जरूरत है। चीजों को समझिए।

जब कर्पूरी ठाकुर ने बहिर में आरक्षण लागू किया था , पछिड़ों को आरक्षण दिया था , तब सड़कों पर गांभी दी जा रही थी। “ये पछिड़ा कहां से आई, कर्पूरिया की फलानी भी आई ऐसी गांभी दी जा रही थी। हम लोग सुबने के आदि हैं। हमको याद है कि पटना के गांधी मैदान में जय प्रकाश नारायण की सभा हो रही थी और एक दलित समाज के नौजवान ने वरिध किया कि जगजीवन राम

*Expunged as order by the Chair.

जो की गाड़ी को क्यों नहीं अंदर दिया जा रहा है? उनको आरक्षण वरिधियों ने घेर लिया और हम उनके सामने खड़े हुए, तो हमको थप्पड़ लगा और मेरा चश्मा खुल कर फँका गया। हम लोगों का अपमान सहने का भी माद्दा है? उनको बोझने दीजिए। और ज्यादा तादाद में उन गरीबों को, और ज्यादा तादाद में उन अनपढ़ लोगों को पार्लियामेंट में ला करके, एसेम्बली में भेज करके, हम उन लोगों को जवाब देंगे। हमारी चमड़ी इतनी पतली नहीं है? सदियों से हमने अपमान सहा है, लेकिन हम उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं और साबित किया है कि हमारे अंदर ताकत है? तुम्हारी छाती पर चढ़ कर हम एम.पी. बन कर घूँगे, मन्निस्टर बन कर घूँगे. तुम जलते रहो, हमको इसकी परवाह नहीं है?

महोदय, लोकपाल के बारे में जो technical पक्ष है, उनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। मेरा यह मानना है कि आज जो abnormal स्थिति पैदा हुई है, आज भ्रष्टाचार का जो रूप और आकार दिखाई दे रहा है, अगर आज़ादी के बाद, आज़ादी के साथ ही यह लोकपाल बन गया होता, तो आज तस्वीर दूसरी होती। आज राजनीति में ऊपर के लोगों की क्या हासत है? आज आप कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? हमारे यहां कहा जाता है, लोहिया कहते थे कि लोगों के कई चेहरे हैं? आज जो भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, कौम लोग यहां हैं, सब लोग एक-दूसरे के बारे में जानते हैं? हम नहीं पकड़े गए, तो हम बहुत ईमानदार हैं? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोझेंगे। हम यहां दिल्ली आते थे, बहुत दसियों से आते रहे हैं? राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कभी धरना देने, तो कभी प्रदर्शन करने आते थे? हमने पटेल चौक पर लाठी खाई है? हमको याद है, मोहन भाई यहां बैठे हुए हैं? सन् 1970 में लाठी चार्ज हुआ था और हमारा एक साथ मारा गया था। इंदिरा जो विश्व हिन्दी कोष का अनावरण करने के लिए मावलंकर हॉल में आई थीं और हम लोगों ने नारा लगाया था। उस समय शायद राजनीति जो भी थे तब हम लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया था और वहाँ हम लोग गरिफ्तार भी हुए थे? हम यहाँ लम्बे समय से आ रहे हैं? यहाँ नेताओं का वजन तौला जाता है कि कसिके पास कतिने हजार करोड़ रुपये हैं, कसिके पास कतिने अरब रुपये हैं? जो नहीं पकड़े गये हैं, वे बहुत ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के

खलिफ बोलते हैं , लेकिन लोग सब समझते हैं। इसलिए कहीं न कहीं हमको अपने भीतर भी झाँक कर देखना होगा कि हममें कहाँ क्या कमजोरी है। हमने गरीबों का हक आज तक नहीं दिया।

उपसभापति महोदय , मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। इस भ्रष्टाचार के सवाल पर, इस लोकपाल के सवाल पर देश गरम हुआ है , ऐबनॉर्मल स्थिति पैदा हुई है। उसको नॉर्मल करने के लिये हम लोग बैठे हैं , लेकिन इस देश में एक सवाल और है , जसि पर आजया कल ऐबनॉर्मल स्थिति पैदा होगी , वह कौम -सा सवाल है ? इस देश में जो गैर -बराबरी है , इस देश में जो भूख है , वह सवाल उसके खलिफ है। याद कीजिए कि जब इस देश का संविधान तैयार हुआ था , तब 1949 के नवम्बर महीने में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को सौंपते हुए क्या कहा था ? उन्होंने कहा था कि संविधान के जरिये हम बराबरी का वादा कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी के जरिए बराबरी का वादा कर रहे हैं . लेकिन हमारे समाज में गैर -बराबरी है। उन्होंने कहा था कि आर्थिक गैर - बराबरी और सामाजिक गैर -बराबरी दोनों हैं और अगर हमने इस गैर - बराबरी को पाटने का काम जल्दी नहीं किया , तो हमारी डेमोक्रेसी पर खतरा पैदा होगा , हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो सकती है। आज वही स्थिति आयी है। आज देश में भ्रष्टाचार के खलिफ उथल-पुथल मची है। आगे चल कर गैर -बराबरी के खलिफ

ऐसा होगा। (समय की घंटी) ये 46 परसेंट बच्चे , जो कुपोषण के शिकार हैं , हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं , इनके खिलाफ भी देश में एक जन आन्दोलन शुरू होगा। उसके लिए भी कोई आवाज उठाएगा और एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि हमको फरि दबि - रात बैठ कर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके जरिए सबको आगाह करना चाहता हूँ। इस देश में जो गरीबी है , इस देश में जो गैर - बराबरी है , उसको भी पाटने का काम कीजिए। सिर्फ inclusive growth और समावेशी विकास कहने से काम नहीं चलेगा। इस शब्द का इस्तेमाल करके आपको लगेगा लोगों को ठगिएगा।

उपसभापति महोदय , हम बहिर से आते हैं। बहिर की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और छोटे - छोटे कई मामलों का काम बनाने का काम किया और उसका नतीजा दस दबि में ही दिखायी देने लगा है। आप यह देखिए कि वोटर का क्या कमाल है। हमारे यहाँ पंचायतों में अति पछिड़ों को 20 परसेंट आरक्षण दिया गया है , जबकि कोई पूछता नहीं था। जब असेम्बली या पार्लियामेंट का चुनाव होता था , तो पूछा जाता था कि राजपूत कतिने हैं , ब्राह्मण कतिने हैं और यादव कतिने हैं। (समय की घंटी) बस, अब मैं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन , भील कतिने हैं , मल्लाह कतिने हैं , बड़ाई कतिने हैं , लुहार कतिने हैं , इस बात को कोई नहीं पूछता था। अंसारी कतिने हैं या धुनिया कतिने हैं , इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेता था। यह जो हजारों वर्षों का जड़ समाज है , वह सिर्फ एक नीति के चलते कि पंचायत में नीतीश कुमार ने अति पछिड़ों को 20 परसेंट आरक्षण दिया , उनके अंदर एक ताकत आ गयी। आज वे पूछते हैं कि फलां वधिन सभा क्षेत्र में अति पछिड़ों की क्या हालत है ? हम लोगों ने "महादलित आयोग" बनाया। बहुत लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि आपने उनको तोड़ दिया , आपने दलितों को बाँट दिया। यहाँ रामविलास जी भी बैठे हैं। क्या हमने उनको बाँट दिया ? क्या मुसहर के बारे में किसी ने कभी सोचा ?... (व्यवधान)...

श्री रामविलास पासवान : शक्तिनन्द जी , अति पछिड़ों के लिए कर्पूरी जी के समय के आरक्षण चला आ रहा है।

श्री शक्तिनन्द तिवारी : हम पंचायती राज में आरक्षण की बात कह रहे हैं। हमने यह कहा था और हमने तो कर्पूरी जी का भी नाम लिया था... (व्यवधान)... आप क्यों बैचैन हो रहे हैं ? आपकी

बेचैनी का कारण भी हम समझते हैं। अब आखिर कथि क्या जाए ?
इनकी पार्टी के तीम एमएलसी थे, जो इनको छोड़ कर हमारे यहाँ
चले आये। ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : आपने उनको खरीद
लिया। ... (व्यवधान) ...

श्री शक्तिनन्द तिवारी : इनकी पार्टी के जो एमएलए हैं ,
उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। ... (व्यवधान) ... इनके साथ रहने के
लिए कोई तैयार नहीं है। ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : ये खरीद रहे हैं। ... (व्यवधान) ...
यह इनकी पुरानी आदत है खरीदने की। ... (व्यवधान) ...

श्री शक्तिनन्द तिवारी : आप अपने भीतर भी झाँक कर देखिए कि
आपकी ऐसी हालत क्यों हो गयी है। एक तरफ आप रिकॉर्ड वोट से
जीतते थे और दूसरी तरफ... (व्यवधान) ... (समय की घंटी)

श्री उपसभापति : अब आप खत्म कीजिए। अभी बहुत-से मੈम्बर्स
को बोलना है। प्लीज़। ... (व्यवधान) ...

श्री शक्तिनन्द तिवारी : उपसभापति महोदय , मैं यह चेतावनी देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि सरकार भूख के खिलाफ , भुखमरी के खिलाफ और देश में जो गैर -बराबरी है , उनके खिलाफ भी कामून बनाये और सख्त कदम उठाये , नहीं तो यह संकट जो आज पैदा हुआ है , वह कल फरि पैदा होगा। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने हमको जो समय दिया , उसके लिये बहुत -बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair is liberal in giving time because this is a very important debate.

श्री राजनीति प्रसाद : सर, शक्तिनन्द तिवारी जी का भाषण अच्छा था , लेकिन अंत में गड़बड़ हो गया।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, the prevalence of the menace of corruption is a global phenomenon. No one can dispute it. The Corruption Perceptions Index 2010 of Transparency International measures the perceived levels of corruption in 178 countries and ranks the countries on the index.

Sir, in the year 2009, India's rank was 84. In the year 2010, India's rank is 87. So it is very clear that the battle against corruption, in order to be effective today, can be achieved only through a comprehensive reform of our political, legal, and administrative judicial system. The establishment of a strong and effective Lokpal is one such measure.

Sir, the UPA II is very particular about bringing in a Lokpal. When it attempted to introduce a Bill to this effect, there was a mood prevalent across the country regarding the Lokpal Bill and the people who were connected with that were accommodated by the Government.

Sir, our Finance Minister's statement very clearly says that five nominees of Shri Anna Hazare were included in the Joint Drafting Committee along with the Government and so many sittings were conducted. Their issues were addressed. And as he said, out of 40 issues, 34 issues were resolved and only 6 are still prevalent. I think the discussion is aiming at a solution even on those points.

Sir, the accusation against the Government that it is not accommodative is baseless. The Government's gesture, the way it has

approached the issue, the way it is even being discussed now after the statement of the Minister, is a clear indication to the people at large in the country that the Government is not rigid in its stand.

Sir, after having many deliberations, the so-called civil society was not in a mood to come along with the Government's decision. They are still persisting with some more demands, and we are discussing them.

Sir, first I would like to tell whether the Prime Minister has to be brought under the purview of the Lokpal. As far as the DMK Party is concerned, we are of the view that the Prime Minister should be under the purview of the Lokpal. As it was pointed out by everyone, in the year 1967,

the first Administrative Reforms Committee suggested a Lokpal and Lokayukta. It was also mentioned repeatedly that the first Bill had been introduced in 1968 and passed in the Lok Sabha in 1969, and after its dissolution, it could not come to the Rajya Sabha. Subsequently in the year 1974 itself, when our Leader Dr. Kalaignar was Chief Minister of Tamil Nadu, Lokayukta was established, and the Chief Minister was brought under the purview of Lokayukta. The Prime Minister should come under the purview of the Lokpal. There are certain other views also which say that there should be a rider to that. They could be discussed and resolved. But we feel that the Prime Minister could also be brought under the purview of the Lokpal with adequate safeguards. There is no dispute with that. Sir, as far as judiciary is concerned, judiciary has to be more accountable. Even the impeachment motion, which was discussed in this House, brought out so many issues which are to be discussed. Appointment of Judges in the High Courts and the Supreme Court must be more transparent. But, Sir, there is a *de facto* immunity guaranteed to the judiciary by the Constitution. That cannot be challenged by anyone. But, Sir, I would suggest that the Bill which has been promoted by UPA-II, the Judicial Standards and Accountability Bill 2010, can be strengthened. By that way, judiciary will also come under scrutiny and judiciary will also not be an exception. It will also be accountable. So, there is no dispute or second opinion that judiciary must also come under scrutiny. On that line, we suggest that the Judicial Standards and Accountability Bill 2010 has to be strengthened.

Sir, a very important thing is whether lower bureaucracy could be brought under the purview of Lokpal. There are lakhs and lakhs of people. Whether they could be brought under the Lokpal is still to be discussed. Whether it could come under one authority. Will it be possible when already cases are piling up in the courts of law? Whether it is possible

has to be discussed. It cannot be resolved in one day or in one moment within a small group. For all these things, there is one more solution. Apart from that, the citizen charter, which has been emphasised by Anna Hazare's team, suggests that it must be implemented without fail.

Sir, the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, when it was chaired by hon. Member Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan, had submitted its 29th Report which has clearly said that the Government Departments and Ministries should have Public Grievances Redressal Mechanism on the lines of the RTI Act in place with special focus on the information delivery system. Officers responsible for the delay must be made accountable. The Committee recommended that like RTI Act, there should be a limit of 30 days and provision of fine on delay in the PGRM system in its 29th Report. The system should be accessible, simple,

quick, fair, responsive and effective. Various Government Departments and Ministries should have a Public Grievance Redressal Mechanism in place with a special focus on information delivery system.

Sir, on all these issues which are under discussion now, which are being insisted by a group who are undertaking an agitation outside, what we suggest is, Parliament is supreme. There is no second opinion on that. We can never challenge the constitutional authorities.

Sir, the separation of powers between Judiciary, Legislature and Executive is a part of the basic structure of our Constitution. Anything that is drafted or enacted should be in conformity with the basic structure of the Constitution and no one can dispute that. So, Parliament is authorised to enact laws and whenever a Bill is introduced, which has some issues, it goes to the Standing Committee. That is our procedure which we cannot dispense with.

Sir, I think, this is not out of place if I give you one very very important example. It is in today's news column which says, "Thriving used products market to hit waste recycling plan". The electronic waste, which is being used and dispensed with by the users, is thrown out and it causes a very big environmental hazard. And, for that, the Ministry has given very clear instructions which are going to be implemented. The Government makes the manufacturers accountable for successful implementation of electronic product recycling and they need to make a significant investment. This is what the producers say. The Government notification E-waste (Management and Handling) Rules 2011 issued in May makes it mandatory for the manufacturer to collect old products and recycle them. The companies have to set up collection centres for old products either individually or collectively where the consumers can go and deposit their old products. They have also to ensure that no hazardous materials are used for manufacturing. The initiative will cover the products like computers, laptops, printers, copies, and cell phones, televisions, including CDRD, LCD, refrigerators and washing machines. Sir, you may think in what situation I am quoting. Sir, this is very important. This notification has come from the Government subsequent to a recommendation by the

Standing Committee on Industry of which I am the Chairman. Till we discussed the e-waste management, the Government did not have any idea about this. They were very much worried about the electronic waste like the products which I told you. How to dispense of those was an issue then? The ordinary people who collect those products cause hazardous environment situation. Now, that the Government has taken a decision that the manufacturer should have a collection centre where the users after having used them can deposit those old goods there and the company being the manufacturer will be responsible for recycling it. The outcome of the Standing Committee recommendations have helped the environment very much and it has to be

appreciated. I have just cited one of the examples. The Standing Committee is nothing but more than a mini-Parliament. All the political parties have got representations. As I said here, our party has got a view that the Prime Minister should be under the purview of the Lokpal Bill whereas the draft Bill of the Government does not have that. But we will put forth our view in the Standing Committee. If it is discussed in the Standing Committee, if the recommendations come before the Parliament, it is going to decide. Even the RTI Act, before it was enacted, it did not have many things which are incorporated now only after the recommendations of the Standing Committee. Those things were incorporated and the RTI is very much appreciated only because of the Standing Committee recommendations. So, Sir, what we would suggest is that the Government is for a strong Lokpal Bill. It recognizes the sentiments of the people at large. The public views have been taken cognizance of. The Government is sending emissaries to discuss with them. Let them wait till the Standing Committee submits its recommendations. It is a procedure which we cannot change. We cannot change the system. It is not a target against the Government or any political party. It is against the system. If we permit something to go on in its own way, it is not correct. Some people even challenge the electoral politics. They say, "Why do you go to the booth and stand like cattle?" I do not know what system they are seeking. But this system we have earned after very big sacrifices. For the last 64 years we have established ourselves that we are the largest democracy in the world. In the past the parliamentary system of democracy has brought out so many appreciable achievements. So, also in this situation, we are very, very sane in keeping under control of the things we are discussing now. This Bill when it goes to the Standing Committee along by informal recommendations of the Speaker, the Jan Lokpal Bill or the NCRPI Bill or anything else, every thing will be discussed and they will come here.

At this moment, I would like to suggest one thing. I would like to tell here without fail. ...*(Interruptions)*... Just one moment. On 9th

September, 2011, three youths are going to be hanged in Tamil Nadu prison. They are Perari Valan, Sanathan and Murugan. Our DMK Party has been suggesting abolishing the death penalty. Even now our leader has voiced it. Many other people, many human activists have voiced that death penalty should be abolished and those three have to be saved. We have urged the State Government and the Central Government to save the lives of those three persons. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS AND THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI VAYALAR RAVI): What is the crime? ...(*Interruptions*)...
What is the crime?

SHRI TIRUCHI SIVA: Just a moment. ...(Interruptions)... Just a moment. I am talking about the death penalty in general. ...(Interruptions)... I have got my right to express my views.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Siva, what has that got to do with this?

SHRI TIRUCHI SIVA: I am coming to the point. When we are against the abolition of death penalty totally which is in existence, how can we allow a person to suffer because of starvation? So, we appeal to Anna Hazare to kindly reconsider his fast. We appreciate his ideology. We want to have his precious life. This septuagenarian has crossed more than 70 years. He has to live long.

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Sir, this subject is different. That subject is different.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(Interruptions)... आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA: I am appealing to Anna Hazare. ...(Interruptions)... Sir, I am appealing to Anna Hazare to kindly. ...(Interruptions)... I have right to express my views, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to say that. ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: I have to express my views. I appeal to Anna Hazare, Sir, to break his fast in the interest of his health, in the interest that he should live long and strive for the people of the country. So, everything lies in giving and taking in such a manner that when the Government has come down, when it has got so many options, kindly consider some of them. We shall sit down; we shall discuss; we shall come to a conclusion. The battle against corruption should be united. We want to put down corruption with all our might. All of us should be united. So, they should also consider this; let them wait till the Standing Committee recommendations come. The Parliament will discuss and the Lokpal law which is going to be enacted here will be the strongest; we assure on behalf of the UPA, Sir. With these words, I thank you, Sir, for giving me this

opportunity to express my views.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Siva. Now, Shri Tariq Anwar.

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, आज हम लोग एक ऐतिहासिक चर्चा के लिये यहां जमा हुए हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अन्ना हजारे जी के अनशन से देश में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसे कैसे शांत किया जाए, नार्मलाइज़ किया जाए। जो लोकपाल बलि है, उसको सही ढंग से, प्रभावशाली ढंग से, मजबूती से कैसे सदन में रखा जाए, इस पर हम लोग आज चर्चा करने के लिये यहां जमा हुए हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है कि यह

4.00 P.M.

मुद्दा हमारे देश में पहले भी चुनावी मुद्दा बना है, लेकिन चुनाव के बाद सरकारें बनने के बाद सही मायने में प्रभावशाली ढंग से, गंभीरता से इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से आज भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सब लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो और उसके लिये जो भी उपाय हो सकते हैं, वे उपाय हम लोग दूढ़ने की कोशिश करें।

अभी हमारे फाइनेंस मन्निस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने यह बताया है कि अन्ना हजारे जी का इससे पहले 5 अप्रैल, 2011 को अनशन हुआ था। उसके बाद उनकी टीम का सुझाव था कि हम लोग मन्निस्टर एक ज्वाइंट इराफ्ट कमेटी बनाएं। इसमें सरकार के नुमाइंदे हों और जो सखिल सोसायटी है, उसके नुमाइंदे हों। सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को माना, हालांकि इसका वरिध भी हुआ, अखबारों में इसके बारे में टप्पिणी भी आई कि ऐसी कभी कोई परम्परा नहीं रही है कि सरकारी बलि लाने के लिये बाहर से जो सखिल सोसायटी के सदस्य हैं, उनको उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको नुमाइंदगी दी जाए, लेकिन सरकार ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की और उनको उसमें शामिल किया तथा उनके साथ बातचीत का एक सलिसिला शुरू हुआ। ज्वाइंट इराफ्ट कमेटी की 9 बार मीटिंग्स हुईं और इसके बाद बहुत सारी चीजों पर सहमति भी हुई तथा कुछ अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। उपसभापति महोदय, जबि पर सहमति नहीं हो पाई, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो प्राइम मन्निस्टर ऑफिस को लेकर सरकार का पक्ष यह था कि पी.एम. का complete exemption हो।

टीम अन्ना का कहना है कि इसमें PM को include किया जाए, MPs in Parliament के बारे में सरकार का यह पक्ष था कि "include MPs but exclude their conduct in Parliament, their powers to speak and vote". टीम अन्ना का यह कहना था कि "MPs conduct in Parliament should be included". जुडिशरी पर सरकार का यह पक्ष था कि जुडिशरी को एग्जेम्प्ट किया जाए, to include it in Judicial Accountability Bill". टीम अन्ना का कहना था कि "to include higher judiciary within the Lokpal".

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

और लोअर ब्यूरोक्रेसी के मामले में सरकार का पक्ष था, “include only Group-A officials, officials of the rank of Deputy Secretary and above”. टीम अन्ना का कहना था कि “all Government employees should be included.” इसी तरह से CBI और CVC के बारे में गवर्नमेंट का पक्ष था कि keep them separate, only 11 member agency. टीम अन्ना का मानना था कि “CBI and CVC be merged with the Lokpal” इसी तरह से कुछ ऐसे मुद्दे थे, जिन पर सरकार और अन्ना जी की टीम के बीच में कुछ मतभेद हुए। मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार की तरफ से लगातार यह प्रयास हुआ कि बाह्यीत के जरिए कोई रास्ता निकाले और एस्टेब्लिश्ड प्रोसेसिजर को मानते हुए, एक तरीका निकाला जाए। जैसा यहां पर सभी लोगों ने कहा है कि हमारे देश में संविधान है, कानून है। हमारे संविधान के नर्बिताओं ने बहुत परिश्रम करके हमारी Constituent Assembly ने एक-एक मुद्दे पर बहस की और उसके बाद वे किसी नतीजे पर पहुंचे तथा इसके बाद ही हमारे देश का संविधान बना। अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो जरूर रखे। सरकार ने इस बात को कहा है कि अगर कोई समूह अपनी बात रखना चाहे, तो रख सकता है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि जो पार्लियामेंटी प्रोसेसिजर है, हम उसको नजर अंदाज नहीं कर सकते तथा जल्दबाजी में कोई

नर्णिय नहीं लयि जा सकता है। अभी यहां यह बताया गया कि पहली बार 1968 में यह बलि पेश हुआ था। पछिले 43 सालों में यह वधियक 9 बार सदन में रखा गया , लेकिन बदकिस्मती से यह पास नहीं हो सका।

महोदय , मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब 43 सालों में कोई कानून नहीं बन पाया , तो यदि हम चाहें कि इसको 9 दसियों में बना लें , तो यह संभव नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो भी कानून हम बनाते हैं , उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है , एक दूरगामी लक्ष्य होता है। हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे संविधान पर, हमारे कार्य -कलाप पर, हमारे तमाम कामों पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम चीजों को देखने और समझने की आवश्यकता है। सभी लोगों ने यह बात कही है कि अगर हमें democracy में रहना है , लोकतंत्र को मजबूत रखना है , तो supremacy of the Constitution जरूरी है। संविधान के अंतर्गत जो हमारा तरीका है , हमें यह अपनाना होगा , तभी हम सही रास्ते पर चल पाएंगे।

महोदय , मैं Prime Minister की भी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने 23 अगस्त को एक पत्र लिखकर , अन्ना हजारे जी से अनशन तोड़ने की अपील की थी , लेकिन शायद अभी तक उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार की तरफ से हर तरह का प्रयास और कोशिश की गई कि बाह्यीत के जरिए इस समस्या का कोई समाधान नकिले। हम सबका यह मानना है कि यदि हमें लोकपाल बलि बनाना है , तो उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजना पड़ेगा। चाहे वह अन्ना हजारे जी द्वारा बनाया गया जन लोकपाल हो , या और जो दूसरी सबिल सोसायटी के लोग हैं , या जबि अन्य लोगों ने भी जो मसौदा पेश किया है , उन तमाम चीजों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए ताकि स्टैंडिंग कमेटी में वे तमाम रास्ते खुलें। स्टैंडिंग कमेटी में हमारा एक प्रोसिजर है। उसमें हम यही करते हैं कि जो भी बलि होता है , उसको स्टैंडिंग कमेटी में इसीलिए भेजा जाता है ताकि उस पर सभी लोगों की राय ली जा सके , उस पर सभी से मशविरा किया जा सके। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी उसको लोक सभा और राज्य सभा के सभा पटल पर रखती है। वह तमाम चीजों की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने सुझाव रखती है , इसलिए

स्टैंडिंग कमेटी को हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वह हमारी व्यवस्था का, हमारी जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए सरकार ने जो कहा है कि हम यह चाहते हैं कि हमारे पास अभी तक जो भी तमाम सुझाव आए हैं, हम उनको वहां भेजने का काम करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी को देने का काम करेंगे, जबकि भी अपनी राय देनी है, मशविरा देना है, वह स्टैंडिंग कमेटी को दे। ग्रीवांसेस रीट्रेसल बिल के बारे में यहां कहा गया है। लोगों ने अपनी राय दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत पहले, हमारी पब्लिक ग्रीवांसेस और जस्टिस की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने 2009 में ही अपनी एक रिपोर्ट में यह कहा था कि पब्लिक ग्रीवांसेस का समाधान सिर्फ आरटी.आई. के जरिए ही नहीं हो सकता है, अगर हम उसका समाधान चाहते हैं, तो हमको उसके लिये अलग से उपाय करना पड़ेगा और उसके लिये ठोस कदम उठाना पड़ेगा। यहां सदन में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट रखी गई थी, लेकिन शायद उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर उस पर कदम उठाया गया होता, तो शायद आज यह जो बात उठ रही है, यह सवाल नहीं उठ सकता था। अंत में मैं अपनी ओर से अन्ना हजारे जी से यह अपील करूंगा कि वे सदन की जो भावना है, उसका आदर करते हुए समाधान निकालें। पछिले दिनों लोक सभा में प्रधान मंत्री ने और वहां की स्पीकर महोदया ने भी अपील की थी और आज हम लोग यहां पर यह जो चर्चा कर रहे हैं, वह

चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि अन्ना हजारे जी अपना अनशन समाप्त करें और सरकार को मौका दें। आज सभी पार्टियां इस बात पर लगभग सहमत हैं कि एक प्रभावशाली लोकपाल बलि बने और उसके जरिए हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकें। यह जो एक राजनीतिक माहौल बना है, मैं समझता हूँ कि हमारे अन्ना हजारे जी को और उनकी सखिल सोसायटी को उसका सम्मान करना चाहिए और मौका देना चाहिए ताकि हम सांविधानिक ढंग से लोकपाल बलि को बना सकें और इस देश को इसका लाभ मलि सके, आम आदमी को, गरीब आदमी को इसका लाभ मलि सके। हम लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम हर स्तर पर भ्रष्टाचार को रोक सकें। उपसभाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उसका सारे देश में यह संदेश जरूर जाएगा कि हम सदन के लोग इस मामले में गंभीर हैं और चाहते हैं कि एक effective लोकपाल बलि बने। धन्यवाद।

SHRI BAISHNAB PARIDA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to express the view of my BJD Party. This is a historic occasion in the history of our Parliamentary democracy when not only the people of this country but the entire world are watching and listening through the electronic media how we are going to curb the menace of corruption and black money in the largest democracy of the world. After a prolonged campaign against corruption, a nationwide movement has developed throughout India by Shri Anna Hazare in a Gandhian non-violent way. The people of this country are aroused to fight corruption and black money in order to save hard-earned Independence, democracy; and to eradicate poverty and unevenness in the society. Sir, today, the leader of Biju Janata Dal in this House, Shri Pyarimohan Mohapatra, is not present here due to an important engagement at Bhubaneswar. So, I am conveying the view of our party and its President, Shri Naveen Patnaik, hon. Chief Minister of Orissa, through my speech.

Sir, our party supports the objectives and concerns of Shri Anna Hazare to curb the alarming growth of corruption and black money pervading all spheres of life. In our party meeting, we cleared our position on the pertinent issues which Shri Anna Hazare has raised. As

per our party's view, the Prime Minister of India must be included under the purview of Lokpal, with exception to his functions related to internal security and public order.

On judiciary, our party's view is that it should not be brought under the ambit of Lokpal. If we bring in judiciary, it will upset the basic structure of the Constitution and will go against the balance of power. Keeping in view judicial independence and judicial accountability, an effective mechanism like the National Judicial Commission can be formed. We are happy that Shri Anna Hazare has accepted this position regarding judiciary.

As regards Members of Parliament, our party thinks that the conduct of Members inside Parliament should not be questioned by any external authority. This will go against the

sovereignty of the Legislature. At present an internal mechanism is available in our Parliamentary system to deal with misconduct of any of its Members. Parliament had recently punished about eleven Members for their misconduct, like, in case of Cash for Question scam.

Sir, now, I will deal with the most pertinent issues raised by Shri Anna Hazare. The first one is about Grievances and Citizen's Charter. The second issue is regarding Lokayukta for States. The third one is regarding lower bureaucracy. My party welcomes the demand for framing Citizen's Charter and passing the Right to Services legislation to root out corruption at the grassroot level. Such legislations have already been passed in some of the States of India. In my State, Orissa, both the Citizen's Charter and Right to Services legislation is in an advanced stage of formation...(Interruptions)...

श्री राजनीति प्रसाद : सर, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठा है। टीबी पर यह दिखाया गया है कि उन्होंने हमारी सारी discussion को, हमारे सारे वाद-विवाद को reject कर दिया है। उन्होंने कहा कि फालतू लोग बहस कर रहे हैं। इसलिए अब इसमें बहस की क्या गुंजाइश है। हम क्यों बहस कर रहे हैं, हम अपने घर चलें।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, you have said it. That is all. Now, please proceed. ...(Interruptions)... That is on record.

SHRI BAISHNAB PARIDA: In our democracy, this is allowed, and we should not worry. Our responsibility is much more important than those who are talking there, outside Parliament. This should be kept in our mind and we should act according to our conviction.

As regards covering all the employees of the Central Government under the Lokpal, my party's view is that the Lokpal should have jurisdiction over all the Central Government employees and the State Lokayuktas should have jurisdiction over all State Government employees. In fact, in my State, all the State Government employees are covered under the jurisdiction of the State Lokayukta, as per the existing laws of our State.

Sir, I now come to the Lokpal Bill. I wish to talk about the third

most important point which concerns all the States in our country. We have a federal structure and the spirit of federalism should not be tampered with in any manner. It is essential that the State Lokayuktas are independent of the Centre. To maintain that independence, State Lokayuktas must be created and governed by State laws. Of course, we have no objection to having an enabling provision in the proposed Lokpal Bill so that States can follow the Central model. But, under no circumstances must the independence of the States to have their own legislation be curtailed. This should be done keeping in view the principles of good governance in order to redress the people's grievances.

On behalf of my Party, the Biju Janata Dal, and its leader, Shri Navin Patnaik, the hon. Chief Minister of Orissa, I humbly appeal to Shri Anna Hazare to end his fast. His precious life and noble services are essential for this country. The objectives of his fast, which are to create awareness and concern against the spread of corruption and black money, must be achieved and we shall do the best in our State and in our State Legislature to fulfill the same. We want a strong and effective Lokpal and Lokayuktas to be formed in order to deal with the serious problems confronting our nation.

Sir, I wish to express my personal views on certain other issues. Comrade Sitaram Yechury was quoting Hegel and Marx. Marx had said that ideas were abstract but when they caught people's imagination, they became a material force Sir, while we failed to catch the imagination of the youth of this country, Anna Hazare, through his Gandhian ways has done it. This is a very important point. Then, talking of members of the civil society, we must not ignore them. Marx had said it in the 19th century. But this is the 21st century. The middle class has a very important role in this country, particularly in these days of science and technology. Sir, an old man with Gandhian dress, with a Gandhi *topi*, with Gandhian ideology is mobilizing thousands of young boys and girls and bringing them out on the streets with a patriotic fervour, giving slogans like *vande mataram* and *Bharat Mata ki jai*, and talking about the problems of this country. Sir, many of our political leaders, including myself, could never bring so many people out on the streets to fight and eradicate corruption, to bring social justice. India is once again following the ideals of Gandhian philosophy. Gandhi may not be alive today but he still lives in the minds of the people. People throughout the world are now practicing Gandhian ways of life. In the meanwhile, we are saying so many things about this *satyagraha*. I can remind you, Sir, during Pandit Nehru's time, there was a debate in the Lok Sabha when Dr. Ram Manohar Lohia talked about *satyagraha*; at that moment Nehruji said, "I think Dr. Lohia is still living in the days of British Raj". But Dr. Lohia retorted, "Panditji, you are forgetting that you are a product of that *satyagraha*, that

ahimsa". And this Parliament, this democracy is a product of that great struggle led by Mahatma Gandhi who did *satyagraha* and whom we should not ignore. *Satyagraha* is eternal, it is not confined to a particular country and particular period of history. It can be applied any time, anywhere, throughout the world. Martin Luther King applied it in America to get his civil rights, against the USA Government. Why could this not be applied here? We must learn, should study and apply those views and methods.

With these words, I express my views, my party's views. We are in favour of a strong and effective Lokpal in our country in order to eradicate corruption.

श्री गुरनारायण पाणि : सर, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ ... (व्यवधान) ... उड़ीसा में लोकपाल ने वहाँ के मुख्य मंत्री के खिलाफ stricture दिया है ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन) : आप बैठिए। ... (व्यवधान) ... बैठिए। श्री सुखेन्दु शेखर राय।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you that you have given me time to speak on this occasion. This is my maiden speech in this august House and I seek your indulgence. I represent all-India Trinamool Congress. Since its inception, my party has waged a war against corruption under the unique leadership of a personality, who is committed to the cause of the people and runs a Government with a human face. Naturally, we are seriously concerned on the issue of corruption as other hon. Members have expressed their concern today.

आज सुबह यहाँ मेरे कई मंत्री आदरणीय वस्ति मंत्री जी के बयान का हब्दी version माँग रहे थे। यह माँग जायज थी। उनकी demand ठीक थी, क्योंकि हब्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम सभी को थोड़ी-बहुत हब्दी बोलनी चाहिए। हालाँकि हब्दी मेरी मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं दूरी-फूरी हब्दी में बोल लेता हूँ और आगे भी हब्दी में बोलने की कोशिश करूँगा।

महोदय, जसि मुद्दे को लेकर आज चर्चा हो रही है, इस बारे में हंगामा करना मेरा या किसी का मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि-

‘हर सूत बदलनी चाहिए।

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी, लेकिन आगजलनी चाहिए’...

तो आगजल चुकी है और उस आग का ताप हमें भी लग रहा है, क्योंकि वर्षों से हम खामोश थे। हम वर्षों से देख रहे थे और सुन रहे थे, लेकिन कोई ठोस कदम हमने नहीं उठाया। यह हमारी weakness थी और इसी weakness की वजह से आज इतना हल्ला मच गया है।

Now, I would like to speak a few words in English also because मेरी हब्दी उतनी अच्छी नहीं है। While we are all concerned about corruption, and there cannot be two opinions that stringent

measures are to be adopted to eradicate corruption at all levels, we should also consider that when we demand an institution with unbridled powers to fight corruption, are we not unwittingly walking into a regime which may ultimately culminate into an authoritarian system? This is a question that I am putting to myself. Immediately, the reply that comes to me is that we should not indulge in such a legislation which will lead to an authoritarian system. We definitely need an ombudsman who will address the grievances of the citizens and force the Government to act within a definite time-frame but not an ombudsman who acts as a super Government or a super Parliament or a super Judiciary. The proposed Lokpal should be within the framework of the Constitution—nothing more and nothing less. Any changes that are considered to be necessary

to keep a balance between our Constitutional framework and the popular demand may be effected, but not under duress. The opinion of the people, at large, are to be invited. And the proposed enactment may take a concrete shape within two-three months. But, this time, it should not be held up for indefinite period. A peculiar demand has been raised that the people who are having track with political parties cannot man the Lokpal institution, as if we are the sacrificing goats and others are holy cows. It should not be. In a democracy like ours, there cannot be distinctions like this.

My next point is, Sir, whether the institution of Prime Minister should be included within the ambit of Lokpal or not. Many hon. Members have suggested many things. I do agree with them. We do not believe in the maxim that 'king can do no wrong'. In a popular democracy like ours, the 'king can do no wrong' maxim cannot have any place. But Prime Minister is considered to be the key-stone of the Cabinet, as was rightly pointed out by one of the hon. Members in the morning. He is having a pivotal position in our system. He is also the leader of the nation. Be it Dr. Manmohan Singh or anyone else who will be the Prime Minister in future, I am talking about the institution of Prime Minister. Our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, the present Prime Minister is internationally acclaimed for his integrity, for his honesty and for his noble character. But, according to me, since he is the leader of the nation, the office of the Prime Minister should not come under the purview of Lokpal, while he is in office. While he is in office, the Prime Minister should not come under the purview of Lokpal. Hon. Leader of the Opposition, who was referring – he is not present now – to the first Lokpal Bill, prepared as back as in 1966, on the recommendations of the Administrative Reforms Commission, probably, headed by late Morarji Desai. But in that draft, the Prime Minister's office was not included.

So, the original idea was not to include the office of the Prime Minister. After 40 years or so, we are trying to evolve a framework to bring the Prime Minister also. Tomorrow, there will be a demand to bring the President also, and there will be no end of it. Some people

are drafting Lokpal Bill on a *dharna manch*. Tomorrow, some other people will draft a new constitution at India Gate, and will urge the Members of Parliament that you accept this constitution and send it to the President for his assent. This way, democracy cannot run. Democracy means the will of the people. I cannot claim that I am the messiah of the people; I am the only messiah of the people. The representatives of the people who have been voted to power, their role cannot be negated. Then, there will be negation of the Constitution. Yes; some people are saying throw away the Constitution. Then, what will be the consequence? Is it Libya or Syria? It is India. Our forefathers have fought for the freedom for long 200 years. And, after their sacrifice only, this right to freedom of speech, and other fundamental rights have come into surface. We are taking

advantage of that situation. No, we should not do it. We should be tolerant. We should come for discussion. Yes, democracy demands discussion.

Democracy demands debates. Dissension will be there. Dissension will lead to demonstration. That is also acceptable. 'But until and unless my demands are met, I would not allow the Parliament to run, I would not allow the system to run', this is something which just cannot be accepted.

My next point is that no one should claim himself or herself as holier than thou. हम ईश्वर की सन्तान हैं, ऐसा माम कसि particular individual को नहीं होना चाहिए। अगर कोई ईश्वर की सन्तान है, तो सभी हैं। अगर कसि में कमी है, तो कमी है। कुछ कमियाँ तो हमारे अन्दर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अन्दर कमी है और उसको सुधारने के लए हमको रास्ता नक़िलना चाहिए। लोकपाल बनाइये, मजबूत लोकपाल बनाइये, लेकिन इसको सुपर पार्लियामेंट, सुपर गवर्नमेंट और सुपर जुडिशरी मत बनाइये। सरकार से मेरी यही अर्ज़ी है।

अभी लोकपाल की यहाँ -वहाँ जो चर्चा हो रही है, this Lokpal is designed as a body in which police and courts are rolled into one. लोकपाल पुलिस भी होगा और लोकपाल कोर्ट भी होगा। यह नहीं हो सकता। यह contradictory है। Independence of judiciary and independence of judicial review cannot be curtailed, cannot be curbed. This is a Constitutional mandate of the separation of power. How to deal with that? I am submitting this point to those who are going to shape the Bill, I mean, the Members of the Standing Committee. I am asking them how they are going to deal with this Bill. Now, Lokpal is required, there is no doubt about it. ...(Interruptions)... Only one or two minutes more. ...(Interruptions)... सर, यह हमारी मेडन स्पीच है, दो-चार मिनट और दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I did not say anything. ...(Interruptions)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: You are looking at me...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, I am not looking at you

for this. ...(Interruptions)... I did not stop you.
...(Interruptions)... I did not stop him. ...(Interruptions)...
Everybody is supporting you. ...(Interruptions)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, I am grateful to you.
...(Interruptions)... Lokpal is required. Lokpal is undoubtedly
required. But again I am telling that it should be within the scope of
our Constitution. Who will police the police? अगर पुलिस में कुछ
बुराइयाँ हैं , तो उसकी पुलिसिंग कौन करेगा ? यह सवाल पैदा
होता है। इसके बारे में कुछ प्रसवधान रहना चाहिए। जो क़ानून
बनने जा रहा है , उसमें कुछ प्रसवधान होना चाहिए कि अगर
लोकपाल करप्ट हो जाता है , तब क्या किया जाएगा ? उसको कौन
सुधारेगा ?...(व्यवधान)...

Finally, unless we come out of our greed, — Lokpal is a legal
office, a legal measure, an administrative measure — temptation, lust
and put ourselves as a nation on moral grounds and

continuously pursue with the tenets of ethics in our daily life, no Lokpal can change the scenario. That is more important. Lokpal or no Lokpal, we require moral and ethical upsurge right now. Time has come when we require more on an ethical upsurge. We are the largest democracy and we must remember the great maxim “republics fall when profligates thrive and wise are banished from the council”. I would like to touch very briefly the three questions that have been put in the statement of hon. Minister and give the viewpoint of my party.

The question is: whether the jurisdiction of the Lokpal should cover all the employees of the Central Government. As per the present Constitutional arrangement, without amending the Constitution, I do not know whether that type of amendment can be affected because there is a judgment of Supreme Court. There are several judgments right from Kesavananda Bharti case to Minerva Mills case. So, many judgments are there. Whatever amendment Parliament wants to do, that should be done within the framework of the Constitution. That point should be taken into consideration. Next is, whether it would be applicable through the institution of Lokayukta in all States. Of course, Lokayukta is a State institution. It should be enacted by the State legislatures only to maintain our federal structure. State legislatures should enact the Lokayukta Act where there is no such Lokayukta Act and naturally, this will be applicable through the institution of the Lokayukta in the State and lastly, we have to see whether the Lokpal should have the power to punish all those who violate the Grievance Redressal Mechanism to be put in place. Although it is a leading question, I am in agreement that yes, all those who violate the Grievance Redressal Mechanism should be punished, that too within a definite time frame. There should be a definite time frame. Before I conclude, I would like to quote only two lines from a great song of Gurudev Tagore which is in Bengali, in my sweet mother tongue.

Sankochero Bihabalatai Nijere Apaman

Sankatero Kalpanate Hoyo maria man

इस का मतलब यह है कि, “संकोच के फेरे में अपने आपको अपमानित मत

करो और संकट की कल्पना में डूबे हुए बेबस मत हो। ” मैंने गुरुदेव टैगोर के सौ साल पुराने गीत की ये दो लाइनें सुबायीं। आप ने मुझे बोलने का मौका दिया , इस के लिए आप को बहुत -बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Sukhendu Sekhar Roy, it was your maiden speech but you spoke like an experienced Member. It was a good speech.

प्रो . राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् , हमारे संविधान के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच -समझकर बना या है और मैं यह समझता हूं कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इस में कोई ऐसी चीज नहीं है जसि का नसिकरण करने की व्यवस्था न हो। इस के अलावा जो अन्य कानून हैं , चाहे

वह आई पी . सी . हो , सी . आर पी . सी . हो और चाहे Anti Corruption Act हो
 — ये सब ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सक्षम हैं।
 अब प्रश्न यह है कि इन सारे कानूनों के बावजूद भ्रष्टाचार
 क्यों नरितर बढ़ा और क्या लोकपाल आने के बाद भ्रष्टाचार रुक
 जाएगा ?

महोदय , मैंने जन लोकपाल बिल को पूरा पढ़ा है और मुझे लगता
 है कि इस में कुछ धाराएं ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने
 के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करेंगी। For example कहीं
 आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों का पुलिस से झगड़ा हो गया।
 पुलिस ने रॉबर्ट में 4 आदमियों के नाम लिखे और सौ अज्ञात
 लोग लिख दिये। अब अज्ञात में जो मिला जाता है , पुलिस उस को
 पकड़ती है। वह कहती है कि चलिए , आपका नाम उस ने अपने बयान में
 दिया है। आपको जेल जाना पड़ेगा। वह कहता है कि हजार , पांच सौ
 ले लो और छोड़ दो। श्रीमन् , इस जन लोकपाल में इस तरह की धाराएं
 हैं , जिन में property seizure, preventive detention, suspension,
 removal का प्रावधान है। अब कोई भी आदमी बिल नाम के ambiguous
 चिट्ठी लिख देगा। और इंस्पेक्टर जांच करने पहुंच जाएगा। इस
 जन लोकपाल में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं , जिनसे हमारी
 पार्टी सहमत नहीं है। महोदय , जिन बन्दिओं में मुझे आज बात
 करनी है , उन पर मैं बाद में आऊंगा। मेरा अनुरोध है कि आप मुझे
 आज कुछ टाइम में दे दीजिएगा क्योंकि अगर आप घंटी बजा देते
 हैं तो मैं अपना भाषण बंद कर देता हूँ। महोदय , स्थिति यह है
 कि इस जन लोकपाल में जहां लोकपाल के गठन की बात की गयी है ,
 उसके लिए सर्व कमेटी की बात की गयी है। उस सर्व कमेटी में दस
 सदस्य होंगे , जिनमें से पांच सदस्य कानूनवेत्ता होंगे ,
 जज जगैरह होंगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि वे पांच लोग
 consensus से पांच अन्य सदस्यों को सखिल सोसायटी में से
 चुँँँगे। इस प्रकार से जो दस लोग लोकपाल के लिए नामों का चयन
 करेंगे , उनमें सखिल सोसायटी में से पांच लोग चुने जाएंगे
 और पांच जज जगैरह होंगे। प्रश्न यह है कि सखिल सोसायटी
 कसिको रिप्रेजेंट करती है , इसमें कतिने लोग हैं ? क्या
 गवर्नमेंट के पास इस बात की जानकारी है कि इसका प्रभाव
 क्षेत्र कतिना बड़ा है , इसके कतिने सदस्य हैं और उन्हीं में
 जो पांच लोग चुने जाएंगे , वे सब बहुत ईमानदार होंगे ?
 impecable honesty के होंगे ... (व्यवधान) ...

श्री तारिक अनवर: उसमें वफ़ा के नेता को भी देखेंगे।

प्रो . राम गोपाल यादव : नहीं , उसमें नहीं हैं - सर्व कमेटी में नहीं हैं , सेलैक्शन कमेटी में भी नहीं हैं। यह जो प्रोविज़न है , उससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं हो सकती। इसके अलावा उसमें मैबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में उल्लेख है कि आप अंदर जो बात करेंगे , भाषण करेंगे या वोट करेंगे , वह भी लोकपाल के परव्यू में होगा। कल कोई बलि आता है , उस पर कोई मैबर बोलता है और बाहर कोई व्यक्ति - पॉलिटिकल लोगों के वसिधी हर जगह होते हैं , political opponents होते हैं , वे एक ऐप्लीकेशन डलवा देंगे कि संसद में vested interest के तहत यह भाषण दिया गया है और इंस्पेक्टर आपके घर आकर जांच करना शुरू कर देगा। यह भारतीय संविधान की धारा 105(2) का स्पष्ट उल्लंघन होगा। इससे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। महोदय , इसका उल्लेख हमारे नेता वसिधी दल और अन्य लोग कर चुके हैं। जब मैं उस सदन में था , तब मैं उन सारी कमेटियों का मैबर था जो मैबर्स के misconduct से संबंधित थी - चाहे वह ऑपरेशन चक्रव्यूह हो , चाहे वह ऑपरेशन दुर्योधन हो , चाहे कबूतरबाजी से संबंधित मामला हो या चाहे cash for vote वाला मामला हो - मैं इन सारी कमेटियों का मैबर था। कसि तरीके से , कत्तिनी जल्दी संसद सदस्यों की उस कमेटी ने और संसद के दोनों सदनों ने 13 सदस्यों को बर्खास्त किया - क्या कहीं इस तरह का उदाहरण मल्लि सकता है ?

कौम सा न्यायालय इतना बड़ा जजमेंट दे सकता था? कौम लोकपाल इतना बड़ा जजमेंट दे सकता है? उस संसद की खल्लि उड़ाई जाए, उस का मज़ाक उड़ाया जाए, यह ठीक नहीं है। महोदय, मुझसे पहले हमारे कई वद्वान साथी बोल चुके हैं। कल से रामलीला मैदान पर यह अनाउंस किया जा रहा है कि कल टीवी देखना और देखना कि कौम सा एमपी क्या बोल रहा है। उन्हें अहसास हो गया होगा कि भारत की संसद में कत्तिने वद्वान, कत्तिने जामकार और कत्तिने अच्छे वक्ता दोनों सदनों में हैं – इस बात का अहसास उन्हें हो जाना चाहिए। जसि तरह की तथ्यात्मक बातें यहां की गयीं, इन सब बातों का संज्ञान उनको लेना चाहिए। महोदय, स्थिति आज यह हो गयी है कि जसि देश में जाति और धर्म के नाम पर पोस्टिंग और ट्रांसफर होने लगे, मुकदमे लखे जाने लगे, चार्जशीट लगने लगे, acquittal and conviction होने लगे, स्कूलों में ऐडमिशन होने लगे – जसिका उल्लेख तबिरी जी ने किया था – उसमें यह आवश्यक हो गया है कि जो लोकपाल बलि की संस्था बने, जसिमें 11 सदस्य होंगे, उसमें माइनॉरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब तथा ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वरना इस वर्ग के लोगों के उत्पीड़न को कोई रोक नहीं सकता और लोगों को एक हंटर मलि जाएगा इनको दंडित करने का, इनको पीड़ित करने का और इनको परेशान करने का। जब भी लोकपाल बने, उसका फाइनल इस्पट बने, सरकार में बैठे हुए लोग जब इसको इस्पट करें, मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि उसमें मेरी रक्विस्ट का खयाल रखा जाए, मेरे सजेशन का खयाल रखा जाए। श्रीमन्, संसद देश की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, कलेक्टिव वलि संसद के द्वारा ही रफ्रिजेंट होती है। जैसा अभी श्री सुखेन्द्र शेखर राय ने अपनी स्पीच के अंत में टैगोर साहब को कोट करते हुए कहा था कि दबाव में आकर, आप संकोच में आकर, अपने अधिकारों का परित्याग करके दूसरों को अपना अधिकार दे दें, तो यह कसि तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ऐसा लग रहा है। मैं सत्ताधारी दल के लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। या तो आप इस मसले को पहले से ठीक तरह से डील कर लेते, लेकिन अब आप हड़बड़ी में हैं। कोई यह

कहे कि चासीस साल से लोकपाल बलि नहीं बना है, तो नहीं बना वह एक गलती थी, लेकिन एक गलती को सुधारने के लिये दूसरी गलती हड़बड़ी में और जल्दबाजी में आप करें तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ कदम मत उठाइए। अगर आजकसी दबाव में आकर फैसला लिया जा सकता है, एक लाख लोगों के दबाव में आकर फैसला लिया जा सकता है तो कल को एक करोड़ लोग भी दिल्ली में आ सकते हैं, जो यह कह सकते हैं कि ऐसा करिए, वरना हम यहां से नहीं हटेंगे। तब आप क्या करेंगे? पुलिस के सप्ताही पीटे जा रहे हैं, एम.पी.जे. को घेरा जा रहा है, वहां से निर्दिश दिया जा रहा है कि एम.पी.जे. के घरों पर जाइए। यह तब कथि जा रहा है जब हिंदुस्तान की संसद ने, खास तौर से लोक सभा में स्पीकर ने, प्रधान मंत्री ने, नेता सदन ने, नेता प्रतिपक्ष ने और पूरे सदन ने एक मत से यह अमील की कि जन लोकपाल बलि पर गंभीरतापूर्वक विचार कथि जाएगा, उसको वेटेज दिया जाएगा, अन्ना साहब, आप अपना अनशन तोड़ दो! पूरे देश के लोगों की इच्छा का सम्मान न हो, देश के प्रधान मंत्री, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष की प्रार्थना पर कोई गौर न कथि जाए और सिर्फ यह ही कथि जाए कि इतने दिनों में यह होना चाहिए, यह जदि जो है, बाल हठ तो मैंने सुनी थी, लेकिन यह वृद्ध हठ इस तरह का होगा, इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। यह नहीं होना चाहिए। मुझे एक संदेह है कि अन्ना हजारे साहब, शायद इस बात को मान भी लें लेकिन उनके साथ आसपास जो चौकड़ी है, उससे हमें ऐसा लगता है कि वह अन्ना हजारे की

जान लेने के लिए तुली हुई है। जब सदन व सरकार आपकी सारी जायज मांगों मानने के लिए तैयार है, फिर इस बात की ज़िद करना कि अनशन नहीं टूटेगा। ... (व्यवधान) ...

श्री राम कृपाल यादव : अन्ना हजारे के आसपास की जो टीम है उसमें से दो माननीय सदस्यों ने कहा है कि अब अन्ना जी को अनशन तोड़ देना चाहिए, अगर उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है। इस बारे में पी.एम., नेता प्रतिपक्ष तथा पूरे सदन ने भी अपील की है। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके द्वारा व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना होगा कि जो एक न्यायालय के जज रहे हैं, उन्होंने इससे खफा होकर कहा है कि अब मैं इस टीम का सदस्य नहीं हूँ। उनका यह बयान समाचार पत्रों में छपा है। उनके अंदर भी इस ज़िद से प्रभाव पड़ रहा है और अन्य लोगों पर भी असर पड़ रहा है तथा उनको यह लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को छद्म-भ्रम करने की कोशिश की जा रही है।

प्रो. राम गोपाल यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा था, उससे आगे कुछ और कहना चाहूँगा कि केवल लोकपाल बल्लि या जन लोकपाल बल्लि में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो छूट गई हैं। इसमें कुछ अनावश्यक हैं और कुछ जो होनी चाहिए थीं, वे हैं नहीं। इसमें जैसे सारे लोकसेवकों की जाँच का तो प्रॉविजन है, लेकिन जो एनजीओज़ हैं, उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वे सरकार से मदद पाते हों या न पाते हों। आज स्थिति यह है कि दवा लेने के लिए जाइए, तो नकली दवा मिलती है, दूध लेने को जाइए, तो नकली दूध मिलता है, कसिन खाद लेने के लिए जाता है, तो नकली खाद मिलती है, सब कुछ नकली है। ये सारी ज़िदें चीज़ें हैं, ये उसके अंदर आनी चाहिए। अगर कोई एम.एस. में दाखिला लेने के लिए जाए, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ में, रेडियोलॉजी में तो एक करोड़ रुपया मांगते हैं, अगर आप pediatrics में एम.डी. कराने के लिए किसी बच्चे का दाखिला कराना चाहते हैं, तो एक करोड़ रुपया मांगते हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज के प्रबंधन को भी इसमें लाना चाहिए, इनमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरे एक ज़िले की छोटी-मोटी ब्योरोक्रेसी और सब लोग मिलकर रश्चित नहीं लेते, उससे कहीं ज्यादा एक आदमी से रश्चित ली

जा रही है। अगर भ्रष्टाचार को मछिना है, तो इन सारी चीजों को लोकपाल के दाखरे में लाया पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया चुनाव के वक्त बेचा जाता है, इमेज बनाने के लिये हजारों करोड़ रुपये का पैकेज लया जाता है। यह चर्चा इस देश में है। अगर किसी को छींक आ जाए, तो वह भी टेलीविजन पर आ जाएगी और आप चाहे कुछ कहते रहिए कभी नहीं आएगा, आप कुछ दे ही नहीं सकते, यह स्थिति है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इसमें आना चाहिए। सारे कॉरपोरेट हाउस इसमें आने चाहिए।

जो तीन बातें हैं, उन पर हमारी पार्टी की स्पष्ट राय है। जो लोकायुक्त है, वह राज्य का मामला है। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल जाकर काम करें। हां, हम राज्यों से एक मॉडल लोकायुक्त बनाकर कह सकते हैं, राज्यों से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तरह का लोकायुक्त बने, लोकपाल की तर्ज पर। राज्य ही अपने मन से लोकपाल बनायें। सटीजन चार्टर पर हमें कोई ऐतराज नहीं है।

जो लोअर ब्यूरोक्रेसी वाली बात है सख्त रूप में इसमें कोई वरिध नहीं है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है, जैसा कि अभी येचुरी साहब ने इशारा किया था कि करोड़ों मुकदमे अभी लम्बित हैं और अगर नये केसेज आ जायेंगे, तो एक समानांतर पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पूरी पैरलल व्यवस्था

5.00 P.M.

बनानी पड़ेगी और जो समानांतर सरकार का प्रविजन यह जन लोकपाल बलि कर रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। उनकी जायज़ मांगों को मानिए और नया लोकपाल बलि, स्ट्रांग लोकपाल बलि बनाइए। अगर इसकी सारी चीज़ें मान ली जाएं, तो यह भस्मासुरी लोकपाल बन जाएगा। यह तो सारे सिस्टम को खत्म कर देने वाला है। सर, मैं आखिरी बात कहता हूँ हम सब एम.पीज़ यहां पर बैठे हैं, मान्यवर, आप भी एम.पी. हैं, एम.पी. के पास क्या अधिकार हैं? जन समस्याओं को सदन में उठाना, राज्य के हितों की बात को राज्य सभा में उठाना, विधायक में, कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तिता देना, यही हमारे काम हैं। हम न ट्रांसफर कर सकते हैं, न पोस्टिंग कर सकते हैं, न अप्वाइंटमेंट कर सकते हैं, न किसी को लाइसेंस दे सकते हैं, न किसी को कोटा-परमिट दे सकते हैं। जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे लोक सेवक हैं? हमारे पास कौन सी executive power है? जब कोई executive power नहीं है, तो MP को इस तरह के किसी भी दायरे में क्यों रखा जाए? हम इसका वसिध करते हैं और इसमें सुधार करना चाहिए।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, our country has been passing through a very turbulent period in its political life. Irrespective of political parties, whether we belong to Left or Right or Center, we all, collectively, will have to address certain basic issues. Dr. Ambedkar is being quoted frequently in this House. Dr. Ambedkar, in his last historic speech in the Constituent Assembly, in the month of November, 1949 made certain observations. "Till 1947, we were blaming British for everything that went wrong in the country. But after 1947, we cannot go on blaming British. If something goes wrong, we will have to blame ourselves." That is what Dr. Ambedkar said. Then, Dr. Ambedkar went on to say, "On 26th January, 1950, our country will enter into a new life but that new life will be a life of contradictions. In politics, we will have equality — one man, one vote. But in social, cultural and economic life, we will have inequalities. How far we resolve these contradictions or how sooner we resolve these contradictions, it is good for our democracy. If we failed to resolve these contradictions, then, our democracy will be in

peril. If at all our political democracy has to last, there should be social democracy and economic democracy at its feet.” This was what Dr. Ambedkar said.

Now let us introspect what went wrong after we became the Republic. India, which started as a welfare State, has, gradually, been emerging as a neo-liberal State. There is always a demand that State must withdraw from all economic activities. State must withdraw from running industries, from building physical infrastructure and social infrastructure, like, health and education. So, States should not have any role in economic activities, as far as distribution of wealth is concerned. Why is it happening? Now, we find enormous growth of corporate houses. These corporate houses dictate the formation of the Government. They dictate the policies of the Government. These corporate houses are also influencing the policies of the Government, manipulating the policies of the Government and resorting to all corrupt practices. That is what

we witness today. Small crimes or small bribes which used to be in the past was a different thing. Now, what we see today are scams involving mind-boggling and alarming figures. This is because the corporate sector, the corporate houses are directly trying to control the Government. Now, again, we are discussing corruption today. It is not one man's cause or one party's cause. It is the entire nation's cause to fight corruption. But how to fight corruption? How to fight corruption? From 1968 onwards, efforts were made to bring a Lokpal. The first Lokpal was Lokpal and Lokayuktas Bill, 1968; the second Bill was also Lokpal and Lokayuktas Bill, 1974. Afterwards, it was Lokpal Bill, 1977; Lokpal Bill, 1989; Lokpal Bill, 1996; Lokpal Bill, 1998; Lokpal Bill, 2001; and now, in 2011 also, we are discussing about a Lokpal.

Sir, an all-party meeting was held on 24th August, 2011. My Party was also present there. This all-party meeting unanimously made an appeal to Mr. Anna Hazare to end his fast. In that all-party meeting, my Party made some suggestions and we said, 'the present Bill is very weak and inadequate; we need a strong Lokpal and the Government will have to work on a strong Lokpal.' While working on a new Bill, the Government can take inputs from various quarters. Government can take inputs from Anna and his colleagues; Government can take inputs from Aruna Roy and her colleagues; and Government can take inputs from various other sections which have worked on this Lokpal.

SHRI MOHAN SINGH (Uttar Pradesh): From Mr. Seshan.

SHRI D. RAJA: From anybody, and political parties do have ...

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: Also from Jaiprakash Loksatta.

SHRI D. RAJA: Yes, from Jaiprakash Loksatta as well. But it doesn't mean that only they have their views on Lokpal. As political parties, we have our own points and the Government must take all these points and it should work on a new Bill. This is what we suggested. Now, Sir, as a Party, we have our views. While demanding a strong Lokpal, we think, the Prime Minister, can also be brought within the ambit of Lokpal. We don't see anything wrong in including the Prime Minister

within the ambit of Lokpal. What is wrong in it? Why should we shy away from including Prime Minister within the ambit of Lokpal? And, we are for that.

Then, Sir, with regard to Judiciary, we did express our views when we discussed the Impeachment Motion. It is true that the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 is pending; but it is also a weak Bill. It needs to be strengthened. Along with it, the Government should agree to constitute a National Judicial Commission. Now, 'Judges appointing Judges' leads to corruption, nepotism and there are cases of one Judge appointing his own relatives as

Judges in several High Courts. We could see it. Judicial Accountability is a must today and we need a corruption-free independent Judiciary. We have respect for our Judiciary but that Judiciary should be free from corruption. That Judiciary should also be made accountable. This is our position.

Then, Sir, with regard to MPs, many leaders have made their position clear. I agree with them. The conduct of MPs, the elected Members, within the House are governed by certain rules, and for whatever they do outside Parliament – they are public servants, they are citizens – all your Criminal Procedure Code, Indian Penal Code can be applied to them also and they are applied. Even now, they are applied. That is our position.

Now, Sir, with regard to Lokayuktas, even though our Constitution says, we are unitary, but, in practice, we are a federal country. We function on the basis of federal principles and one should not think of imposing certain things on States. We can think of a model Bill or some kind of an enabling law which can give some kind of clarity to the States to act on their own. This is our position.

Now, I come to the composition of Lokpal, Sir. This composition will have to be defined. It cannot be a mechanical one which is out of touch with the social reality of our country. After all, the Indian society is a complex society. We have, whether we like it or not, a caste hierarchy. We may talk about inclusive growth. When we talk about our economy, we say India is an emerging and a fast growing economy, India is emerging as an inclusive economy. But it is not so in reality. That is why when we talk about the composition of the Lokpal, I think it has to reflect the social inclusiveness there; it has to have representation from SCs/STs, backward classes, women and minorities. We passed the Bill for 33 per cent reservation for women in this House. In panchayati raj, you have a reservation to the extent of 50 per cent. The atrocities committed against women are immense, atrocities not only like sexual assaults, even in terms of other aspects of social life. I think women and minorities must also be represented. Only then, people will have some confidence in the institution of Lokpal. People will look at it as an institution which

can deliver fair justice to every section of the society. Otherwise, what is happening today? People do not have confidence even in, I am sorry to say this, the judiciary because they think that the judiciary can be biased in a given situation. That is where we talk about judicial accountability. This is one aspect the Government will have to keep in mind.

Then, I come to the definition of 'corruption'. How do you define 'corruption'? When it comes to Government's functions, how do you define diversion of funds meant for SC component Plan, diversion of funds meant for Tribal Sub-Plan. If you ask me that is also corruption. There are organizations who strongly believe that diversion of funds earmarked or

meant for SC Component Plan to some other activities to benefit some groups and families, is corruption. So, how do you define corruption? There, the Government will have to apply its mind. This is one thing we will have to keep in mind.

With regard to these three questions, these three questions were raised by Shri Anna Hazare and his team. I do not know how Government negotiates with Shri Hazare and his team. Government can negotiate directly with Shri Anna Hazare. Why do you have these interlocutors? I do not know it has become a fashion with the present Government that for everything you go in for interlocutors or mediators. Why can't you negotiate directly? On these three issues, they demanded in writing and you are asking Members of Parliament to give their opinion and Mr. Pranab Mukherjee says that we will be a part of consensus-making, not consensus-breaking. What is your position? Why should the Government handle this issue in this manner? This is something the Government should take into consideration.

Then, Sir, there are some other issues. One is the Standing Committee. Now, the time has come when we will have to really look at the functioning of Standing Committees. The Standing Committees submit their reports and their observations and views are given by them. They are all recommendations. And the recommendations are not mandatory. But we claim that Standing Committees are mini-Parliaments. But the Standing Committees' opinions are recommendatory, just recommendatory! It is not only with Standing Committees, it is also happening in case of the National Commission on Scheduled Castes, National Commission on Backward Classes, National Tribal Commission and in all Commissions. We interacted with them. What they say and whatever we say, they are all just recommendations. Government does not simply agree and our recommendations are thrown to the dustbin. So, I think, when we discuss Lokpal, we need to discuss the question of functioning of Standing Committees also.

Now I come to the functioning of law. How is the law functioning in our country? We should look at the functioning of law. My hon. friend, Shri Tiruchi Siva, raised one concrete issue. People who have been given death sentence spent their 20 years in prison and now the

sentence is going to be executed. How it is justified? Even a life imprisonment is carried out with a particular time limit of 14 years. But in a death sentence, the convict passed 21 years in prison but the sentence is not commuted. How is our law functioning? He mentioned concretely three names – Perarivalan and two others. Even Mr. Vayalar Ravi had got into an issue. But I am not entering into the case. I am questioning the functioning of law in our country. How does our law function in our country? We will have to keep this in mind. Otherwise how is your Lokpal, that you are creating, is going to function? I did meet some of the representatives. I asked them what will be the establishment of Lokpal. They said, they will draw some personnel from anti-corruption wing of CBI, some personnel from vigilance wing of different Departments. Then

Lokpal will have its own establishment. I am telling you. Then I asked, how are you going to recruit people for Lokpal. Finally, Lokpal is going to be an institution. Here again, I bring the warning given by Dr. Ambedkar. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Dr. Ambedkar gave the warning while discussing in the Constituent Assembly as to what should be the democratic system that India should adopt - whether multi-party parliamentary democratic system, or, a presidential form of Government. Dr. Ambedkar rejected the presidential form of Government; he also rejected two-party system. Dr. Ambedkar opted for multi-party democratic system. There Dr. Ambedkar gave justification. He said, in *bhakti* or in religion you can lay all your liberties at the feet of one individual; you can think that you will have salvation and you will go to the heaven. But, in politics, if you put your liberties at the feet of one man, then it will lead to dictatorship and autocracy. Now what is happening in India? It is a kind of anarchy that is emerging. Such a situation is very bad and political parties will have to apply their heads and their minds together in order to overcome this crisis because this is a crisis in which many European countries plunged in. We have seen many countries plunging into crisis because of corruption. We saw Japan plunging into crisis because of corruption. India is also plunging into crisis because of corruption. This has to be fought provided the Parliament has the political will. We should carry on this fight against corruption.

With these words, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Members, I have to share the Chair's problem with you. There are twenty-two more speakers.

DR. V. MAITREYAN: Sir, this problem arises only with smaller parties!

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): First let me say. You have to listen to me first. There are twenty-two more speakers. So far, we are following a procedure that every speaker is allowed to the extent he wants to speak. I have no problem. But, we will have to sit late, maybe up to 12.00 at night or even beyond that. I have no problem, but if there is consensus, I can say that each Member may go a little beyond the time allotted to his party, say five minutes more than the allotted time.

श्री रामविलास पासवान : सर, यह बहुत ही historic debate है बाहर जो कुछ हो रहा है, हम लोग सुन रहे हैं आपसभी मैम्बर्स को अपना view रखने दीजिए, वह कम-से-कम रिकॉर्ड पर तो जाएगा। इसे कसिने

लोग सुनेंगे , नहीं सुनेंगे , यह अलग बात है। लेकिन , रिकॉर्ड पर सबका view जाएगा , इसलिए आपटाइम की कोई पाबंदी मत लगाइए , चाहे इसमें रात के बारह बजे या 2 बज जाएँ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो . पी.जे. कुरियन): मैं आपसे सहमत हूँ ... (व्यवधान)... मैं आपसे सहमत हूँ I have no problem. I only shared my concern. However, I am requesting hon. Members to exercise self-restraint, like you can go five minutes beyond your allotted time or even double the time, but not more than that. Now, hon. Members are taking so much time. So, please co-operate. Now, Shri Paul Manoj Pandian.

SHRI PAUL MANOJ PANDIAN (Tamil Nadu): Sir, due to paucity of time, as you expressed just now, I would also impose self-restraint with regard to the views that I am going to express and I will also be very brief with regard to whatever I am saying. In the backdrop of 2G scam and the various scams which were detected very recently, it has now become the need of the hour to discuss about a Bill like the Lokpal Bill. It was the endeavour of my leader, the Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalithaaji, who had exposed this scientific corruption to the entire world in the 2G scam.

Now, with regard to the Bill, I would like to submit my views which can be taken note of by the Standing Committee about how and what are the changes, what are the amendments and what are the views that have to be imbibed in order to give an effective and comprehensive Bill to curb the menace of corruption in our society. At the outset, I would like to highlight the point regarding the establishment of an organisation like the Lokpal. If it has to be established, we have to see how it has to be in consonance with the legal provisions of various Acts, and mostly, with the provisions of the Constitution. Sir, though it is a Constitutional right of an individual, civil society or anybody, for that matter, to express their views, but, ultimately any person, who has to redress his grievances, who has to raise a voice, the expression of his views has to come to this august House and this august House will have the authority, after

deliberating all the issues, to establish the supremacy of this House. It is only after going through this process that any law is enacted by this House. Sir, with regard to the Lokpal Bill, I wish to draw the attention of the Members, as well as the Standing Committee, regarding the matters that are pending in the Courts. For instance, if a complaint is given to a vigilance authority or an investigating officer and thereafter, a police charge-sheet is filed and it is sent to a Special Court, as it comes under the Prevention of Corruption Act, Sir, the provision, as I was able to have a glance with regard to the Government's proposed Bill, it says that matters pending before any Court, Committee or authority for inquiry before Lokpal are not to be affected. And, the explanation is also given. For the removal of doubts, it is declared that continuance of such matter or proceeding in any Court

shall not affect the power of the Lokpal to enquire into any matter under this Act. Sir, can a person who is charged of an offence before a court of law, be subject to another proceeding before the Lokpal? It has to be taken note of by the Standing Committee. Can there be two simultaneous prosecutions, one before the special court under the Prevention of Corruption Act, and, the other before the Lokpal? Ultimately, a person is being tried twice, which is the violation of Constitutional provision enshrined under article 20. This has to be taken note of, Sir.

Sir, with regard to three questions that have been posed, I wish to submit the view of my party. Sir, our leader, Dr. Jayalalitha ji has already expressed her view with regard to the inclusion of the Prime Minister within the ambit of Lokpal. Sir, the AIADMK party is of the firm view that the Prime Minister should be out of the purview of the Lokpal. The reason is that if frivolous complaints are filed against the Prime Minister, it will undermine the authority of the Prime Minister. Once a complaint is filed, it will be telecast on the news channels, and, thereafter, no Prime Minister would be able to function. It will definitely affect the authority and administration of the Government. Not only that, the Prime Minister is already under the purview of the Prevention of Corruption Act. If the Prime Minister is going to commit any wrong or indulges in corruption, he will be prosecuted under the Prevention of Corruption Act. It is not as if he is having a Constitutional protection like the one which is given to the hon. President or Governor of a State under article 361. There is no protection for the Prime Minister; there is no protection for the Chief Minister of a State. That is why, Sir, my view is that the Prime Minister, who is under the purview of the Prevention of Corruption Act, need not be brought under the purview of the Lokpal.

Sir, with regard to establishment of Lokayukta, since the establishment and appointment of Lokayukta is a State subject, it must be left to the State and the respective State Government. The State Government could set up Lokayukta on the basis of whatever is being expressed here and also taking note of the relevant factors and all legal provisions.

Sir, with regard to inclusion of lower bureaucracy within the purview of Lokpal, an attempt has been made to include lower bureaucracy within the ambit of Lokpal but it would only be counter productive. The main focus of the Lokpal Bill is to punish the corrupt persons at the top level. If there is going to be a number of cases filed before the Lokpal, there is going to be no end, there is going to be no decision, there is going to be no prosecution, and, ultimately, the whole exercise will prove futile.

Sir, with regard to the powers of the Lokpal, I wish to submit certain views. Even according to the Government Bill, the Lokpal has the police powers with regard to seizure, arrest and investigation. If the Lokpal has the power with regard to arrest, then, where is the person going

to be remanded? Is he going to be remanded before a Magistrate? He cannot be remanded before a Magistrate. Does the Bill give the powers to remand before the Lokpal? It is not provided. This lacuna with regard to the arrest has to be addressed.

Not only that, Sir, in the proposed Bill, there is a mention of the preliminary investigation and final investigation. Sir, there is no expression of preliminary investigation in any provision. It has been done away with. The use of word 'preliminary investigation' has been done away after the pernicious practice of conducting preliminary investigation by filing incomplete chargesheets within 15 days under the old CrPC. It is not there now. It is not there under the present criminal jurisprudence. Therefore, I want to submit that there are a number of lacunas in the proposed Bill and also in the other Bills which have been brought forward by the civil society. All these have to be taken into consideration, all views have to be expressed, all views have to be taken note of, and, then, we can pass a comprehensive Bill.

Sir, coming to the last point with regard to filing of complaints, I would like to submit that there are so many technical issues. If a complaint is given by the Lokpal, as I have seen from the proposed Government Bill, it has to be through the Director of Prosecution. That is, by way of a complaint, it will go directly to the special court. Sir, if there is a police case already pending in that particular court, after the complaint is presented by the Lokpal, the complaint given by the Lokpal will be automatically stayed because of the provisions of section 210 of the CrPC. We must take note of this fact. If a complaint is going to be given by the Lokpal, and another complaint is already pending with regard to a police charge sheet, then, once the complaint is filed before the Special Court, the complaint of the Lokpal will be automatically stayed. This is the provision of section 210 of CrPC. There are so many technical flaws. I know there is time constraint, Sir. However, there are a number of flaws which have to be corrected. A lot of deliberation is necessary; a comprehensive Bill is necessary. Therefore, I appeal to this august

House to take note of all legal implications, to take note of all constitutional implications, to take note of all legal provisions, all the Acts, be it the Criminal Procedure Code or the Prevention of Corruption Act. Then, there is no mention about the Central Vigilance Commission in the proposed Lokpal Bill. The Central Vigilance Commission was enacted by a judgement of the Supreme Court. There is no reference about the Central Vigilance Commission.

Sir, with regard to the Judges to be brought within the purview of this Act, the Standing Committee must take note of the fact that for initiating any criminal action against a Judge, permission of the Chief Justice is necessary. It is by virtue of a judgement of the Supreme Court. So, these things have to be taken note of. We cannot pass a Bill, enact it, and then if it is struck

down as unconstitutional, we will be doing injustice to the people. (Time-bell rings) Therefore, I appeal to this august House to take note of all legal issues while framing this comprehensive Bill with regard to the Lokpal. Thank you, Sir.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA (Nominated): Thank you, Sir. Over the past few weeks and days, we have seen a very natural public outpouring against a long pending issue of corruption.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJEEV SHUKLA): Sir, there is a Resolution which will be brought after the debate is over and 22 more Speakers are still left. So, I think, there should be some time limit fixed. The issue could also be resolved outside. I think, there should be some time limit fixed.

श्री राजनीति प्रसाद : जब यह पहले तय हो गया। ... (व्यवधान) ...

श्री राजीव शुक्ल : देखिए , आप यह समझिए कि अभी 22 speakers हैं। ... (व्यवधान) ... अभी Resolution भी आना है। एक आदमी , जो भूखा बैठा है और यहाँ 11 बज जाएँगे , इसलिए आप थोड़ा इसको समझिए और इसके लिये कोई समय-सीमा हो जाने दीजिए। मेरा मुख्य वक्ता दल से भी आग्रह है कि वे भी इस बात को कहें।

श्रीमती माया सहि (मध्य प्रदेश) : सर, speakers बहुत ज्यादा हैं , क्योंकि 'Others' में आपके पास already 12 speakers हैं। अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के speakers भी अभी बाकी हैं। मुझे लगता है कि यह डबिट जब तक खत्म होगी , तब तक 9 या 10 बज जाएँगे। क्या इतनी देर तक सब लोग यहाँ बैठेंगे ? ... (व्यवधान) ...

कुछ माननीय सदस्य : हाँ , हाँ , बैठेंगे। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती माया सहि : इस बारे में सदन की भावना क्या है ? इसलिए मैं चेयर से यह आग्रह करती हूँ कि आप टाइम -लिमिट कर दीजिए , उससे सारे speakers को अपनी बात कहने का मौका मिले जाएगा और हमारी यह डबिट भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद मनिस्टर की reply है। ... (व्यवधान) ...

श्री राजनीति प्रसाद : सर, हम लोग 9 बजे तक भी

बैठेंगे। ... (व्यवधान) ...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Let the Congress Party and the BJP withdraw all their speakers. ... (Interruptions) ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't worry. ... (Interruptions) ... You will get time. You allow me to speak. ... (Interruptions) ... If all of you speak together, what can I do? ... (Interruptions) ... Please speak one by one. ... (Interruptions) ...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I have a point, Sir. Today, in the presence of the hon. Chairman, this matter was discussed and everyone categorically requested to speak.

...(Interruptions)... There should be a free and frank discussion. Secondly, Sir, all the time, small parties cannot be deprived of the opportunity to speak. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please sit down Mr. Baishya. ...(Interruptions)... I heard you. ...(Interruptions)... I heard the point made by you.

श्री राजीव शुक्ल : लोक सभा में डबिट खत्म हो गयी और वहाँ Resolution भी पारित हो गया , फरि यहाँ चलते रहने से फायदा क्या है ? इसलिए हमें समयसीमा में रहना चाहिए। ... (व्यवधान)...

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : लोक सभा में क्या समयसीमा तय हुई है ? ... (व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल : लोक सभा में साढ़े छः बजे का समय तय हुआ है। ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I understand and appreciate the feelings of the Members, especially of the Members from small parties and those who are in the category of Others. You have a point. You want to make your point. But what the hon. Minister has said must also be considered. When discussion in the Lok Sabha will be over, they will have the Resolution and that will go to the media and we will become redundant. That is also there. ...(Interruptions)... Let me say this. ...(Interruptions)... Please. We should have a compromise on both. The category of Others has 12 speakers. According to the time allotted by the Chairman, which is 43 minutes, each Member will get four minutes. ...(Interruptions)... Instead of four minutes, you take five-seven minutes. But not more than seven minutes. I think it is justified. ...(Interruptions)...

श्री रामविलास पासवान : अगर यह कहना है तो हम लोग हाउस छोड़कर चल देंगे ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will decide. ...(Interruptions)... Please sit down. I think the major parties can reduce their share of time. Isn't it? ...(Interruptions)...

श्रीमती माया सहि : सर, हमारे दो स्पीकर्स हैं और जो

हमारा टाइम है, वे उस टाइम को लेंगे। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We can do that within that time. ... (Interruptions) ... बैश्य जी, आप बैठिए। ... (Interruptions) ... Listen to me. Among the major parties, I think the Congress Party has got nearly one hour and four speakers. I will request their Members to take ten minutes each. Nobody will take more than ten minutes whether major parties or small parties. ... (Interruptions) ...

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): It does not happen like that. ... (Interruptions) ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will manage like that. ... (Interruptions) ...

DR. BHARATKUMAR RAUT: First it should be small parties.
...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That cannot be done.
...(Interruptions)... I cannot violate the Rules.
...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... From the category of Others, each speaker will get only four minutes. But I said I would give you up to ten minutes. I am reducing the time allotted to major parties. Their Member will speak up to ten minutes.
...(Interruptions)... Nobody will speak for more than ten minutes whether it is a major party or a small party. ...(Interruptions)... I have given the Ruling. ...(Interruptions)... Consensus लयिा , रूलिंग दयिा that nobody will speak for more than ten minutes. It means you speak for ten minutes. ...(Interruptions)...

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSYAYAN (Nominated): Sir, can the mute wisdom bench get five minutes?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I said a Member can speak up to ten minutes. If you conclude within five minutes, I will be very happy.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, I will try to make you happy.

Sir, over the past few weeks, we have seen a genuine popular agitation against the long-standing scourge of corruption. The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, had termed it as a cancer that was gnawing at and eating into the vitals and values of our nation. I think that there is a national consensus on it. The need of the hour is that Parliament brings in a strong Bill to try and tackle this menace.

Sir, the current events pertaining to the various scams and scandals that have been tumbling out also point to the fact that we need a very strong anti-corruption law and, more importantly, we need to have the political will to implement that in a firm manner.

Sir, to tackle this statutory corruption, an independent body is

necessary and the model of the Ombudsman or the Lokpal that we have devised has been overwhelmingly agreed upon as a practical and effective force to uphold a law that not only provides a *de jure* deterrence for corruption but also a *de facto* deterrence. We need an effective Lokpal. But we also need an effective Lokpal fitted with strong safeguards against its possible misuse. When we centralise so much of power and we have a body without much decentralisation, it is very important to have in place checks and balances to ensure that it cannot be misused. It is also important for us to understand that even the most stringent and even the most effective Lokpal will not be and cannot be a panacea for all corruption. Sir, the Lokpal ambit is to lie only over the statutory bodies, whether it is Members of Parliament or judiciary or bureaucracy. This excludes vast

areas of public life where corruption is rife and where the common man specially falls prey on a daily basis, whether it is corruption to try to go in for procurement of commodities, whether it is school admission or whether it is corruption at the corporate level or, as my friends spoke about, whether it is corruption at the media level. Sir, I belong to media, but, I have no hesitation in saying that we need to weed out corruption at each and every level in all the spheres of activity. Sir, for all these areas where graft has thrived, far more changes and implementation of stricter laws are required. Then, Sir, last but not the least, a change in the social behaviour in society has to take place. Constitution of a strong Lokpal with proper safeguards, I am sure, will be a beginning in the right direction.

Sir, now, I come to some of the substantive issues which have been covered and discussed today. Sir, I respectfully like to state that I think the office of the Prime Minister needs to be brought under the ambit of Lokpal. Sir, incumbent Prime Ministers should be under its purview if we have to send a signal that this is a strong anti-corruption Bill that has been proposed. Keeping the Prime Minister out may send a wrong signal. But, I do believe that it should be a qualified inclusion and, therefore, there should not be day-to-day irritants that actually hamper the functioning of the office of the Prime Minister. Also, Sir, I think, the areas of national security, foreign policy and defence need to be kept firmly out of the purview of any investigation by the Lokpal. Even the current laws of the country do not provide any immunity to the Prime Minister. He is first amongst equals. So, the Prevention of Corruption Act applies equally to the Prime Minister. So, there is little meaning in trying to keep him out of this.

Sir, as far as judiciary is concerned, they should not be under the Lokpal but the Government must acknowledge the fact that there is corruption in judiciary, and therefore, a strong Judicial Standards and Accountability Bill should be passed at the earliest. I know this Bill has been pending, but, Sir, this Bill does not cover all aspects.

A Judge today can only be impeached under Article 124(4) and Article 217 and no other mechanism is available other than an extraordinary constitutional method under practice of Judges inquiring into the Judges' conduct. How can this ever be impartial, how can this ever be transparent and how can this ever be termed fair? So, I think, we should move towards a National Judicial Commission which can be enacted by amending the Constitution.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Sir, as far as lower bureaucracy is concerned, I think, the idea of trying to cover the entire civil servants is a worthy idea. But, we have to look at the practicality of actually rolling out

something as momentous as this. We have over three crore people that are to be covered. I think, the efficacy of the Lokpal itself will be under slight tension and strain if it has to oversee the functioning of so many people. Therefore, Sir, I think, while the higher bureaucracy should be kept under the ambit of the Lokpal, the lower bureaucracy should be overseen by the CVC.

Sir, as far as citizens' charter is concerned, inefficient delivery of services can be because of corruption but may not necessarily be only because of corruption. It could be because of the slackness of the system; it could be because of a host of other reasons. Sir, to give you an example, if a Block Officer does not send details of his annual expenditure to the District Officer, he cannot have the money to spend even if the District Officer has been sanctioned the money that is actually to be sent to the Block Officer. So, we have many methods and processes that we follow. There is a general slackness in the system and very often, the work does not get done because there isn't money to disburse not necessarily because of corruption but also because the system is very lethargic. Therefore, Sir, I believe that there should be a separate legislation which should take care of inefficient delivery of services and this should not form part of the current proposed draft Lokpal Bill.

Sir, as far as CBI is concerned, I most certainly believe that the CBI, which has often been accused of political interference not by one particular party but by all parties at some point or the other, should be made independent. At least the Anti-Corruption and the Investigative Wing of CBI should be protected and have a buffer between the Executive and the CBI. Sir, even the Crown Prosecution Services in the United Kingdom, for instance, worked outside the domain of the Executive. If you want to have credibility in the actions that you are taking, we need to ensure that the agency which is investigating has to be insulated from the Executive. Therefore, it is high time that such investigative agencies must be independent. This is like keeping with other democracies in the world.

Then, we come to the issue of can there be a single Bill for setting up the Lok Pal at the Centre and the Lok Ayuktas in the

States. It is a matter where the federal polity does not allow us today to legislate for the State. But what can be done because we believe in the principle that there should be a strong Lok Pal at the Centre and Lok Ayukta at the State. The Centre should try and form a model Lok Ayukta Bill. They should try and advocate the features and get a few States to follow that. From then on it can become the model Bill to be followed and the Centre can help with strong advocacy to try and seek that the States do adhere to it. Having said that, it is not something that can be covered under the purview of the existing Bill, because it will damage the federal polity.

Sir, these are all important issues and I think there are parts in every Bill whether it is part of the Jan Lok Pal Bill, whether it is part of the Government's Lok Pal Bill or it is part of the civil society Bill that are doing rounds. I think the need of the hour is for the Parliament to discuss and debate the various clauses. We have waited since 1968, we can wait a little longer. I do not think the pressures of Ram Lila maidan should actually be hanging over our head in terms of decision making and discharging our responsibilities to the best of our ability. I think we have taken so many years, we should discuss and debate every clause and make sure that the new Lok Pal Bill that will come eventually out of the Standing Committee is a Bill that will serve us for centuries to come. Thank you.

MR DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rajeev Chandrasekhar. Not here. Next, Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on issues relating to setting up of a Lok Pal. I am very glad to participate in this historic discussion. Before I give my opinion and my party's opinion on today's discussion, we must salute Annaji for his nonviolence movement which united the entire nation from Assam to Kerala and from Kashmir to Kanyakumari. For the last 45 years we have been discussing about the Lok Pal in our country. After the recommendation of the Electoral Reforms Commission, in the year 1996, the matter of Lok Pal was discussed in Parliament. In 1968, for the first time, the Indian Parliament had passed the Bill. Again after that on many occasions discussion on the Lok Pal came up before Parliament. But still we do not have an effective and strong Lok Pal in our country. The Common Minimum Programme of the United Front Government was drafted in the year 1996... One of the major agenda items under the Common Minimum Programme of the United Front was that Prime Minister should be brought under the purview of Lokpal. Sir, in democracy, public opinion played strongest Role. The non-violence movement has also brought very, very significant rules in our country. Today, again, in our country, this is going to be established after a call being given by

Annaji against corruption; the country is united and a strong public opinion has emerged in the country. On the basis of that, we are discussing it today. Saturday is generally a holiday for us, but we are discussing this issue as a matter of urgency. This is the need of the hour. So, we are discussing about the Lokpal.

Sir, my party, Asom Gana Parishad, from the very beginning, is supporting the movement led by Annaji. Not only that; in the two all-party meeting, which was convened by the hon. Prime Minister, AGP also participated and by supporting the Jan Lokpal, we have given our favourable opinion. We have supported the movement, Sir.

Now, I am coming to the main point of today's discussion; that relates to the Prime Minister. Sir, Prime Minister should be brought under the purview of Lokpal; there is no doubt about that. It was supported by most of the political parties. Secondly, Asom Gana Parishad is also in favour of having a strong Lokpal in the Centre, and, simultaneously, a strong Lokayukta in the State Legislature.

Regarding Judiciary, our opinion is quite clear, Sir. There should be, there must be accountability, towards the Judiciary also. My party is in favour, and I am personally in favour, of having a Judicial Commission. So, we are totally supporting it. Instead of bringing any law, my party is supporting the formation of a Judicial Commission.

I am now going to tell you, Sir, what is our opinion about the Members of Parliament. We are public representatives. Our opinion is quite clear that all corruption related issues of Members of Parliament should be brought under the purview of Lokpal. This we are also supporting, Sir. All corruption-related issues of Members of Parliament should be brought under the purview of the Lokpal.

Now, I am coming to the three demands. I am going to discuss about the three demands which are given by Annaji and his team, Sir. Number one; public grievances....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only three minutes are left.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: No, Sir. At least, today, you can relax the time limit, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, no. The House has to finish. ...*(Interruptions)*... Please listen. The House has to come to the conclusion that everybody be given ten minutes.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, I have still time. Allow me to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have just reminded you.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, allow me to speak.

As regards Public Grievances and Citizen's Charter, this is one of the very important demands raised by the Civil Society. We are in favour of it. The responsibility of the officials should be fixed.

Without fixing the responsibility of the officials, it is very difficult to get the work done by any officer in our country. So, we are supporting this demand of Annaji.

Sir, I have already mentioned that we are in favour of a strong Lokpal at the Centre and, at the same time, we are supporting a strong Lokayukta in the State.

Sir, the third demand is about bringing the lower bureaucracy under the Lokpal. This is a very important point. The common people and the poor people of our country always get

harassed at the lower level. To get a ration card or a passport the common people face harassment like anything. It is very unfortunate that in our country to get a death certificate or a municipal certificate or some registration done, people have to pay money, people have to bribe the officials. It is necessary that there should be control on the lower bureaucracy also. So, we support this demand that the lower bureaucracy should also be brought under the purview of the Lokpal.

Sir, today, the entire nation is looking at us. *(Time-bell rings)*
Give me one minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shanta Kumar. ...*(Interruptions)*... Your time is over, Mr. Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, just one minute. Today, the country is moving towards a historic moment. The entire nation is looking at us. So, I request all Members of this House to pass a resolution today supporting Annaji's demand. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shanta Kumar.

DR. BHARATKUMAR RAUT: Sir, I have a suggestion to make. I have to make only one suggestion and nothing else. When Mr. Kurien was in the Chair, we had suggested that because of paucity of time one round of all political parties should be completed first. Since there is paucity of time, give a chance to all other party Members to speak and then start the second round.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Has that been agreed to by the House?

SOME HON. MEMBERS: No.

DR. BHARATKUMAR RAUT: Otherwise, what happens is...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. There are other parties. ...*(Interruptions)*... I have called Shri Shanta Kumar. ...*(Interruptions)*... They know about their time. ...*(Interruptions)*...

DR. BHARATKUMAR RAUT: The bigger parties have already exhausted their time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We can discuss it later. But now I have called him. ...(*Interruptions*)...

श्री शान्ता कुमार (हमिचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, आज देश इतिहास के एक वक़्त मोड़ पर खड़ा है और हमारी तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं। हमारा आजका और आने वाले कुछ दलों का नज़रिया, इस देश के भविष्य को एक नई दशा देगा। आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के वृद्धि गुरुसा चरम सीमा पर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज पूरा देश सड़कों पर आ गया है और देश की जवानी भी सड़कों पर आ गई है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण पछिले कुछ वर्षों का इतिहास, पछिले कुछ

वर्षों की परिस्थितियां हैं। इनके कारण प्रत्येक व्यक्ति त्रस्त है, परेशान है और दुखी है। वह इसका कोई समाधान चाहता है। देश आजाद हो गया, जी.डी.पी. बढ़ रहा है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। आजस्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती हुई खाई आर्थिक वषमता पैदा कर रही है। राष्ट्र संघ की रफ़ोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग हबिदुस्तान में रहते हैं। गरीबी बढ़ रही है, अमीरी भी बढ़ रही है। देश के अंदर यह जो आर्थिक वषमता बढ़ रही है उससे गरीबी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, जिसके कारण आमआदमी दबि-प्रतिदिन परेशान होता चला गया। इससे एक और बात पता लग गई कि गरीबी, वषमता, परेशानी, महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। एक और मैसेज चला गया कि आजकी व्यवस्था भ्रष्टाचार को खत्म करने में ईमानदार नहीं है, इसलिए आज पूरे देश में एक भयंकर असंतोष है। मैं यह नखिदन करना चाहता हूँ कि आजसदन को, संसद को यह एक बहुत बढ़िया मौका मिला है कि यह जो एक वश्वास का संकट पूरे देश में पैदा हो गया लोकपाल बलि पास करें, भ्रष्टाचार खत्म करने में पहल करें, यह बहुत आवश्यक है, लेकिन सबसे आवश्यक यह है कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर जो अविश्वास पैदा हो गया है, नेताओं के प्रति पार्टियों के प्रति लोगों के क्या वधिार आए हैं, मैं उस पर सबसे जरूरी यह समझता हूँ कि हमको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। यह जो एक crisis of confidence, Political System के बारे में पैदा हो गया है, इस कस्मि का आंदोलन सन् 75 में भी पैदा हुआ था, तब उसका नेतृत्व राजनीति कर रही थी। यह आजभी हो रहा है, लेकिन राजनीति कहीं नजर नहीं आ रही है। इस फर्क को देखना चाहिए। राजनीति पर से लोगों का वश्वास उठ रहा है। राजनीति irrelevant होती चली जा रही है। इसमें आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति पर, राजनैतिक व्यवस्था पर जो अविश्वास बढ़ रहा है, उसे बहाल कथिा जाए और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था पर अविश्वास को बहाल करने का एक सुनहरी मौका है, हमको जिसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि, भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार कुछ लोगों को बहुत अमीर बना देता है, कुछ लोगों को लूटने का लाइसेंस दे देता है। भ्रष्टाचार कुछ लोगों को बहुत गरीब बना देता है, जिसके

कारण आर्थिक वशिमता बढ़ती है, आर्थिक वशिमता बढ़ती है तो अपराध बढ़ता है और उसके साथ-साथ नक्सलवाद बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण यही है। योजना आयोग ने जो Expert Group बठि या था, उसकी report में साफ़ कहा गया है कि यह नक्सल गलियारा गरीब गलियारा है, गरीबी के कारण, आर्थिक वशिमता के कारण। आजका यह संकट, जो भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुआ है, इससे एक और वशिमता लोगों के दिलों में चला गया कि आज की व्यवस्था भ्रष्टाचार खत्म करने में ईमानदार नहीं है, इसलिए लोग सड़क पर आ गए। कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। हम कुछ भी कहें, यह आम आदमी, जिस आम आदमी के नाम पर यह सरकार बनी थी, वह आम आदमी दुखी है, त्रस्त है, परेशान है, उसका वर्तमान व्यवस्था पर वशिमता समाप्त हो गया है, वह सड़क पर आ गया है। अगर वर्तमान व्यवस्था पर वशिमता समाप्त होगा तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, इसलिए उस वशिमता को बहाल करना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि किस दंग से वशिमता खत्म हुआ। यहां दिल्ली में, हमारी नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे, 2 जी स्फेक्ट्रम हो, चाहे गेम्स घोटाला हो, जो कुछ भी होता रहा, उसमें हमने किस दंग से वशिमता खोया है। उपसभापति जी, ऐसा शोर मच रहा है कि विदेशी बैंकों में बहुत पैसा है। पुणे का एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके 1,34,000 करोड़ के खाते विदेशी बैंकों में हैं, यह इन्कम टैक्स की जांच के बाद पता लगता है और सात

6.00 P.M.

सात तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। विश्वास कैसे बनेगा ? कौन इस देश की व्यवस्था पर भरोसा करेगा ? अगर सुप्रीम कोर्ट समय पर दखल नहीं देती तो जो थोड़ी-बहुत कार्यवाही हुई है, वह भी नहीं होती। वह 1,34,000 करोड़ रुपए कैसे वदेशों में ले गया, सरकार ने उससे नहीं पूछा। उस पर कर चोरी का मामला बनाया, उसको बचाया गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। विश्वास बिल्कुल टूट गया है। वदेशी बैंकों में 100 लाख करोड़ रुपए हैं, 300 लाख करोड़ रुपए हैं, कई चर्चाएँ हो रही हैं। बहुत से लोग इसके बारे में अपने authoritative आँकड़े दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के ऊपर दबाव डाला, tax haven कही जा रही वाली countries पैसा वापस लौटा रही हैं। मुझे याद है कि हम एक delegation के साथ न्यूयॉर्क गए थे और जसि दबि सभा में United Nations Convention Against Corruption पर बहस थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। यह कतिनी हैरानी की बात है, इस देश की सरकार ने विश्वास को कसि ढंग से तोड़ा है। यूनाइटेड नेशंस ने 192 देशों के साथ मल्लि कर एक कानून बनाया, संधि बनाई और उसका fundamental यह है कि अगर किसी देश के लोगों का पैसा, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा दूसरे देश में है, तो वह वापस लाया जाए। वह संधि हो गई। एक बहुत बड़ी International Treaty है। दुनिया के देशों ने पैसा वापस लेना शुरू कर दिया, मगर भारत सरकार ने उसको ratify करने में 6 साल लगाए। मैं वहाँ पर मौजूद था। स्विटजरलैंड के प्रतिनिधि ने अपने भाषण में कहा कि हम पैसा वापस देना चाहते हैं। उसने कहा कि आपके देशों की stolen property हमारे पास है, हम इसे लौटाना चाहते हैं। स्विटजरलैंड के प्रतिनिधि ने कहा, मेरे पास उसके भाषण की प्रति है, जो उसने वहाँ दिया था, मैं उसे पढ़ कर समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इस भाषण में स्विटजरलैंड का प्रतिनिधि यह कहता है कि हमने यूनाइटेड नेशंस की इस treaty पर हस्ताक्षर किए, हमने इसे ratify किया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि हमने अपने देश के पार्लियामेंट का विशेष कानून बनाया है, ताकि दुनिया के देशों के लोग हमारे बैंकों से पैसा वापस ले सकें। जब मैं वहाँ था, तो हमने ratify भी नहीं किया था। मैंने वापस आकर प्रधान मंत्री जी को भाषण की यह प्रति भेजी। मैंने कहा कि जसि देश में हमारे देश के 70 लाख करोड़ रुपए जमा हैं, (समय की घंटी) उस देश के प्रतिनिधि ने मेरे सामने कहा कि हम यह पैसा

वापस करना चाहते हैं , लेकिन भारत सरकार ने आज तक वह पैसा वापस लेने की कोशिश नहीं की। अमेरिका पैसा वापस ले रहा है , दुनिया के 10 देश पैसा वापस ले रहे हैं , लेकिन भारत पैसा वापस नहीं ले रहा है। मैं यह कह रहा हूँ कि विश्वास टूटा है। लोगों के मन में यह विश्वास है कि हमारी गरीबी , हमारी परेशानी , हमारी भुखमरी का कारण भ्रष्टाचार है और उसे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये यह व्यवस्था , यह सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए बड़ी बेताबी के साथ , बड़ी परेशानी के साथ , देश की सारी की सारी जवानी आजसड़क पर है। मैं यह नविदन करना चाहता हूँ कि उस विश्वास को बहाल करने का एक मौका आया है। अन्ना हजारे जी ने ऐतिहासिक काम किया है। (समय की घंटी)

श्री उपसभापति : श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी।

श्री शान्ता कुमार : उन्होंने इसका नेतृत्व किया है। मैं अन्ना हजारे जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब जबकि लगभग हम सब लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है और हमारी पार्टी ने इस कामून की जो व्यवस्था है , मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता , हमने उसको support किया है , लेकिन मैं सभी पक्षों से कहना चाहता हूँ कि इसे कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएँ , इसे कोई ego का प्रश्न न बनाएँ , बल्कि पूरी सहमति जल्द -से- जल्द बनाएँ।

मैं एक नविदन और करना चाहता हूँ कि यह असाधारण परिस्थिति है। यह कहा जा रहा है कि कामून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, अधिकार निश्चित है, लेकिन 43 साल तक हमने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया, इसका भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए औपचारिक तौर पर यह कहना चाहिए।

अन्त में मैं एक नविदन और करना चाहता हूँ कि कल यह कहा गया कि केवल इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, तो और जो करना है, करिए न, रोका किसने है आपको? और भी करिए। (समय की घंटी)

मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति : आपकृपया समाप्त कीजिए।

श्री शान्ता कुमार : हांगकांग 30 साल पहले दुनिया के महाभ्रष्ट देशों में था। उसने Independent Commission Against Corruption बनाया। उस independent कामून के कारण आज हांगकांग का नाम दुनिया के ईमानदार देशों में आ गया है।

इसलिए इस पर सहमति बने, मेरा यह नविदन है। उनका अनशन टूटे, यह मेरा नविदन है। हम सब इस बुनियादी सवाल पर कि पूरे के पूरे समाज के अन्दर हमारी जो credibility erode हो रही है, लोकपाल बलि बना कर उसको बहाल करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (उत्तराखंड) : मामनी य उपसभापति जी, हम एक बड़े संवेदनशील मुद्दे पर आज यहां चर्चा कर रहे हैं और मैं अपने साथियों से सहमत हूँ, जब उन्होंने यह कहा कि आज पूरा हिन्दुस्तान हमें देख रहा है। लोग संसद की तरफ इस उम्मीद से नज़र उठाकर देख रहे हैं कि संसद से आज एक ऐतिहासिक फैसला हो रहा है।

श्रीमन्, मैं सभी विभिन्न दलों के सांसदगणों के भाषण सुन रहा था और जितना मैं समझ पाया, दो बातों पर मुझे नहीं लगता है कि बहस की कोई गुंजाइश बची है। पहली बात यह है कि इस मुद्दे पर कम से कम कोई विवाद नहीं है कि इस देश को इस समय एक मज़बूत कामून की जरूरत है। एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है, जो इस देश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी तरीके से, असरदार तरीके से अंकुश लगा सके। मेरे खयाल से इस पर किसी भी दल के अन्दर कहीं कोई दो राय मुझे देखने में नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि लगभग सभी

के बीच में इस बात पर भी सहमति देखने को मिली है कि इस देश का संविधान सर्वोपरि है और इस देश की संसद को कानून बनाने का सर्वोच्चाधिकार प्राप्त है। अगर कोई भी कानून या कोई भी व्यवस्था परिवर्तित करनी है या नया कानून बनाना है, तो उसमें संविधान को एवं देश की संसद की गरिमा को सर्वोच्च बना कर रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर भी किसी दल के बीच में कोई दो राय नहीं देखी है। ये दो वक़िदहीन मुद्दे हैं।

श्रीमन् , अपराध वहि़न समाज है , भ्रष्टाचार वहि़न समाज है , असमता वहि़न समाज है , अन्याय वहि़न समाज है , साम्प्रदायिकता वहि़न समाज है , जाति वहि़न समाज है , हमारे पूर्वजों और नेताओं ने अपना संविधान बनाते समय इन तमाम ऊँची परिकल्पनाओं को दृष्टिगोचर में रखा था। ये हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं। लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि लक्ष्य वही रखा जाता है , जो हमारे पास नहीं होता है। जो हमारे पास हासिल है , उसे कभी हम अपना आदर्श नहीं बनाते। आदर्श हम उन्हीं चीज़ों को बनाते हैं , जो हमें हासिल

नहीं हैं और जो हमें हासिल करनी है सच्चाई यह है कि ये हमारे आदर्श हैं , लक्ष्य हैं , लेकिन सच्चाई यह भी है कि न कभी अतीत में और न वर्तमान में , मुझे कहीं दिखाई नहीं देता कि कभी वह दमि भी आएगा जब समाज की सारी बुराईयां और कुरीतियां , जिनकी हमने अभी चर्चा की है , सदा के लिये समाप्त हो जाएंगी। ऐसे समाज कल्पना में तो होते हैं , लेकिन वास्तविकता में नहीं।

आजबहस इस बात की छड़ी है कि सरकार का लोकपाल बलि सही है , अन्ना हजारे और उनकी टीम द्वारा बनाया गया प्रस्तावित लोकपाल बलि सही है अथवा जो अन्य सखिल सोसाइटी के संघठन हैं , उनके द्वारा भेजा गया लोकपाल बलि सही है। इस बात पर विवाद है। कुछ मुद्दों पर तो सहमति है , लेकिन जैसा कि प्रणब जी ने अपने भाषण के आरम्भ में स्पष्ट किया कि जब चर्चा शुरू की गई थी , तब 40 बुद्धि यादी सद्धितों को अन्ना हजारे जी की टीम ने सरकार के सामने रखा था। 40 में से 34 सद्धितों पर लगभग सहमति हो गई , क्योंकि उनमें बहुत अधिक विवाद का कोई विषय नहीं था। लेकिन 6 ऐसे मुद्दे बाकी रह गए थे , जिन पर असहमति या मतभेद था अथवा विचारों का अंतर था और उसी अंतर ने इस विवाद को जन्म दिया। अंततः : अन्ना हजारे जी अनशन करने के लिये रामलीला मैदान पर बैठ गए। वहां से आज तक की जो यात्रा हुई है , इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत साफ तौर पर सामने आई है और वह यह है कि अन्ना हजारे जी बार -बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि जो प्रावधान उनके द्वारा प्रस्तावित बलि में हैं , वही प्रावधान ज्यों के त्यों मान्य किए जाएं।

श्रीमन् , मैं अन्ना हजारे जी के राजनैतिक अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करता हूँ। देश के किसी भी नागरिक की तरह उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वे अपनी बात कहें। लेकिन , हमारा संविधान इस देश के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता कि वह जद्वि करवाकर संसद और संविधान की स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध अपनी बात को मनवा सके। यह अधिकार हमारा संविधान किसी भी नागरिक को नहीं देता। अगर उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है , जिनका हम सम्मान करते हैं , तो हम भी यह अपेक्षा करते हैं कि

अन्ना हजारे जी भी इस देश के अन्य लोगों के वधिरों के और उनके प्रस्तावों के सम्मान करें। हमारी ही बात पूर्णतः सत्य है और इसके अलावा सब की बात असत्य है, ऐसा मान लेना मैं समझता हूँ कि अन्ना हजारे जैसे एक वरिष्ठ और बुजुर्ग आदमी के लिए सम्मानजनक बात नहीं है, औचित्यपूर्ण बात नहीं है। इसलिए, मैं उनसे सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसी तरह सरकार ने बीच में बार-बार अनेक अवसरों पर चर्चा के दौरान लचीला रुख अख्तियार किया है, उनके वधिरों से अपनी सहमति बैठाने का प्रयास किया है, उसी तरह मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि वे और उनकी टीम भी सरकार और अन्य वधिरों के लोगों के साथ अपनी सहमति और अपना सामन्जस्य बैठाने का प्रयास करें और कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश हो, जिससे साँझ भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी, जो बुनियादी लक्ष्य है कि एक प्रभावकारी कानून बने, वह बन जाए, लेकिन इस देश के अंदर ऐसी स्थिति निर्मित न होने पाए, जिससे देश में हम वधिरों की तरफ बढ़ें। मैं उनसे यही सम्मानपूर्वक आग्रह करना चाहूँगा।

श्रीमन्, वे छः बन्धु, जिन पर चर्चा की जानी चाहिए या जिन पर आज तक वधिद बना हुआ था, उन बन्धुओं पर मैं एक-एक कर के अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री को इस लोकपाल की परिधि के भीतर होना चाहिए या नहीं, यह एक contentious issue था, एक वधिदास्पद बन्धु था। प्रधान मंत्री,

डा० मनमोहन सहि जी, ने स्वयं अपनी तरफ से अपनी कैबिनेट में यह आग्रह किया था कि प्रधान मंत्री को अगर उसमें रखा जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, खुशी होगी। यह पहल उन्होंने खुद की थी। इसके बावजूद बहुत-सारे अन्य considerations के कारण कैबिनेट ने यह उचित समझा कि यह प्रश्न केवल डा० मनमोहन सहि जी का नहीं है। प्रधान मंत्री के पद पर आज डा० मनमोहन सहि जी हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। इस देश में आने वाले अनेक वर्षों और दशकों तक इस कामून को लागू रहना है और इन सब कामूनों के लागू होने का परिणाम क्या हो सकता है? अभी मेरे कुछेक साथी, विशेष कर पूरे राम गोपाल यादव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकार कामून तो बनाए, प्रभावी कामून बनाए, लेकिन अगर आज जल्दबाजी में या दबाव में आकर ऐसा कोई कामून सरकार बना देगी तो जो लोग आज माँग कर रहे हैं कि ऐसा कामून बनाया जाए, कल वही लोग यह आरोप लगाएंगे कि सरकार ने दबाव में आकर जल्दबाजी में ऐसा कामून बना दिया, जिसके दुष्परिणाम पूरे देश को देखने पड़ रहे हैं। इसलिए, मेरा आग्रह है कि...

श्री उपसभापति : अभी आपके पास दो मिनट हैं, उनमें आप अपनी बात समाप्त कीजिए। ... (व्यवधान) ... अभी आपके दो मिनट हैं, उनमें आप समाप्त कीजिए। ... (व्यवधान) ...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप कहें तो मैं अभी बैठ जाता हूँ।

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं। ... (व्यवधान) ...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं। ऐसा है कि हाउस का consensus बना है कि ... (व्यवधान) ...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : श्रीमान्, consensus बना है, लेकिन मुझे भी समय दिया जाए। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : हर पार्टी को दस-दस मिनट ... (व्यवधान) ...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : श्रीमान्, मेरा नविदन यह था, मैं यह कह रहा था, कि इसमें प्रधान मंत्री को शामिल करने के मामले पर हम कोई ज़िद की बात न करें, बल्कि उस पर हम गम्भीरता

सें वचिार करें। आजहमारा हैं , कल आपका होगा और कभी कसिी दूसरे का होगा। प्रधान मंत्री का पद इस देश के Chief Executive का पद हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का Chief Executive का पद हैं। अगर यह कल को केवल लोकपाल के सामने रोज एक फाइल लिए खड़ा मल्लिगा तो मुझे बताइए कि इस देश के शासन और प्रशासन की दशा और दशा क्या होगी ? इस बात पर हमें गम्भीरता से वचिार करना होगा। राजनैतिक पूर्वाग्रहों से हट कर हमें इस पर वचिार करना होगा। मैं इस बात के बल्लिकुल वसिद्ध नहीं हूँ कि प्रधान मंत्री कतई उसके दायरे में न हों या प्रधान मंत्री के ऊपर कोई अंकुश न हो। प्रधान मंत्री पर अंकुश पहले से ही हमारे संविधान का है , इस सदन का है , संसद का है और इसके अलावा हमारे देश का जो Anti Corruption कानून है , उसके अंतर्गत भी प्रधान मंत्री हैं। इसलिए , मैं नहीं समझता हूँ कि यह कहा जा सके कि प्रधान मंत्री पर कसिी तरह की जल्लिमेदारी नहीं है या उसके ऊपर कानून का कोई अंकुश नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता। प्रधान मंत्री को जसि कल्लिम की गंभीर परिस्थितियों में नर्णिय लेना पड़ता है , उसमें प्रधान मंत्री की स्वतंत्रता को बनाए रखना इस राष्ट्र के हति में होगा। हमारे सामने बड़ी - बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे उत्तर की तरफ भी हैं और हमारे पश्चिम की तरफ भी हैं। (समय की घंटी) दोनों तरफ से आने वाली इन चुनौतियों के समय कहीं कसिी वक्त ऐसा न हो कि हमारे सामने यह संकट की घड़ी बन जाए और उस वक्त हम यह देखें कि इस कानून की वजह से हमने अपने राष्ट्र का

अहित कर लिया है। अगर ऐसा हुआ , तो आने वाली पीढ़ी इस देश को और हमको कभी क्षमा नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखना होगा।

श्रीमान् , दूसरा मुद्दा न्यायपालिका को इस कामून के अंतर्गत लाने का था। मेरा यह मानना है कि न्यायपालिका के मामले में लगभग सभी की शायद यही राय हो भी गई है कि न्यायपालिका के लिए और उसको जम्मेदार बनाने तथा उस पर अंकुश लगाने के लिए अलग से एक कामून बनाया जाए। सरकार उस कामून को यहां बिल के रूप में ला कर रखे। अगर संसद के बाहर किसी भी गतिविधि में संसद सदस्यों पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप हो , तो उसमें संसद सदस्य लोकपाल के अंतर्गत आएँ , इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। (समय की घंटी) लेकिन , संसद के अंदर संसद सदस्यों की कार्यविधियों और उनके बोलने पर अंकुश लगाने की कोई भी बात लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत होगी और यह व्यावहारिक नहीं होगा। पूरे राम गोपाल यादव जी ने जो उदाहरण दिये थे , मैं उनके साथ अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय , लोकायुक्त को यहां से बनाया जाए , इस मामले में मेरी राय बहुत स्पष्ट है। जैसी तरह हमने पंचायती राज का एक केन्द्रीय मॉडल कामून बना कर राज्यों को दिया था , उसी तरह इसके लिए भी एक मॉडल कामून बनाया जा सकता है। इसको राज्यों के वक्ता पर छोड़ दिया जाए , क्यों कि अगर हम ऐसा कोई कामून बनाएंगे। (समय की घंटी) जैसी राज्यों के अधिकारों पर यहां से कोई अपवंचन होगा , तो इस बात का विशिष्ट किया जाएगा , जैसा कि मुख्य मंत्रियों ने इससे पहले किया भी है।

श्रीमान् , नविले स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को इस परिधि में लाने के संबंध में मेरा मानना यह है कि संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं और अगर संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करना है , तो इसका एक ही उपाय है कि संविधान संशोधन किया जाए। मैं समझता हूँ कि संविधान संशोधन के लिए आजवातावरण ऐसा नहीं है , राजनीतिक अकगणित भी ऐसी नहीं है। दूसरी बात , एक तरफ तो अन्ना जी कह रहे हैं कि तत्काल यह बिल पास कीजिए। वह डेड लाइन देते हैं , कभी 30 तारीख बताते हैं , तो कभी 20 तारीख बताते हैं। दूसरी तरफ , अगर संविधान संशोधन करना पड़ा , तो राज्यों की वधान सभाओं के

पास इसको rectification के लिये भेजना पड़ेगा।

श्री उपसभापति : कृपया आप conclude कीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : ये सारी प्रक्रिया , फिर कम से कम साल , डेढ़ साल लगा लेगी और अगर इसमें दो साल लग जाए , तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए , यह व्यावहारिक नहीं होगा कि हम संविधान संशोधन का बिल आजलाश और संसद में जल्दी से जल्दी यह कानून भी पारित कर दें (समय की घंटी)। दोनों बातें अंतर्विरोधी हैं , इसलिए , श्रीमान , मेरा आपसे नविदन यह है कि ये जो 5-6 बिल हैं , जिन बिलों पर बहस हो रही है , इन बिलों के ऊपर मैंने अपनी राय और हमारी पार्टी की राय व्यक्त की है। मैं यह चाहूंगा कि सभी इस बात पर विचार करें। हम थोड़े पूर्वग्रहों से दूर होकर , राजनीतिक पूर्वग्रहों से भी दूर होकर विचार करें और इस बात की कोशिश करें कि एक सामंजस्य बन सके और हमारा मुख्य लक्ष्य प्राप्त हो , जिससे एक प्रभावी कानून बने। (समय की घंटी)।

श्री मान , मैं एक अंतिम बात कहे बिना नहीं मानूंगा। अन्ना जी से मेरा नविदन यह है कि अन्ना जी , हम आपका सम्मान करें , यह बात तो ठीक है लेकिन , आपके मंच से इस देश के संसद सदस्यों के लिये जितनी भाषा

का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वह सम्मानजनक है? (समय की घंटी)। क्या वह गरिमापूर्ण है? क्या आप इस देश के सारे सांसदों पर बर्ला भेदभाव किए एक तरफ से लुटेरे होने का आरोप लगा देंगे, चोर-चोर कह कर पुकारेंगे? क्या आप उनको उनके अधिकारों से अपवंचित करना चाहेंगे?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अगर इस तरह का कोई प्रयास होगा, तो श्रीमान, जैसी तरह हमने सम्मान दिया है, (समय की घंटी) हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर उसी तरह उनका भी सम्मानपूर्ण रवैया संसद के प्रति रहे, संविधान के प्रति रहे, तो हम उनका सम्मान करेंगे, वरना जुबान हमारे मुंह में भी है और जवाब देना हमको भी आता है। धन्यवाद। जय हस्ति।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a request from Mr. Adeb as he is fasting...(Interruptions)...

SHRI M.V. MYSURA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, we have also been waiting. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has made a request. ...(Interruptions)... Your request is there. ...(Interruptions)... Immediately after him you can speak. ...(Interruptions)... It is only a request. ...(Interruptions)... You will be called. I am not saying that you will not be called. ...(Interruptions)...

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश): जनाब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर आज यह तीसरी बहस हो रही है। इससे पहले दो बहसों में यह बात तय की जा रही थी कि लोकपाल बिल कौन बनाएगा, कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। इस पर लीडर ऑफ द ओपोजिशन ने एक नायाब तरीक़ा दो दिनों पहले की थी। लेकिन, आज जो यह तीसरी बहस हो रही है, मैं समझ नहीं पाया कि यह बहस किसलिए हो रही है। यह बात साबित होनी चाहिए कि यह किसी की हठधर्मी है या मीडिया का ब्लैकमेल है कि आज Saturday को स्पेशल सेशन बुलाया गया और यह कहा गया कि इस पर फिर से बहस होगी। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब एक पार्लियामेंट ने पूरे तरीक़े से एक आवाज होकर कहा कि अन्ना जी, आप अपना अनशन बंद कर दीजिए, प्राइम मनिस्टर

ने कहा , लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा , लेकिन हठधर्मी कायम हैं और वह कायम ही नहीं हैं , उस मंच से जसि तरह की अज्ञात उठायी जा रही हैं , मुझे तकलीफ होती है कि जहाँ वे बैठे हैं , वहाँ मेरे गांधी की फोटो लगी हुई है वहाँ उस मंच पर क्या हो रहा है ? कोई फल्लिम एक्टर आ रहा है , कोई हमको “चोर ” कह रहा है , कोई “चकारा ” कह रहा है , कोई “डकैत ” कह रहा है और यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग , इनको एहसास भी नहीं होता कि इस अजीम पार्लियामेंट की अज़मत का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है इस पर बहस होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी ? इस मसले पर हम दो बार बात कर चुके हैं यह कहा गया कि पार्लियामेंट के मेंबरों को इसमें लया जाए। मुझे बताइये , कोई शख्स यह नहीं कह सकता कि पार्लियामेंट का मेंबर रश्वित देता है , लेकिन लोकपाल के आने के बाद हमारे ऊपर यह इल्जाम आएगा और हमको यकीनी तौर लोकायुक्त को रश्वित देनी पड़ेगी कि साहब , हमको बरी कर दीजिए , हमारा कोई दोष नहीं

है... (व्यवधान) ... यानी, हमको रश्मि वत दलाने की कोशिश की जाएगी। यह एक नया मसूबा बना है। कम से कम पार्लियामेंट के मੈम्बर के ऊपर यह इल्जाम कभी नहीं लगा कि वह रश्मि देता है, लेकिन हमारे ऊपर जो मुसल्लत कथि जाएगा, उसको हम रश्मि देंगे।

कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें लाया जाए। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, nominated executive के अंदर आएगा। यह कसि कस्मि का समाज आपबनाना चाहते हैं? मैं अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा दूँ, तो वे जाकर वहाँ खड़े होंगे, वे हुकुमत कसि तरह चलाएँगे? एक नये नजिम का तसव्वुर लाया गया है। ये कौन लोग ला रहे हैं? अफसोस इस बात का है कि वे गांधीवादी का नाम लेते हैं और गांधी जी का नाम लेते हैं। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। हमारे पार्लियामेंट के बारे में कहा गया कि सब "जाहिल" बैठे हुए हैं। हमको बताया गया कि अन्ना जी बहुत शरीफ आदमी हैं, पढ़े-लिखे भी नहीं हैं, फरि भी हम उनसे कह रहे हैं कि हम आपकी राय माँगे, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट में पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि डीग्रियाँ दिखाओ। जहाँ ऐसा लायक लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठा हो, जहाँ सरकार में इतने लायक वकील बैठे हों, वहाँ एक बहस हो रही है, वहाँ एक मुद्दा तय हो रहा है।

मैंने उस दबि भी आपसे कहा था कि यह मौजूं भ्रष्टाचार का नहीं है, इसके पीछे कुछ और साजिश है। ये सब बातें साफ़ होती जा रही हैं। मैं यह समझता हूँ कि आज जो बहस हुई। यहाँ इससे पहले और तीन बहसें हुईं। मैं यह अल्फाज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी प्रोफेसर साहब ने यह बताया और मैंने खुद टीबी पर सुना कि लोगों को यह हुक्म दिया गया है कि आज कोई काम मत करना, टीबी पर यह देखना कि ये "जाहिल-चोर" क्या बातें कर रहे हैं। उनकी समझ में आ गया होगा कि यह मुल्क, ये चन्द लोगों से नहीं चलता है। कहा गया कि ये सोशल लोग हैं, जो यह कर रहे हैं। कसि ने एक कत्तिब लिखि दी, उसके बाद ये बहुत बड़े आदमी बन गये, क्योंकि अमरीका में उनकी कत्तिब छप गयी है और अब वे मुल्क चलाएँगे। कोई कसि नाले या डैम में खड़ा हो गया और उसने कहा कि अब हम हब्दिस्तान में काम नहीं करने देंगे, बजिली नहीं बनेगी, तो वह social activist बन गया और अब वह मुल्क चलाएगा। जब ये लोग

बनाएँगे , इनके पीछे कतिने लोग हैं ? इनके पीछे कौन लोग हैं ? यहाँ जो लोग भी बैठे हुए हैं या उस हाउस में जो बैठे हुए हैं , वे 15-15, 20-20 लाख लोगों को represent करते हैं। वे यहाँ पर represent करके आते हैं , लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाए और यह सांसद चुप रहे ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि तीनों मुझों पर बहस हुई। आप लोगों ने जजों के बारे में राय दी। मैं भी कहता हूँ कि जरूर कुछ होना चाहिए। इसे आप लोग तय करे , यह हाउस तय करे। हम लोग इस की ताईद करेंगे , उस पर बहस करेंगे , आप से पूछेंगे। यह कहा गया कि सारे -के-सारे लोकपाल के under में आ जाएंगे। अभी एक बहस में येचुरी साहब ने बताया था कि लाखों - करोड़ों कैसेज अदालतों में पड़े हुए हैं। जनाब -ए-आली , हम अभी तक उन के लिये तो infrastructure develop नहीं कर पाए हैं , लोक आयुक्त के लिये कहाँ से infrastructure develop होगा ? यह एक parallel body बनायी जाएगी तो उस के लिये पैसा कहाँ से आएगा ? ये सब चीजें सोचने की हैं। ये सड़क पर बैठकर तय नहीं होती।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो . पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

मैं तीन-चार बातें और रखना चाहूँगा। आजअन्ना जी को चाहिए कि वह अपनी हठधर्मिता को खत्म करें। वे यह समझें कि पार्लियामेंट की अज़मत क्या है , इस की जरूरत क्या है , लेकिन जन्म लोगों के हाथों में वे हैं , मैं

इस हाउस से गुजारिश करूंगा , एक फ़िल्म आयी थी: “Peepli live” अगर किसी ने वह फ़िल्म नहीं देखी है तो लोग उसे देखें और सोचें कि वे बेघारे क्या हो गए हैं ? किसी लोगों ने धरू रखा है ? उन की क्या हैसियत हो गयी है ? इस मुल्क का प्राइम मनिस्टर कह रहा है , पार्लियामेंट के फ़्लोर से कह रहा है , लेकिन वे कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। मैं इस हाउस से पूछना चाहता हूँ कि आप ने आजबहस की , आप आज एक resolution पास करेंगे और उस के बाद भी वह नहीं मानें तो क्या होगा ? अगर वे कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आप? मैं इस हाउस से गुजारिश करूंगा कि जबि लोगों ने इस पार्लियामेंट को बदनाम किया है – टेलीविजन चैनल्स ने या उन लोगों ने , उन्हें इस हाउस में बुलाया जाए और उन से यह कहा जाए कि तुम को यह हक नहीं मिलि जाता। हम संजीदा हैं , लीडर ऑफ द अपोजीशन संजीदा हैं। मैंने आज लीडर ऑफ अपोजीशन को मुबारकवाद दी है। मैंने कहा है कि आप ने दोमों - तीनों बहसों में पार्टी -लाइन से ऊपर उठकर बात की है और हमारी ओर से भी यही बात हुई है। एक-एक शख्स का यही कहना है कि यहां से भ्रष्टाचार दूर हो , लेकिन जब आप एक parallel body बनाएंगे तो हम लोग भी जो भ्रष्ट नहीं हैं , वे लोग भी भ्रष्ट बनेंगे। फरि यह अंजाम होगा कि एक नयी फौज खड़ी हो जाएगी।

सर, मैं बराबर यह कहता हूँ कि हम को समाज बनाने की जरूरत है। हर डिपार्टमेंट में एक वॉजिलेंस डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट को यह चाहिए कि वह उन वॉजिलेंस डिपार्टमेंट्स को और सख्त बनाए। वहां पर ईमानदार ऑफिसर्स को भेजे और सी.बी.आई. ऑफिसर्स और जत्तिनी वॉजिलेंस एजेंसीज हैं , उन के ऊपर बुनियादी तौर पर सख्ती करनी चाहिए।

सर, जहां तक ब्लैक मनी और दूसरी बातें हैं , कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है , मैं तो सिर्फ़ यह कहता हूँ कि दिल्ली के आसपास – गुडगांव , नोएडा में हजारों रजिस्ट्री रोज होती हैं , वहां जसि मकान की रजिस्ट्री 10 लाख की होती है , वह दो करोड़ रुपए में बिकिता है और रोज करोड़ों -खरबों रुपयों की black money generate होती है। क्या यह सब को माफ़ूम नहीं है ? क्या लोकपाल से यह उक़ेगा ? गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इन सब चीजों पर गौर

करे कि कहां रोज़ black money develop होती है। सर, इन 10 सालों में जो जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं , इस से black money पैदा हुई है और इसी से ये मुसीबतें खड़ी हुई हैं। अब हुआ यह है कि पहले हमारे पास स्टेट में पैसा कम था। हम को पैसे के लिये जुगाड़ करना पड़ता था। आज इस मुल्क ने तरक्की की, पैसे की रखाखानी हो गयी , पैसा बढ़ने लगा और लोगों की नीयत खराब हो गयी। इसलिए हम सब इस के ज़िम्मेदार हैं , लेकिन मैं अन्ना जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि वह इस मुल्क को चलने दें और मैं हुकूमते हद्दि से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग सड़कों पर traffic violation कर रहे हैं , गाड़ियों पर चल रहे हैं और पुलिस की बातें नहीं मान रहे हैं , उन के खिलाफ सख्त -से-सख्त action ले। और जो लोगे यह तहरीक चला रहे हैं , उन से हमारी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते गांधी जी का नाम न लें। गांधी जी हमारे पास से चले गए, लेकिन जहां पर भी हैं , उन के दल्लि को यह तकलीफ पहुंचती होगी कि लोगों ने कैसे-कैसे ऐलान कर रखे हैं।

बहुत -बहुत शुक्रिया , आप ने मुझे मौका दिया। मुझे जाना था इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की थी।

جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : جناب آپ کا بہت بہت شکریہ، اس مدعے پر آج یہ تیسری بحث ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے دو بحثوں میں یہ بات طے کی جا رہی تھی کہ ٹوک پال کون بنائے گا، کیسے بنے گا اور کہاں بنے گا۔ اس پر لیٹر آف اپوزیشن نے ایک نایاب تقریر دو دن پہلے دی تھی۔ لیکن، آج جو یہ تیسری بحث ہو رہی ہے، میں سمجھ نہیں پایا کہ بحث کس لئے ہو رہی ہے۔ یہ بات ثابت ہوئی چاہئے کہ یہ کسی کی ہٹ دھرمی ہے یہ میڈیا کا بلیک میل ہے کہ آج Saturday کو اسپیشل سیشن بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس پر پھر سے بحث ہوگی۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جب ایک پارلیمنٹ نے پورے طریقے سے ایک آواز ہو کر کہا کہ انا جی، آپ اپنا ان-شن بند کر دیجئے، پرائم منسٹر نے کہا، لیٹر آف اپوزیشن نے کہا، لیکن ہٹ دھرمی قائم ہے اور یہ قائم ہی نہیں ہے، اس منچ سے جس طرح کی آوازیں اٹھانی جا رہی ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں، وہاں میرے گاندھی کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ وہاں اس منچ پر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی فلم ایکٹر آ رہا ہے، کوئی ہم کو "چور" کہہ رہا ہے، کوئی "چکرا" کہہ رہا ہے، کوئی "ٹکیت" کہہ رہا ہے اور یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئی لوگ، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس عظیم پارلیمنٹ کی عظمت کا کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس پر بحث ہونی چاہئے تھی یا نہیں ہونی چاہئے تھی؟ اس مسئلے پر ہم دو بار بات کر چکے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے ممبروں کو اس میں لیا جائے۔ مجھے بتائیے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پارلیمنٹ کا ممبر رشوت دیتا ہے، لیکن ٹوک پال کے آنے کے بعد ہمارے اوپر یہ الزام آئے گا اور ہم کو یقینی طور پر ٹوک ایکٹ کو رشوت دینی پڑے گی کہ صاحب، ہم کو بری کر دیجئے، ہمارا کوئی دوش نہیں ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ یعنی، ہم کو رشوت دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک نیا منصوبہ بنا ہے۔ کم سے کم پارلیمنٹ کے ممبر کے اوپر یہ الزام کبھی

†Transliteration in Urdu Script.

نہیں لگا کہ یہ رشوت دیتا ہے، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیا جائے گا، اس کو ہم رشوت دیں گے۔

کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو اس میں لایا جائے۔ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر، nominated executive کے اندر جائے گا۔ یہ کس قسم کا سماج آپ بنانا چاہتے ہیں؟ میں اگر کہیں پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگا دوں تو وہ جاکر وہاں کھڑے ہوں گے، وہ حکومت کس طرح چلائیں گے؟ ایک نئے نظام کا تصور لایا گیا ہے۔ یہ کون لوگ لا رہے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے کہ گاندھی وادی کا نام لیتے ہیں اور گاندھی جی کا نام لیتے ہیں۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ہمارے پارلیمنٹ کے بارے میں کہا گیا کہ سب "جاہل" بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو بتایا گیا کہ انا جی بہت شریف آدمی ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی رائے مانیں گے، لیکن جو لوگ پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے نہیں، ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ڈگریاں دکھاؤ۔ جہاں ایسا لائق لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھا ہو، جہاں سرکار میں اتنے لائق وکیل بیٹھے ہوں، وہاں ایک بحث ہو رہی ہے، وہاں ایک مدعا طے ہو رہا ہے۔

میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ موضوع بھرپور جانچا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور سازش ہے۔ یہ سب باتیں صاف ہوتی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو بحث ہوئی۔ یہاں اس سے پہلے اور تین بحثیں ہوئی۔ میں یہ الفاظ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پروفیسر صاحب نے یہ بتایا اور میں نے خود ٹی۔وی۔ پر سنا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج کوئی کام مت کرنا، ٹی۔وی۔ پر یہ دیکھنا کہ یہ "جاہل-چور" کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ملک، یہ چند لوگوں سے نہیں چلتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ سوشل لوگ ہیں، جو یہ کر رہے ہیں۔ کسی نے ایک کتاب لکھ دی، اس کے بعد یہ بہت بڑے آدمی بن گئے، کیوں کہ امریکہ میں ان کی کتاب چھپ گئی ہے اور اب وہ ملک چلائیں گے۔

کوئی کسی نالے یا ڈیم پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب ہم ہندوستان میں کام نہیں کرنے دیں گے، بجلی نہیں بنے گی، تو وہ social activist بن گیا اور اب وہ ملک چلانے گا۔ جب یہ لوگ بنائیں گے، ان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہاں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اس ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 15-15، 20-20 لاکھ لوگوں کو represent کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر represent کر کے آتے ہیں، لیکن ان کا مذاق اڑایا جائے اور یہ مستند چپ رہے؟

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹینوں مدعوں پر بحث ہوئی۔ آپ لوگوں نے ججوں کے بارے میں رائے دی۔ میں بھی کہتا ہوں کہ ضرور کچھ ہونا چاہئے۔ اسے آپ لوگ طے کریں، یہ ہاؤس طے کرے۔ ہم لوگ اس کی تائید کریں گے، اس پر بحث کریں گے، آپ سے پوچھیں گے۔ یہ کہا گیا کہ سارے کے سارے لوگ پال کے انٹر میں آجائیں گے۔ ابھی ایک بحث میں پجوری صاحب نے بتایا تھا کہ لاکھوں کروڑوں کیسیز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جناب عالی، ہم ابھی تک ان کے لئے تو infrastructure development نہیں کر پائے ہیں، لوگ ایکٹ کے لئے کہاں سے infrastructure develop ہوگا؟ یہ ایک parallel body بنائی جائے گی تو اس کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ یہ سڑک پر بیٹھ کر طے نہیں ہوتیں۔

(اپ سبھا ادھیش (پروفیسر پی جے۔ کورنن) پیٹھاسین ہونے)

میں تین چار باتیں اور رکھنا چاہوں گا۔ آج اتا جی کو چاہئے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کو ختم کریں۔ وہ یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کی عظمت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ہیں، میں اس ہاؤس سے گزارش کروں گا، ایک فلم آئی تھی "پیلی لانیو" اگر کسی نے یہ فلم نہیں دیکھی

ہے تو لوگ اسے دیکھیں اور سوچیں کہ وہ وہ بے چارے کیا ہو گئے ہیں؟ کن لوگوں نے گھیر رکھا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہو گئی ہے؟ اس ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، پارلیمنٹ کے فلور سے کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ میں اس ہاؤس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج بحث کی، آپ آج ایک ریزولوشن پاس کریں گے اور اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ میں اس ہاؤس سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے اس پارلیمنٹ کو بدنام کیا ہے - ٹیلی ویژن چینلز نے یا ان لوگوں نے، انہیں اس ہاؤس میں بلایا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم کو یہ حق نہیں مل جاتا۔ ہم سنجیدہ ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن سنجیدہ ہیں۔ میں نے آج لیڈر آف اپوزیشن کو مبارکباد دی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ آپ نے دونوں تینوں بحثوں میں پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر بات کی ہے اور ہماری اور سے بھی یہی بات ہوئی ہے۔ ایک ایک شخص کا بھی کہنا ہے کہ یہاں سے بھرشتاچار دور ہو، لیکن جب آپ ایک parallel body بنائیں گے تو ہم لوگ بھی جو بھرشت نہیں ہیں، وہ لوگ بھی بھرشت بنیں گے۔ پھر یہ انجام ہوگا کہ ایک نئی فوج کھڑی ہو جائے گی۔

سر، میں برابر یہ کہتا ہوں کہ ہم کو سماج بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر ڈیپارٹمنٹ میں ایک وجیلنس ڈیپارٹمنٹس کو اور سخت بنائے۔ وہاں پر ایماندار آفیسرز کو بھیجے اور سی۔بی۔آئی۔ آفیسرز اور جتنی وجیلنس ایجنسیز ہیں، ان کے اوپر بنیادی طور پر سختی کرنی چاہئے۔

سر، جہاں تک بلیک منی اور دوسری باتیں ہیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ دہلی کے آس پاس۔ گڑ گاؤں، نوئیڈا میں ہزاروں رجسٹری روز ہوتی ہیں، وہاں جس مکان کی رجسٹری 10 لاکھ کی ہوتی ہے، وہ دو کروڑ میں بکتا ہے اور روز کروڑوں کھریوں روپوں کی بلیک منی جنریت ہوتی ہے۔ کیا یہ سب کو معلوم ہے؟ کیا لوک پال سے یہ رکے

گا؟ گورنمنٹ کو چاہئے کہ وہ ان سب چیزوں پر غور کرے کہ کہاں روز بلیک منی ڈیولپ ہوتی ہے۔ سر، ان 10 سالوں میں جو زمینوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس سے بلیک منی پیدا ہوئی ہے اور اسی سے یہ مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلے ہمارے اسٹیٹ میں پیسہ کم تھا۔ ہم کو پیسے کے لئے جگاڑ کرنا پڑتا تھا۔ آج اس ملک نے ترقی کی، پیسے کی روانی ہو گئی، پیسہ بڑھنے لگا اور لوگوں کی نیت خراب ہو گئی۔ اس لئے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن میں انا جی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ملک کو چلنے دیں اور حکومت بند سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سڑکوں پر traffic violation کر رہے ہیں، گاڑیوں پر چل رہے ہیں اور پولیس کی باتیں نہیں مان رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے۔ اور جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے گاندھی جی کا نام نہ لیں۔ گاندھی جی ہمارے پاس سے چلے گئے، لیکن جہاں پر بھی ہیں، ان کے دل کو یہ تکلیف پہنچتی ہوگی کہ لوگوں نے کیسے کیسے اعلان کر رکھے ہیں۔

بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ مجھے جانا تھا اس لئے میں نے آپ سے گزارش کی تھی۔]

उपसभाध्यक्ष (पूरे . पी.जे. कुरियन): बहुत -बहुत धन्यवाद
अदीब जी। श्री मैसूरा रेड्डी।

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Thank you very much, Sir.

Sir, I think, today is the 12th day of Shri Anna Hazare's Aanshun. When I was a Member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly, I also undertook fast for 13 days with a glass of water, lime juice and salt for the development of the backward region of Rayalaseema. The fast was up to the sine die of the Assembly Session.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It means, you have

experience in fasting.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: I have the personal experience.

I undertook it for 13 days. Of course, when the House was adjourned *Sine Die*, we broke our fast.

So, I appeal to Anna Hazare also not to cross that '13 days' limit. With the acquaintance of Anna Hazare group, I had also introduced the Jan Lokpal Bill in this very House. Anyway, Sir, in democracy, give-and-take policy should be there. In view of the constitutional limitations and also in view of the federal structure where States are also involved in this matter, I appeal Shri Anna Hazare, through my good friends, to end his fast, because, I am sure, they have sufficiently brought the issue to the notice of both the Houses of Parliament.

Coming to the Bill – the Government requested our party's point of view – I would like to submit that the Prime Minister should also be brought within the purview of the Lokpal with limited safeguards. We can leave this to the Standing Committee. The Standing Committee can decide what sort of safeguards should be provided to the Prime Minister.

With regard to selection process, I would like to submit, we strongly feel that majority of the Government should not be there, because our party feels that it is like accused appointing his own Judge. It will be like that. That is the reason why our party feels that there should not be any majority for the Government in the selection process of Lokpal.

Coming to the issue of Judiciary, our party is in conformity with the Judicial Commission and also the Judicial Accountability Bill.

Coming to the issue of conduct of Members of Parliament inside the House, we are in conformity with the House procedures. So, there is no need that the conduct of Members within the House is brought under the purview of the Lokpal. This is our party's view.

Regarding the issue of Lokayukta, I would submit that it is a State Subject. In any way, the Lokpal Bill, with an enabling provision, can become a model Bill which States can adopt. Already, Sir, Andhra Pradesh is having the Lokayukta. I have gone through the provisions of

Lokpal, the Jan Lokpal and Lokayukta of Andhra Pradesh. With a little bit of amendments, we can bring Lokayukta to the level of Lokpal.

Coming to the issue of public servants, I would like to submit, if a public servant is guilty of an allegation, the Lokpal for the Central Government employees and Lokayukta for the State Government employees can report to the appropriate Government. And the Government concerned can impose such punishments as prescribed by law and the Action Taken Report can be sent to the Lokpal/Lokayukta as the case may be. We are accepting this provision. That is not a problem with regard to the provision relating to public servant. The Lokayukta of Andhra

Pradesh and Karnataka are adopting this model. Without probing or investigation, the Lokyukta sending their recommendations to the appropriate Government and the Government, after taking action, can send the ATR to Lokyukta. That is sufficient for circumventing the constitutional obligation.

Regarding the public grievance and seizure and search, I would say that it is the most contentious issue and is the main reason behind people's knee-jerk reaction to Anna Hazare's fast. Why the people wanted a stringent Lokpal is also because of this. Previously, when we were in Government, the Citizens Charter was implemented in majority of departments with imposition of fine, wherever applicable. If the Government wants to bring Redressal Bill, there should be an enabling provision for the States to adopt such type of Citizen Charters and redressal mechanism, so that the federal structure is maintained. Our party is of the opinion that Lokpal alone cannot root out corruption. The other legislations can also be brought in simultaneously. Electoral reforms are very important to prevent money power in politics. Because of the liberalization policy many corporate entities are sending money from India to other tax haven countries so that the same can be brought back in the form of legal money. So, the laws may be amended accordingly. Then, the corporate sector can also be brought within the ambit of Lokpal. Along with the Lokpal Bill, all these things can be considered. On three items also we have given our party's opinion.

Thank you very much, Sir, for having given me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Next is Shri Ravi Shankar Prasad. Ravi Shankarji, if you agree, can I call Dr. Bharatkumar Raut because he has to board a flight?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): No problem, Sir.

DR. BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. Thank you, Ravi Shankar Prasadji, for having given me this opportunity out of turn.

At the outset, on behalf of my party, Shiv Sena, and on my own

behalf, I appeal hon. Anna Hazare to withdraw his fast immediately and let the parliamentary proceedings take place so that an effective Lokpal Bill can be passed.

We support a strong Lokpal Bill, which will remain within the framework of the Constitution. More importantly, it would not be superior to Parliament. We also support Anna's demand to bring the lower bureaucracy under the purview of Lokpal because for *aam aadmi*, common man, the Prime Minister is not an issue, whether he should come under the purview of the Lokpal or not; for him, the local *babu*, the local *tehsildar*, the *patwari*, etc. are the people who bother his

life. So, the men in the lower rung of the ladder of bureaucracy should come under the purview of the Lokpal. We also support uniform Lokayukta laws at the State level because Lokpal will not be able to give justice to everybody, to every small hamlet. Leaving a few Central Government employees, like, a man sitting on the railway booking window, or, a postman who comes to his house, rest of the *babus*, rest of the employees who are indulging in corruption, with whom *aam aadmi* has to deal with everyday, are all either State Government employees, or the *zila parishad* employees, or, the *gram panchayat* employees. Therefore, Lokayukta should be effective. All *babus* should come under that.

Having said this, I would like to come to point the that there should be a tool to remove Lokpal if found guilty and corrupt. Recently, the Rajya Sabha saw a High Court Judge being impeached. I would suggest that there should be a provision in the Bill, in the law by which the Parliament should be able to impeach a guilty Lokpal. There should be a control, otherwise, a Lokpal may become a monster; may become monarch of the country. Therefore, there should be a provision for impeachment in the law itself by which we will have a control over Lokpal. At the same time, all the people are not able to come to Parliament and impeach Lokpal. For that, there should be a special desk under the Chief Justice of India where common man's complaint against Lokpal or Lokayukta can be lodged. That should be another provision in the Bill.

Then, there should be a timeframe for investigating into a complaint filed by a citizen. Legal assistance should also be provided by the Government to a poor complainant because a poor man will not be able to fight a case till the Supreme Court. So, the Government should make a provision in the Budget by which a poor man may be provided financial assistance for legal battle. Lawyers should be provided to them. Sir, I will make two more points and I will conclude. Everybody has said that MLAs should be kept out of it. The CBI and the Judiciary should also be kept out of the purview of the Lokpal. But there should be a separate mechanism on the lines of CVC to control the CBI and the

Judiciary. The National Judicial Commission or something like that should be there so that these institutions don't remain in the hands of the Government and they don't become the subject of Government's will and wish.

The last point that I would like to say is that this Bill should not be passed in a hurry. It should not be passed under any pressure. We should have a positive discussion. Let people from all walks of life come together, put their minds together and form a very able and strong Lokpal Bill. If necessary, we can have a separate special Session, say, for a week, after the Monsoon Session or before the Winter Session to pass only the Lokpal Bill. But let there not be any hurry because this is a milestone decision that this House would be taking.

Sir, my last appeal to this House is that today we must pass a resolution. We should pass a resolution by which our commitment to the cause is conveyed. Mere discussion will only be a seminar. This Government, if it is reported correctly, had assured Shri Anna Hazare and his team that a resolution, by voting, will be passed. If we don't do that, then, that is a betrayal. No good cause can be started on the foundation of betrayal. So, it is the responsibility of the Government to pass a resolution so that we can honestly appeal to Shri Anna Hazare to withdraw his hunger strike and parliamentary procedure can proceed. Sir, I thank you very much for giving me time.

श्री रवि शंकर प्रसाद : उपसभाध्यक्ष जी, सुबह से बहस चल रही है। इस बहस में शालीनता है, एक सहजता है और एक संवाद भी है। हमारा संविधान बनाने वालों ने संसद को लोकतंत्र का प्रहरी बताया था। कानून यहीं बनेगा और हमसे कुछ मर्यादाओं की अपेक्षा की थी। आज हमारे जो मंत्री यह समझते हैं कि संसद में सिर्फ़ शोरगुल होता है, मैं उनसे बहुत वनिमता से वनिती करूंगा और अपील भी करूंगा कि वे सोचें, यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है और जब भी अवसर आता है, तब संसद अपनी मर्यादाओं पर खरी उतरती है, जिसका हमने आज परिचय दिया है। हमेशा हम अपनी बात कहने की आजादी है, अपनी बात कहें, खुलकर कहें, वरिध भी करें, संसद की आवाज सिर्फ़ एक बार बंद करने की कोशिश की गई थी 1975-76 में, जब पूरे देश के लोग जेलों में थे या बाहर थे। उसका क्या हशर हुआ यह हम जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मुझे बहिर में लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के साथ बहिर के आंदोलन में काम करने का अवसर मिला है। यहां पर शक्तिनन्द जी बैठे हैं, मंत्री जाबिर साहब बैठे हैं, हम सभी सक्रिय थे। 4 नवम्बर, 1974 को जे.पी. के ऊपर लाठी चली थी, नामाजी देशमुख ने उनको बचाया था, अगले दस पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई थी और एक दस के नोटिस पर 4 लाख लोग आए थे। स्वर्गीय धर्मवीर भारती की एक कविता मुन्नादी पढ़ी गई थी, मुन्नादी का मतलब होता है डुबडुगी। मैं उसकी तीन-चार लाइन पढ़ना चाहूंगा :-

खलकखुदा का, मुल्क बाश्शा का
हुकुम शहर कोसवाल का
हर खासो -आमको आगहकशि जाता है कि
खबरदार रहें

और अपने -अपने कविड़ों को अंदर से
कुंड़ी चढ़ा कर बंद कर लें
गशि लें खड़कियों के परदे
और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें
क्योंकि ,
एक चौहत्तर बरस का बूढ़ा आदमी
अपनी कांश्चती कमज़ोर आवाज में
सड़कों पर सच बोलता हुआ नक़िल पड़ा है !

यह सवाल था जय प्रकाश जी के बारे में आज यह 2011 का
हस्तिदुस्तान है यहां पर खड़कियों के पर्दे गशिने की
हस्मिमत अब कोई नहीं करेगा , लेकिन हमें यह बात बहुत ईमानदारी
से स्वीकार करनी पड़ेगी कि रामलीला

मैदान में जो 74 साल के अन्ना हजारे बैठे हैं , वे भी सच बोल रहे हैं , ईमानदारी से बोल रहे हैं , इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने हमें आइना देखने का काम किया है। यह बात मैं दलित से बोल रहा हूँ। गलतियां उधर से भी हुई हैं , कुछ हम लोगों से भी हुई हैं। हमने आंदोलन करने की कोशिश की , ईमानदारी से कहना पड़ेगा कि शायद कुछ कमियां हों। अगर नया स्टैडियम डेढ़ सौ करोड़ में बन जाता है और एक स्टैडियम के रफ़्तार में 980 करोड़ रुपए का खर्चा होता है , तो हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। देश हमसे सवाल पूछता है। अगर देश से बाहर लाखों , करोड़ों रुपए जमा हैं , हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं , तो देश हमसे सवाल पूछता है कि मेरी चाय से चीनी गायब है , मेरी रोटी की सब्जी गायब है , तो यह क्या हो रहा है ? देश के सामने ये बड़े सवाल हैं। इसीलिए हमें इन आलोचनाओं को इस तरीके से देखना पड़ेगा , ताकि हम अपने स्तर को सुधारें। आज लाखों नौजवान घूम रहे हैं , मुम्बई की सड़कों पर डेढ़ लाख लोग आ गए हैं। हम जानते हैं कि रैलियां करने में कतिनी कठिनाई होती है। अगर लोग इसके लिये नक़िल पड़े हैं , तो उनके दलित के दर्द को समझना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर वह दर्द संसद से जवाब मांगता है , तो संसद को जवाब देना चाहिए कि हम एक प्रभावी लोकपाल बिल बनाकर दिखाएंगे। अगर हमसे गलतियां हुई हैं , तो देश हमसे बात कर रहा है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। 42 साल बीते बहुत देर हो गई है। इसके अंदर प्रधान मंत्री को क्यों नहीं आना चाहिए , इस पर क्यों बहस होनी चाहिए ? लोग कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री को फंसाया जाएगा। माननीय उपसभाध्यक्ष जी , हब्दुस्तान को आजाद हुए 64 साल हो गए हैं , मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हमारे यहां IPC है और Prevention of Corruption Act है , क्या किसी प्रधान मंत्री पर false implication करने का कोई केस हुआ ? मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ ... (व्यवधान) ... मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष जी , मेरे पास तर्क भी हैं और तथ्य भी हैं , लेकिन मैं आज बहस का एक स्तर रखना चाहता हूँ , इसलिए बोफोर्स की चर्चा छोड़ दीजिए। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please let him speak.

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक को भी

falsely implicate नहीं किया गया। यह देश प्रधान मंत्री के पद का सम्मान करता है। हाँ, वंदिश नीति में, राष्ट्रीय सुरक्षा में और लॉ एंड आर्डर में आप जरूर अपवाद रखिए। जब एक गरीब आदमी वृद्ध -पेंशन के लिए जाता है, पट्टा लेबे के लिए जाता है, इन्कम सर्टिफिकेट लेबे के लिए जाता है, आवासीय प्रमाण -पत्र के लिए जाता है, इंदिरा विकास योजना में जाता है, तो उसको सबसे अधिक परेशानी होती है। फिर सभी कर्मचारी इसके अंदर क्यों नहीं आएंगे ? पास -पोर्ट आफिस से पास -पोर्ट बनवाने में कितनी परेशानी होती है ? फिर उन लोगों को इसके अंदर क्यों नहीं आना चाहिए ? इसका सिस्टम क्या होगा, आप इस बात पर चर्चा करिए, जो अरुण जेटली साहब ने कही है।

महोदय, इस देश के दो मुख्य मंत्री Public Service Act लाए हैं। एक मध्य प्रदेश के योग्य मुख्य मंत्री शक्तिराज सहि चौहान और दूसरे बहिर के मुख्य मंत्री, नीतीश कुमार जी लाए हैं। यह एक अच्छी बात है, मैं उनकी कद्र करता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बहिर में 15 अगस्त से Public Service Act लागू हुआ और 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में 2,80,000 आवेदन फाइल हो गए। जिनमें 1,21,000 आवासीय प्रमाण -पत्र के लिए थे, 70,000 कास्ट सर्टिफिकेट के लिए थे, 47,000 इन्कम सर्टिफिकेट के लिए थे। हमारा देश यह चाहता है कि हमें इनके लिए दक्षिण नहीं होनी चाहिए। इसलिए, जो सर्टिफिकेट चार्टर की बात है, वह

अच्छी बात है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अन्ना की तरफ से जो तीव्र मांगें रखी गई हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ और उन पर बहस नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आज देश जागा है। हमें देश की इस जागृति का सम्मान करना चाहिए। आज जो हमारे नौजवान घूम रहे हैं, इनके लिये हम तो बहुत कुछ कह सकते हैं, हमारी दूसरे साथियों ने बहुत कुछ कहा है। मैं इस पर कोई बहस नहीं करूँगा, लेकिन यदि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आज जो मुम्बई, दिल्ली, पटना, उत्तराखंड, बहिर, असम और लेह में इतने लोग अन्ना की टोपी पहनकर बैठे हैं, तो हमें उस दर्द को समझना चाहिए। वह दर्द यह है कि एक प्रभावी लोकपाल आना चाहिए। मुझे दो बातें और कहनी हैं, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हम मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। इस देश में मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। भ्रष्टाचार को उजागर करने में जहाँ वक्श ने या जनता ने काम किया, वहीं मीडिया ने भी किया है, इसलिए मैं मीडिया का भी सम्मान करना चाहता हूँ। मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि वह अपने अंदर झाँक कर देखे कि वह पेड न्यूज क्यों चलता है? पेड न्यूज भी चले और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में मीडिया की बात करेंगे, तो मीडिया के लोग मुझे क्षमा करें, अगर सफ़ॉन्सर्ड सम्पादकीय चलेगा और पेड न्यूज चलेगा तो प्रेस की आजादी कभी मजबूत नहीं रहेगी। यह बात समझनी बहुत जरूरी है। इसलिए उनको भी समझना पड़ेगा। चतुर्वेदी जी, मैं एक प्रदेश का चुनाव प्रभारी था। एक दल एक ही अखबार में, एक ही पेज पर, एक ही विधान सभा क्षेत्र से, आपकी पार्टी का उम्मीदवार भी जीतता है और मेरी पार्टी का उम्मीदवार भी जीतता है। हमने कहा कि यह कैसे हो सकता है, भाई? आप समझते हैं, इसका मतलब क्या है? मुझे NGOs के बारे में भी बात करनी है। मैं NGOs का सम्मान करता हूँ। NGOs ने बड़ा काम किया है, They are doing very good work. बहुतों को विदेश से भी पैसे मिलते हैं, बहुतों को हर्बिस्टान की सरकार से भी पैसे मिलते हैं। उनकी क्या accountability है? क्या वहाँ करप्शन नहीं है, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर का, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसका बिल्कुल unwieldy ही

कीजिए , लेकिन आज कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बहुत से लोग जेलों में बंद हैं , 2 जी में , 3 जी में , पी जी , जसिमें छोड़ दीजिए , ये वे लोग थे जो corporate governance पर बड़े-बड़े भाषण दिया करते थे। उनकी कम्पनी में कहा गया होगा कि, “We strongly believe in the elements of corporate governance.” और आज उनके लोग कहां हैं , यह हम भी देख रहे हैं। अगर यह देश जागा है तो हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी , आज पोलिटिशियन्स की साख गरी है , हम चाहते हैं कि उस साख को बनाएं , हम सब लोग उसमें काम करें। मैं अन्ना जी से बहुत वनिमता से अपील करूंगा कि आपने देश को दशा दी है कि आप जागिए , मैं उनके समर्थकों से और देश के लोगों से आग्रह करूंगा कि कतिनी भी कमजोरी हो , यह देश लोकतंत्र से चलेगा , चुनाव से चलेगा , संसद से चलेगा , संविधान से चलेगा , बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी , माननीय वरिष्ठ नेता प्रणब बाबू ने , जो कि सरकार के वस्ति मंत्री हैं , आज यहां पर जो शुरूआत की और सदन में लोकपाल विधियक पर जो चर्चा हो रही है , उस पर मैं अपने विचार रखने के लिये यहां प्रस्तुत हुई हुई महोदय , माननीय श्री अन्ना हजारे साहब की नीयत में यहां किसी को कोई शुभहा नहीं है , हम जानते हैं कि वे देश भक्त हैं , उन्होंने ऐसे आंदोलन पहले भी चलाए हैं और समाज में एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई है , लेकिन उनके साथ जो उनकी टीम काम कर रही

हैं, जो खुद की पहचान टीम अन्ना के नाम से बना रही हैं, हमें उन पर संदेह है। महोदय, एक बार अन्ना हजारे जी मुझे पार्लियामेंट अनेकसी में मंजूर थे, बलि की मीटिंग से आ रहे थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि, अन्ना साहब, आप इतने बड़े सामाजिक नेता हैं, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि इस देश में इतने वर्ग, इतने समाज रहते हैं, SC/ST/OBC, Minority, किसान वर्ग, महिलाएं आदि तब क्या कारण हैं, ऐसी क्या वक़िशता रही कि एक ही परिवार के पति और पुत्र आपकी सखि ल सोसायटी में, पांच सदस्यों में जगह पाने में कामयाब हुए? क्या इतने बड़े देश में आपको अलग-अलग जगहों से, अन्य वर्गों से ऐसे पांच ईमानदार लोग नहीं मंजूर?... (व्यवधान) ... क्योंकि मैं यह कहना चाहती हूँ ... (व्यवधान) ... अन्ना साहब एक भले और सीधे व्यक्ति हैं ... (व्यवधान) ... बताइए, आपसे एक महिला का बोझना भी बर्दाश्त नहीं होता है। ... (व्यवधान) ... सर, इन्होंने बीच में जो इतना समय लिया है, वह मेरे दस मिनट में से अलग काट दिया जाए। अगर मैं गलत बात कह रही हूँ तो आप बोल दीजिए। महोदय, जो टीम अन्ना में जगह पा गए हैं या जख़्ख़ोंने जगह बनाई है, उन्होंने भले, सीधे, सरल स्वभाव के अन्ना साहब को भी जरूर कहीं मसिलीड किया होगा, गुमराह किया होगा, इसीलिए वे कहीं उनके भ्रम में आ सकते हैं। आज वे लोग पूरे देश को भी कुछ मुद्दों पर गुमराह कर रहे हैं, मैं आपको वे मुद्दे बताना चाह रही हूँ कि वे कबि-कबि बातों पर गुमराह कर रहे हैं। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम तो एक सखिल सोसायटी के सदस्य हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि वे कौन-सी सखिल सोसायटी के चुने हुए सदस्य हैं, क्या यह भ्रमक बात नहीं है? आज इस संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, जो माननीय संसद सदस्य हैं, क्या वे सखिल सोसायटी के चुने हुए जन प्रतिनिधि नहीं हैं? क्या वे आर्मी की तरफ से चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं? वे कौन हैं? वे कहते हैं कि जख़्ख़ी संख्या 800 भी नहीं है, वे पूरा देश चला रहे हैं। वे यह भ्रम क्यों फैला रहे हैं? इस देश की जो 120 करोड़ जनता है, उसके चुने हुए जन प्रतिनिधि, 120 करोड़ लोगों के समर्थन से यहां बैठे हुए हैं, यहां कोई 800, पौने आठ सौ लोग नहीं बैठे हुए हैं। वे संसद के बारे में इस तरह की बात कहकर संसद का भी कहीं अपमान करते हैं। वे साथ ही उस जनता का भी

अपमान करते हैं , जसिने अपनी ओर से इन जन प्ररतिनिधियों को चुनकर इस संसद में भेजा है। महोदय , मैं कहना चाहती हूँ कि वे एक बात कहते हैं कि सरकारी बल्लि नहीं चलेगा , तो कौम सा बल्लि चलेगा ? बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान की व्यवस्था बनाई , जो इतने वर्षों से चली आ रही है , जसिके तहत इतने वधियक और कामून बने हैं , उसी के तहत तो बनेंगे कामून। अब वे कसि नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं ? अगर सरकारी नहीं चलेगी , तो क्या कसि भी दादागिरी की व्यवस्था चलेगी ?

अन्ना साहब तो एक भले व्यक्ति हैं , लेकिन टीम अन्ना में पता नहीं कौम -कौम लोग हैं ? केजरीवाल साहब रोज़ इतना बोझ रहे हैं , गरज रहे हैं। केजरीवाल साहब और टीम -टीम करोड़पति लोग टीम अन्ना में बैठे हुए हैं। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है ? इतना लंगर चल रहा है , हजारों लोग खाना खा रहे हैं , वहाँ इतने बड़े - बड़े टेंट लगे हुए हैं। ज़रा टीम अन्ना बताए कि यह सब खर्च कहाँ से हो रहा है ? महोदय , मैं यह पूछना चाह रही हूँ ... (व्यवधान) ... मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को भी असलियत बताना चाह रही हूँ कि ... (व्यवधान) ... आप क्यों नाराज होते हैं ... (व्यवधान) ... सुनिए , महिला का सवाल नहीं है। महिला को घर सँभालना भी आता है और यहाँ संसद सँभालना भी आता है। आपइससे परेशान मत होइए , लेकिन आपतो ऐसे परेशान हैं , जैसे इस अभियान में कहीं आपका योगदान है। ... (व्यवधान) ... क्या बात है ? आपइतने

7.00 P.M.

परेशान क्यों हो रहे हैं ?... (व्यवधान) ... इतनी परेशानी किस बाह्य की है ? आप बताइए कि आज तो अन्ना साहब हैं , कल कोई और आ गया , परसों कोई और आ गया , सखिल सोसायटी के नाम पर कोई भी मुँह उठाए चला आएगा। कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं , कई ऐसे महान लोग हैं , जन्हें कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिये गलत बयानबाजी करके यहाँ ले आएगा। दिल्ली के लोग परेशान हैं , रोज हजारों लोगों के धरने हैं , बच्चों का स्कूल -कॉलेज जामा मुश्किल हो रहा है। महोदय , यह क्या व्यवस्था हो रही है ? कभी वे कहते हैं कि सरकारी बस्ति नहीं चलेगा , कभी वे कहते हैं कि सांसद 'चोर' हैं , सांसद 'लुटेरे' हैं। क्या उनको यह कहना शोभा देता है ? केजरीवाल साहब से मैं कहती हूँ कि बुजुर्ग अन्ना साहब कब से अनशन पर बैठे हुए हैं , कृपा करके कम-से-कम उनको योगदान देते हुए , आपमें बहुत ताकत है , आप गरज रहे हैं , उनके साथ आप कुछ दखि के लिये अनशन पर तो बैठ जाइए और उनका साथ दीजिए। आप ज़रा अनशनमें भी उनका साथ दीजिए। ... (व्यवधान) ...

महोदय , वे कह रहे हैं - जन लोकपाल बस्ति। लोकपाल बस्ति और जन लोकपाल बस्ति में क्या फर्क है ? जन का अर्थ भी लोक है और लोक का अर्थ भी जन है। अर्थ किसने निकाला ? केजरीवाल साहब या टीम अन्ना के दूसरे सदस्यों को शायद हब्बिदी की जानकारी नहीं। जन लोकपाल और लोकपाल का एक ही अर्थ है। उधर जन जनपाल बिल हो गया। ... (व्यवधान) ... सुनिए , भ्रष्टाचार भारत छोड़ो ... (व्यवधान) ... हम सब कह रहे हैं। मैं आप पर थोड़े ही comment कर रही हूँ। मैं तो देश की जनता को बता रही हूँ। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, do not create problem. ... (Interruptions) ...

डॉ. प्रभा ठाकुर : ये ऐसे ही चढ़ते हैं। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ , जब मैंने यह सुना। कल राहुल जी ने बड़े सधे हुए तरीके से अंतरात्मा की आवाज से बोला , जो हर सांसद का अधिकार है और चेयर की permission से बोला। आज इतनी सीनियर वरिष्ठ नेता वहाँ पर सवाल कर रही हैं , चेयर को चुनौती दे रही हैं कि राहुल जी कौन हैं , उनको इतना समय क्यों दिया गया ? ... (व्यवधान) ... मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान) ...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, she is commenting upon...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, let me listen to him. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, she is commenting upon the speech made by a Member in the Lok Sabha. ...(*Interruptions*)... We have maintained decorum during this debate; let that decorum be maintained. All other Members have maintained that decorum. I would request the hon. Member to maintain that decorum too. ...(*Interruptions*)...

डा॰ प्रभा ठाकुर : वकील साहब तो बहुत पढ़े-लिखे हैं , लेकिन मैं भी जनता की वकालत कर रही हूँ ...(*व्यवधान*)... मुझे अदालत की वकालत नहीं आती ...(*व्यवधान*)... लेकिन मैं लोक अदालत की वकालत करना जानती हूँ ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, sit down. ...*(Interruptions)*... Dr. Prabha Thakur, you cannot refer to the speeches made in the other House and criticize a Member. ...*(Interruptions)*... A standard has been maintained today in the discussion; please, maintain that standard.

डा॰ प्रभा ठाकुर : ठीक है, सर, जैसा स्टैंडर्ड उन्होंने बना कर रखा है, वह स्टैंडर्ड मैं भी पूरी तरह बना कर रखूंगी।

सर, मेरा आपसे नविदन है कि अकेले लोकपाल के बनने से ही सारा भ्रष्टाचार दूर नहीं हो जाएगा। भ्रष्टाचार मछिने के लिये क्या आसमान से भेजा हुआ कोई लोकपाल आएगा या कोई फरिश्ता आएगा? अगर ऊपर से कोई फरिश्ता आ रहा हो, तब तो हम भी विश्वास कर सकते हैं (समय की घंटी)। लोकपाल कौन होगा? जैसे हममे से कोई लोग हैं, वैसा ही होगा। जब आपको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, प्रधान मंत्री में विश्वास नहीं है, संसद में विश्वास नहीं है तो लोकपाल में विश्वास कैसे और किस आधार पर कर सकते हैं? उनको कौन-सी जनता चुन करके यहां भेजेगी, जो प्रधान मंत्री जी के भी हिसाब-कत्तिब करेगी, सांसदों के आचरण के भी हिसाब-कत्तिब करेगी।

महोदय, प्रधान मंत्री जी पर कोई उंगली नहीं उठ सकता। उनके ऊपर कोई किसी तरह की तोहमत नहीं लगाई जा सकती। लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सांघ को आंघ नहीं होती और झूठ के पांख नहीं होते।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now please conclude. ...*(Interruptions)*... आपका टाइम हो गया ...*(व्यवधान)*...

डा॰ प्रभा ठाकुर : महोदय, मेरे पांघ मलिट तो उन लोगों ने ले लिये ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन) : नहीं, नहीं। आपका टाइम हो गया है, समाप्त कीजिए।

डा॰ प्रभा ठाकुर : सर, एक बात मैं अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी। उनका अपना कोई दोष नहीं है। उनका दोष इसलिए नहीं है कि वे क्या करें, वे तो उनके टीबी के मल्लिकों के टीआरपी के कायदों से बंधे हुए हैं। मैं यह कह रही हूँ कि अगर लोकपाल के दायरे में लोकतंत्र के चार मजबूत स्तम्भ ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन) : बैठिए, बैठिए। Please

conclude. ...(Interruptions)...

डा॰ प्रभा ठाकुर : लोकतंत्र से चार मजबूत स्तम्भ कहे जाते हैं - संसद , न्यायपालिका , ब्यूरोक्रेसी और मीडिया। जब इनमें से तीन का नाम उन्होंने लिया , तो मीडिया को क्यों छोड़ दिया ? इसके अंतर्गत चारों का नाम लिया जाना चाहिए , तब जाकर...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Take your seat. ...(Interruptions)... बैठिए ...(व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर : नहीं , मीडिया की आजादी पर हमला नहीं होना चाहिए। मीडिया की टीआरपी पर जरूर हमला हो सकता है , आजादी पर हमको कोई हमला नहीं चाहिए , ताकि एक ईमानदार ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन) : अब बैठिए , हो गया , बस अब समाप्त कीजिए ...(व्यवधान)...

डा०. प्रभा ठाकुर : सर, अंत में मैं कहूंगी कि अन्ना जी पूरे समाज को शपथ दिलाएं। समाज में भ्रष्टाचार की यह मान्यता हो गई है कि आज हमारी महिलाएं बैठ कर कहती हैं कि हमारी बेटी का होने वाला जो पति है, उसे 10,000 सैखरी मिलती है, लेकिन ऊपर की आमदनी 30,000 की है। इसे गर्व से कहा जाता है। यह बात समाज में आ गई है, तो कैसे बदलाव होगा, आप ही बताइए ? दहेज के लिए गर्व किया जाता है कि हमें एक करोड़ का दहेज ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Take your seat. ... (Interruptions) ... बस, बैठिए ... (व्यवधान) ...

डा०. प्रभा ठाकुर : अन्ना साहब पूरे समाज को शपथ दिलाएं, नौजवानों को शपथ दिलाएं और यह शपथ दिलाएं कि वे अपने-अपने घरों में पूछें कि कहीं कोई रश्वत की कमाई तो नहीं आ रही है, ऊपर की कमाई तो नहीं आ रही है ... (व्यवधान) ... अंत में मैं बस चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : नहीं, नहीं, बस हो गया, और कतिना अंत में ... (व्यवधान) ... आप बैठिए। आपका टाइम ओवर हो गया है ... (व्यवधान) ...

डा०. प्रभा ठाकुर : सर, एक शेर तो सुब लीजिए, मैंने अभी-अभी खुद लिखा है ... (व्यवधान) ... केवल चार पंक्तियां हैं, अभी लिखा है, आप भी सुनिए, सर:

देश भक्त हैं अन्ना साहेब, टीम दे रही धरना साहेब।
कब्तु कभी पूछिए अपनी टीम से, क्या है छुपी तमन्ना साहेब।।

श्री शशिनन्द तिवारी : महोदय, हम कांग्रेस पार्टी और सरकार से जामना चाहते हैं कि आखिर यह जो उपवास है और जो लोकपाल है, इनके बारे में सरकार की नीति क्या है? एक तरफ तो भाषण हो रहा है कि लोकपाल बनना चाहिए और हमने सुना है कि कोई प्रस्ताव भी आ रहा है, रैजोल्यूशन आ रहा है और अपील की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भाषण करवाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हम यह जामना चाहेंगे ?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): What she has said is her opinion only. Don't worry about that. ... (Interruptions) ... In

Parliament, everybody is free to speak. Party's stand will be known later.

श्री रामविलास पासवान : उपसभाध्यक्ष जी, अन्ना जी का यह जो अनशन या आन्दोलन चल रहा है, उसका मेरा मकसद क्या है, यह अभी तक मेरी समझमें नहीं आया है। कहा जा रहा है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन है जो गरीब भूख से मरते हैं, क्या वह भ्रष्टाचार नहीं है? दलितों, अकलियतों और पछिड़ों के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं, क्या वे भ्रष्टाचार के अन्दर नहीं आते हैं? भ्रष्टाचार के अन्दर यदि घूसखोरी है तो ये सीरी चीज़ें भी भ्रष्टाचार के अन्दर ही आती हैं। आजसबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ तीन चीज़ें हैं – पहली वधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। वधायिका ही एक ऐसी ताकत है, जसमें बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी आदि सब लोगों का योगदान था और जन्होंने 'एक व्यक्ति एक वोट' का अधिकार दिया। कोई चाहे राजा हो या रंक हो, उसे एक ही वोट देने का अधिकार है, equal rights and equal value. सबको equal value दिया गया है। उस समय भी बहुत डबिट चल रही थी, जैसे

आज नारा लगाया जाता है, कि इस देश में जो मूर्ख लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, सिर्फ पढ़े-लिखे लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया जाए, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं माना और वोट देने का अधिकार सब को दिया गया। उसका नतीजा है कि आज न्यायपालिका में दलित वर्ग के लोगों की संख्या ज़ीरो है, कहीं-कहीं हाईकोर्ट वगैरह में एकाध होंगे, लेकिन पछिड़ी जातियों के लोगों की संख्या ज़ीरो है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कभी आ जाते हैं, जैसे दलित वर्ग के बालाकृष्णन जी आ गए। उसी तरीके से इसमें ट्राइबल लोगों की संख्या भी ज़ीरो है। जो कार्यपालिका है, उसमें भी क्लास वन और क्लास टू सर्विसेज़ में पछिड़ी जाति के लोगों की संख्या चार परसेंट है। इसमें रजिर्वेशन के कारण शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। इनकी जो संख्या है, वह क्लास थ्री और क्लास फोर सर्विसेज़ में है। क्लास थ्री और क्लास फोर सर्विसेज़ में ही दलित, ओबी.सी. और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। अब उसमें भी यह षडयंत्र करने की साजिश हो रही है कि उनको भी लोकपाल के अन्दर ले आओ, जिससे वे भी एक तरह से साफ हो जाएँ। इसलिए, मैंने कहा कि जो कार्यपालिका है, उसमें भी इनकी संख्या कम है। कुछ मन्त्रिण एक जगह वधायिका ही है, जिसमें दलित, पछिड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग इसके लिए कोई कास्ट सिस्टम – अभी शकिनन्द तकिरी जी बोझ रहे थे। हम लोगों के नेता मधु लक्ष्मिये थे, जो कि ब्राह्म मण थे। इसी तरह मामा बालेश्वर दयाल, एस.एम. जोशी, मधु दंडवते, मृणाल गोरे और प्रेमिला दंडवते सभी ब्राह्मण थे, लेकिन ये सभी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे और ये नारा लगाते थे कि 'संसोपा ने बाँधी गाँठ, पछिड़ा पात्रे सौ में साठ'... उस समय यह नारा लगाया जाता था। हकीकत यह है कि जो वधायिका है, वहीं इनकी संख्या अधिक है, चूँकि सब को वोट का डर है। अब यह साजिश चल रही है कि वधायिका में जो इनका हस्तक्षेप है, जोकि कामून बनाने का एकमात्र रास्ता है, लोक सभा, राज्य सभा, वधान सभा और वधान परिषद्, उनमें किसी तरीके से इनको खत्म किया जाए। उसके लिए यह बाई पास रास्ता निकाला जा रहा है।

सर, मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर है। अभी हमारे एक साथ ने अन्ना हज़ारे जी के सम्बन्ध में कहा। अन्ना हज़ारे जी

की टीम में स्वामी अग्निवेश जी हैं। मैं स्वामी अग्निवेश जी को जानता हूँ। वे एक सोशल वर्कर हैं। उनमें वहीं एक आदमी है, जसि पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे माओवादियों के भी समर्थक हैं और गरीबों के भी समर्थक हैं, बाकी लोगों के सम्बन्ध में हमें नहीं मालूम है। एक जस्टिस हेगड़े भी हैं। स्वामी अग्निवेश जी ने क्या कहा है? यह मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इसमें से कोट करता हूँ। "Agnivesh said, "A 'coterie' was dictating to Hazare, and hatred and contempt for the political class had crept in which was unbecoming." "Anna's credibility is being dented. There is a hardening of attitude by a small coterie," he said.

"When we began talks, it was understood that we would lobby only for introduction of the Lokpal bill but that has changed now. I have chosen to disassociate myself from the group because of this," Agnivesh said. He added that the campaign was increasingly becoming anti-minority and anti-backward classes." यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह स्वामी अग्निवेश जी कह रहे हैं। "I have spoken to a number of MPs and dalit, OBC and Muslim leaders who feel that there is a shrinking of space for them. They feel that this campaign is dictating to Parliament, taking away whatever little space that they have," Agnivesh said. इसमें बहुत लखि है।

महोदय , मैं कहना चाहता हूँ कि वहां ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं , जो reservation के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। मनुस्मृति के जरिए , वर्ण व्यवस्था के जरिए गाली देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों के बारे में तो कहा ही जाता है कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हुए हैं , वे सब uncivilized हैं , जैसे सिर्फ वे ही लोग civilized हैं।

महोदय , मेरे पास जन लोकपाल बिल की कॉपी है। इसमें सेलेक्शन का जो procedure रखा गया है , उसके अंतर्गत सेलेक्शन कमेटी में पांच सदस्य होंगे और पांच सदस्यों के अलावा judges होंगे। उसमें Judges के अलावा जो पांच सदस्य होंगे , उनमें इन्होंने CAG को रखा है , Chief Election Commissioner वगैरह को रखा है। उसमें कोई एम.पी. नहीं रहेगा। एम.पी. के संबंध में यह कहा गया है कि यदि एम.पी. योग्य भी होगा , तो भी उसको Chairman नहीं बनाया जाएगा। हम लोग कहा जा रहे हैं ? उसमें एक भी scheduled caste का सदस्य नहीं रहेगा , एक भी scheduled tribe का सदस्य नहीं रहेगा , एक भी backward class का सदस्य नहीं रहेगा , एक भी minority का सदस्य नहीं रहेगा। ये सब लोग मिला कर अपना coterie बना कर जसिको चाहेंगे , उसको सदस्य बनाने का काम करेंगे। ये लोग पार्लियामेंट को by-pass करने जा रहे हैं। इसलिए , मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। हम सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं , लेकिन भ्रष्टाचार की आड़ में जसि तरीके से काम किया जा रहा है और जसि तरीके से weaker sections के लोगों के हितों के ऊपर हमला किया जा रहा है , हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा बनाए गए संविधान की कसम खाए हैं और अगर कोई संविधान का उल्लंघन करने का काम करेगा , तो हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे।

महोदय , अभी हमारे साथियों ने कहा कि 43 साल में 8 बार इसी पार्लियामेंट में लोकपाल के संबंध में बिल आया। यह 1968 में आया , 1969 में आया , 1971 में आया , 1977 में आया , 1985 में आया , 1989 में आया , 1990 में आया , 1996 में आया , 12वीं लोक सभा में आया और 13वीं लोक सभा में भी आया। उनमें से तीन बार यानी 1989 , 1996 और एनडीए के समय में , यह कहा गया कि प्रधान मंत्री को इसके अंतर्गत रखा जाए। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी यह राय है कि इसके अंतर्गत प्रधान मंत्री को नहीं

रखना चाहिए। हो सकता है कि 10 साल या 20 साल के बाद लोगों को इसके बारे में पता चले। अगर हमेशा brain haemorrhage होता रहेगा, तो शरीर कैसे काम करेगा? प्रधान मंत्री देश का गौरव होता है। आज इस पक्ष का प्रधान मंत्री है, तो कल उस पक्ष का प्रधान मंत्री होगा। कोई भी चाहेगा, तो वह प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप लगा देगा। आरोप सही हो या गलत, लेकिन उसका क्या moral standard रहेगा? यह पार्लियामेंट है, यहां अविश्वास का प्रस्ताव आता है या नहीं आता है? पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है? हम पार्टी को चुन देते हैं, जो पार्टी बहुमत में आती है, वह पार्टी अपने नेता को चुनती है और वही नेता देश का प्रधान मंत्री बनता है या राज्य में संबंधित राज्य का मुख्य मंत्री बनता है। वह अपनी कैबिनेट को चुनता है और वह कैबिनेट सरकार कहलाती है। अगर बदलाव करना है, तो पांच साल के बाद फिर चुनाव होगा और फिर सरकार आएगी। मायावती जी ने ठीक कहा कि 2014 का इंतजार कीजिए। 2014 में चुनाव लड़ने का काम कीजिए। लेकिन, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। (समय की घंटी)। सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): आपके 10 मिनट हो गये, इसलिए कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : जब हम शुरू करते हैं और हमारा tempo आता है तब आप हमारा tempo खत्म कर देते हैं... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आपका tempo 10 मिनट के बाद आता है ? Tempo पहले आना चाहिए।... (व्यवधान)...

श्री रामविलास पासवान : सर, यह जो इनका चार्टर बना है, इस चार्टर को आप पढ़िए। इसमें यूएनओ का सब कुछ दिया है। अगर आपने चार्टर में यूएनओ का सब कुछ दिया है, तो उस चार्टर से आपने एनजीओज़ को बाहर क्यों रखा है ? क्या एनजीओज़ भगवान के धोये हुए हैं ? हमने तो उस दबि भी कहा था। अभी हमारे साथी ने मीडिया के paid news के संबंध में कहा, ये जतिने big business houses हैं, उनके संबंध में कहा और NGOs के संबंध में कहा। हाथी नकिल गया है, अब आप पूछ के लख लड़ रहे हैं ? (समय की घंटी)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, please conclude it now.

श्री रामविलास पासवान : प्रधान मंत्री के नाम पर सहमति हो गयी, judiciary के नाम पर सहमति हो गयी, अब जो तीन चीज़ें हैं, मैंने तीन चीज़ों के संबंध में सुना है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, please.

श्री रामविलास पासवान : सर, मैं बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ जो छोटे कर्मचारी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके संबंध में कोई एकमत है। क्या छोटे कर्मचारी को लोकपाल देखेगा ? अगर खटमल काटेगा, तो क्या आप शेर को मारिएगा ? नीचे जो लोकायुक्त है, क्या वह काम नहीं करेगा ? क्या सरकार के पास कोई और मशीनरी नहीं है कि आप इसे एक मूँछ का प्रश्न बनाये हुए हैं ? (समय की घंटी)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, please.

श्री रामविलास पासवान : सर, मैं अब खत्म कर रहा हूँ ये जो तीन चीज़ें हैं, जो छोटे कर्मचारियों का मामला है, जो यह कहते हैं कि कानून बने, राज्य सरकार कानून बना रही है। लोकायुक्त की जो बात है, हमने किसी को यह कहते हुए नहीं सुना है कि लोकायुक्त को लोकपाल के अन्दर लाया जाय उसकी नयुक्ति लोकपाल करे। इस चीज़ में अब कोई तर्क नहीं बचा है और इनको प्रार्थना की जा रही है। प्रधान मंत्री कहते हैं,

अन्ना जी, मैं सैल्यूट करता हूँ। पार्लियामेंट कहती है कि हम सैल्यूट करते हैं। राज्य सभा में कहते हैं कि सैल्यूट करते हैं। इस तरह की unanimity कभी-कभी आयी है जहाँ लीडर ऑफ़ हाउस से लेकर लीडर ऑफ़ डिअपोजिशन तक सब आपको कह रहे हैं। (समय की घंटी) एक तरफ हम लोग प्रार्थना करते हैं और दूसरी तरफ आप गाक्षी देने का काम करते हैं। इसलिए सर, यह पूरा का पूरा जो आन्दोलन है, यह anti scheduled castes है। यह पूरा का पूरा जो आन्दोलन anti backward classes है। यह पूरा का पूरा आन्दोलन anti-tribal है, यह anti minorities है। ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): ओके।

श्री रामविलास पासवान: सर, अन्त में एक बात सुनिए। यदि यह लोकपाल बनने जा रहा है, तो सरकार अभी सुझाव ले कि सल्लेक्शन कमेटी से लेकर लोकपाल तक उसमें जितने लोग बहाल होंगे, क्या वे भगवान के यहाँ से आएँगे या खुदा के यहाँ से आएँगे या इन्हीं कर्मचारियों में से आप लेंगे, वह कर्मचारी करप्ट नहीं होगा,

इसकी गारंटी कौन ले सकता है? उन सबको अन्ना हजारे जी कहाँ से लाएँगे ? (समय की घंटी) इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब हमारे यहाँ scheduled castes, scheduled tribes and backward classes का 50 परसेंट आरक्षण है, तो मैं माँग करता हूँ कि उसमें महिला और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लीजिए। जब ये संशोधन और सारी चीजें मान ली जाएँगी, तब यह पास होगा, नहीं तो हम लोग उसको पास नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।

उपसभाध्यक्ष (प्रो . पी . जे . कुरियन) : रामविलास जी, आपका समय समाप्त हो गया। अब आप बैठिए। ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : अगर वे दस लाख लोगों को ला सकते हैं, तो हम लोगों की भी यह capacity है कि हम भी पचास लाख लोगों को बुला सकते हैं। ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (प्रो . पी . जे . कुरियन) : रामविलास जी, अब बैठिए। ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : सर, लोगों को जुटा कर कल कोई यह कह दे कि दलित का रजिर्वेशन खत्म करो, पछिड़ों का रजिर्वेशन खत्म करो, अक्लियत से देश की नागरिकता छीन लो, तो क्या हम ऐसा होने देंगे ? (समय की घंटी) हम यह कभी नहीं होंगे देंगे।

इसलिए सारा सदन एक साथ है। अन्ना जी को अपना अनशन वापस लेना चाहिए। उनके लोग, जो वहाँ बैठे हुए हैं, वे उनको मारना चाहते हैं। वे उनके बहकावे में न आएँ और जल्दी से जल्दी अपने अनशनको समाप्त कर दें ताकि उनकी टेंशन भी खत्म हो और हम लोगों की टेंशन भी खत्म हो।

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this particular issue. We have been discussing the importance of a strong and a very well thought-over institution to weed out corruption from this country. I was just listening to our learned friends from both the sides. Much has been said in the morning as to why there is a need for such a serious effort. It is not that there are no systems in place to curb the scourge of corruption. Because of its ineffectiveness, I think, we have to seriously determine to bring a strong Lokpal.

Sir, we have heard a number of speakers. I would like to basically

throw some light on very important aspects.

I am thankful to Mr. Yechuryji, Mr. Raja, and Mr. Ram Vilas Paswanji for throwing light on specific social justice angle and bringing it into the whole gamut of discussion, and also for highlighting the importance of social justice. We discussed this issue among our friends, among the Members of Parliament belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backwards Classes. We have given it the shape of a Bill. It is called Samajik Nyay Lokpal Bill. This morning we brought it to the notice of the House through the Secretary-General and the Chairman. We will give a copy of this Bill to the Standing Committee of Parliament for its consideration. We will also elaborate on various issues. We, Mr. Ram Vilas Paswanji, Mr. Raja,

Mr. Yechury, and other Members of Parliament, would request that this Bill should also be considered alongwith the Government's Bill, Annaji's Bill, Arunaji's Bill, and other Bills which are given by individuals and groups of individuals.

Sir, it is basically touching three-four issues. One is definition. Mr. Yechuryji mentioned that the existing definition should be widened. What is the definition? The Government's Bill is silent on definition. But the Jan Lokpal Bill does mention some sort of a definition. It defines maladministration as unreasonable, unjust, oppressive, or an improper, discriminatory action. Sir, we would like to further expand the definition to include denial of justice, denial of economic justice, denial of social justice, and denial of other forms of privileges which are enshrined in the Constitution. I would like to emphasise that discrimination is also a form of corruption. You are causing immense psychological reductionism by exposing an individual to undue delay in your decisions. Incriminating words and deliberately trying to deny the fruits of development should also form the gamut of description or the definition of corruption. Sir, in the morning it was mentioned that if you deny or divert the funds meant for the development of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and minorities, it should also be construed a definition of corruption. We also would like to urge the Standing Committee through you that the definition scope should also be enhanced to cover the corporate malpractices and malpractices of media. That is the focus. It cannot be a simple definition where we can ignore issues.

There is also concern for protection of whistleblowers. We are also concerned with the qualification part. In the appointment of Lokayukta, it is mentioned that it should be of impeccable integrity. Apart from impeccable integrity, we want a criterion that he should be free from unconstitutional caste bias. We have been experiencing it though we deny it in obvious terms. We do experience unwritten, unspoken discrimination based on extraneous consideration. For instance, in case of whistleblowers there is witch-hunting. There are people who complain against an officer belonging to low socioeconomic background. It is used against them. I can give you some statistics. In the Government of India, there are, as you said, 40 lakh employees.

For example, take the Class-I Officers. There are inquiries conducted by the CVC or the CBI. Recommendations for imposing major penalty have been sent to UPSC. If you look at the number of cases which go to UPSC for concurrence or opinion, you will find that 40 per cent of them are cases belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes officials whereas their population in the Government service is 10 per cent. Do you mean to say that they are four times more corrupt than general category officers? This is why, we would like these issues also to be addressed and addressed comprehensively not for the sake of the Act but it should be addressed substantially.

Sir, finally, we would like to say that the need of Lokpal is not only to enact it. Yesterday, my leader, Shri Rahulji, mentioned in the other House, and we do agree, that we should give a constitutional status to this institution. Right now, we will have a statutory status after enacting a strong Lokpal. But, in a span of one year, we can give it a constitutional status. The hon. Law Minister is here. I would urge upon him to take appropriate action to make it a constitutional body. He may recall that the former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, made the 73rd and 74th amendments in the same way. It was a statute for Panchayati Raj. But, we thought that it should be a constitutional body. So, that is why, the amendments were brought in. Now, we cannot give it a constitutional status at this stage. So, we will enact and provide it a statutory status. And, in the span of one year, it should be given a status of constitutional body and necessary amendment should be made.

Having said that, Sir, I would like to elaborate a little more on its nature. We have some concerns. Apart from the qualifications of judicial members, disqualification or appointment of Chairpersons and other members, age limit was nowhere mentioned in the three versions of the Bill. We must mention that a person should be mature enough to take such onerous responsibility. I suggest that it should be around 60 because they said that 25 years of legal or judicial experience is necessary. So, we should fix up the age. I agree with Mr. Paswan that in the composition of the Selection Committee, the Search Committee and the Lokpal including the staff which is going to be on deputation, there should be proportional representation to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBCs and the minorities because we do feel that the brunt of it is felt at the State level.

Sir, I would like to bring to the notice of this august House the types of corruption. Most of the money is spent at the State level and the District level. So, we should have a strong redressal of citizens' grievances mechanism at the District level. Each Department should notify the redressal officer. He should take up complaints for redressal. Sir, our friend, Shri Ravi Shankarji, mentioned that these

many applications have come up. Sir, after enacting a strong Lokpal, we must inculcate such moral values in ourselves that the Lokpal does not have any work. That is possible if we can make some effort to discipline ourselves, to bring in simplicity. That is what is always enunciated by my leader, Shrimati Sonia Gandhiji. We must be simple. We cannot have filthy exhibition of wealth. Sir, today, the youth is feeling that because of (*Time-bell rings*) liberalisation and privatisation, new vistas and new areas have come up in the ambit of corrupt practices. As Mr. Arun Jaitley has pointed out, now, there is underground mining, there is land development and also the waves are being sold. So, we should have reforms not only in the distribution of natural resources but we should also bring about reforms in the other sectors.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I would like to take a minute. Sir, just like we are saying whenever there is a complaint against a senior officer in the Lokpal.. we must refer it to the statutory body of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission or the Backward Classes Commission for the purpose of the double checking the veracity of the complaint.

I hope you are not going to bring the Office of the Prime Minister under the ambit of the Lok Pal. In case for some reasons, you want to bring with some safeguards, that safeguard should include a second look by a committee of judges of the Supreme Court because anybody can give a petition. It should be verified.

Secondly, the safeguard also should include any legitimate action of the Prime Minister to safeguard the interest of the weaker sections, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes and minorities. These are few things I would like to enumerate.

We want a strong system of electoral reforms, that is, funding of the political parties in elections. It has to be brought in through the electoral reforms; and also a national Act for corporate malpractices, corporate offences and media offences. All these things should be brought under a statute so that we are able to regulate various issues only then, Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have made all your points. Please take your seat.

SHRI JESUDAS SEELAM: You are only trying to shoot (*Time-bell rings*) We must address the roots of corruption only then can the Lok Pal can function effectively and fairly; otherwise the same thing will be repeated. This is my submission. Thank you.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, Shri Anna Hazare must be thanked and complimented for awakening our people to buttress against rampant corruption and ushering back hope and optimism back in our lives in place of despair, disgust, despondency and cynicism. As responsible parliamentarians, it is our duty to live

up to our people's expectations and to enact effective laws within the Constitutional framework that empowers the common man and makes him an agent for a change in our society. Sir, however the hopes from this Bill are so high that people are expecting instant *nirvana* with the passage of this Bill. Let us ensure that they are not disappointed.

Sir, my party Shiromani Akali Dal believes that this Bill will improve the governance and accountability which unfortunately has taken a back seat in recent years. Thanks to the major scandals which have been unearthed. Initially my party had reservations about the inclusion of the Office of the Prime Minister. Our concern was mainly due to the sensitive nature of the Prime

Minister's Office and also what the country has witnessed during the regime of Shri V.P. Singh, when his son was involved in a false case at St. Kitt's foisted by some unscrupulous people at the behest of a political party.

Sir, we will now go with the sense of the House, provided the Prime Minister is included for acts other than relating to the national security and public order. We feel that the judiciary should be kept outside the purview of the Lok Pal by creating a National Judicial Commission or a body of that nature for the appointment and accountability of the Judges.

Members of Parliament are given parliamentary privileges within the House in terms of the speech as well as their vote. Their probity for the in House conduct must be dealt with only by the Ethics Committee of the House. Misconduct or misdemeanor outside the House could come under the purview of the Lok Pal.

Sir, the process and criteria of selection of the Lok Pal is critical. After all any institution is as good or as bad as people manning it. Therefore, we cannot stress enough on the requirement for transparency in the manner of their appointment. There is no point in having a Government Lok Pal akin to the current CBI which symbolizes the State's failure to deal with corruption.

Inclusion of the lower bureaucracy within the Lokpal's ambit is not a matter of objection. However, we must realise that it could potentially be too immense an administrative burden for one institution to carry. There could be millions of cases referred to it, every year, while the machinery to deal with these would not be adequate. Already, there exists about 30 million cases pending with our Judiciary. Over 10,000 CBI cases lie unresolved; one-fourth of these have been pending for over ten years. This has led us today to have a total and utter contempt for the law. We must not have another non-performing vigilance body and we must ensure that the Lokpal is strengthened and given total budgetary support irrespective of the monetary cost.

Sir, the Constitution has given us a federal structure which must

be respected in, both, letter and spirit. We have to tread the path of the appointment of the Lokayuktas carefully. Regional parties are apprehensive that the office of the Lokayuktas may be misused to destabilize Opposition Governments in the States just as the appointment of certain Governors with political inclinations by creating confrontation or controversy in recent times. We fully support the citizens' charter as demanded by Shri Anna Hazare as we believe that in the final analysis, prevention is better than cure.

In our State of Punjab, we have recently enacted the Punjab Right to Service Act, 2011. Herein, we shortlisted 67 basic services relating to all the Departments of Police,

Revenue, Transport, Housing, Local Government, Health, Welfare of SCs/BCs, Social Security etcetera. Having identified these areas where there was a direct interface with the people, which would be breeding grounds of corruption, we ensure that every citizen has the right to these 67 basic facilities to be provided within a certain timeframe, barring which penalties are imposed on the concerned officers. Sir, 2,700 officers have been designated for these facilities. The Right to Identity Act and computerization of issuance of various licenses, permits like RTOs, DTOs, registration certificates of vehicles, land records etcetera, are now all available on line. It is effectively reducing the bureaucratic corruption that was prevalent in our system.

Sir, in the end, I would like to highlight that what we need today is a total systemic revamp. We can only succeed in this endeavour if (a) we reduce the discretionary powers, at all levels, by clearly defining our laws and rules; (b) improve governance and mitigate public harassment through a strong citizens' charter, and eliminate areas that breed corruption; (c) urgently address the failure of the State to improve the justice delivery system, and (d) while we all cherish and revere our democracy, however collectively we have created a situation where the elections have become prohibitively expensive, politicians are looked at with contempt. We must seriously introspect and bring simplicity back in our lives, both political and personal. Political funding through dubious sources is leading to a massive corruption. We must find ways and means for State-funding of elections and incentivise corporate donations to political parties via cheques.

In the end, Sir, I would say that there is a famous saying that among a people generally corrupt, liberty cannot long exist. We must realise that the need of this legislation comes from the need to fight for the liberty of our people. Our young people have resolved to usher in a clean and honest India. We cannot expect to be a global power with Albatross of corruption hanging around our neck. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Gujral. Now, Shri Ram Kripal Yadav.

श्री राम कृष्ण यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय , आज सदन में एक

अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है जिसमें काफी मामनीय सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। आज पूरे देश में अन्ना जी के आंदोलन की चर्चा है और अन्ना जी कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और इसको मैं मामता हूं। अन्ना जी की सोच अच्छी रही होगी, यह भी मैं मामता हूं, मगर अन्ना जी की टीम जबि मुद्दों को लेकर, जसि तरह से एक्ट करना चाहती है, मुझे लगता है कि इससे कहीं न कहीं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट करने का काम किया जा रहा है।

महोदय, आज आजादी को 64 साल हो गए हैं। हमारा बहुत ही पवित्र संविधान है और हमारे यहां महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो मामता हूं कि अन्ना जी एक

टीम के साथ नहीं , एक गरिह के साथ बंधे हुए हैं। गरिह अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए अन्ना जी को मसिगाड़ कर रहा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने की एक सोयी समझी साजिश है।

महोदय , डा. भीम राव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और बहुत ही छानबीन करने के बाद संविधान के निर्माताओं ने इसको लागू करने का काम किया , जिसे संविधान के तहत यह पार्लियामेंट है और हम सब यहां पर चुनकर आते हैं , आज पार्लियामेंट के ऊपर अविश्वास करने की कोशिश की जा रही है। महोदय , यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है। मैं शकिनन्द तकिरी और रामविलास पासवान जी के विचार से सहमत हूँ कि जब पार्लियामेंट का स्वरूप बदल रहा है , गरीब तबके के लोग आ रहे हैं , जबकि प्रतिनिधित्व नहीं होता था , लोगों में एवेयरनेस आई है , वे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं , तो निश्चित तौर पर ज़िम्मेदार लोगों ने हजारों वर्षों तक सत्ता , सभ्यता , संस्कृति और शिक्षा को अपने तक ही सीमित रखने का काम किया है , उन लोगों में एक डर सा पैदा हो गया है। इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की एक नई साजिश की जा रही है। जन लोकपाल जैसे विधायक को लेकर सुप्रीम ताकत के आधार पर देश में शासन करने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर यह शुभ संकेत नहीं है। इसलिए मैं आप से और माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि साजिश को समझने का काम करें। कोई यह कहे कि हम पार्लियामेंट को नहीं मानते हैं , स्टैंडिंग कमेटी को नहीं मानते हैं , किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं , तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां जाएगी ? इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा ? मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर एक साजिश की जा रही है , कोई षडयंत्र रचा जा रहा है और हम इस षडयंत्र के पात्र बन जाएं , तो हमें इससे अलर्ट होने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि लोकपाल विधायक बनना चाहिए और मज़बूत लोकपाल बने। यह संविधान के अंतर्गत बनेगा क्यों कि सदन कानून बनाता है और वर्षों से बनाता आया है। सब लोगों को इसकी चिन्ता है कि हम एक मज़बूत लोकपाल बलि बनाएं , जिससे हमारा भ्रष्टाचार नियंत्रित हो सके। हम अन्ना जी की टीम के सदस्यों से प्रश्न पूछना चाहते हैं। केवल दो - एक मिनट और

लेंगे।

महोदय , हमारे कई सदस्यों ने चर्चा की है कि स्वयं सेवी संस्था लोकपाल वधियक के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं आनी चाहिए ? आज स्वयं सेवी संस्था भारत सरकार या राज्य सरकार की कई चीजें देखने का काम कर रही हैं। आज स्वास्थ्य , शिक्षा व सोशल वेल्फेयर के जो काम हो रहे हैं , सभी NGOs के माध्यम से हो रहे हैं। उनके लिये वदिशों से भी पैसा आ रहा है। क्या इस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जाएगा ? क्या उनको छूट दे दी जाएगी। यह बात हम और आप सभी जानते हैं कि कतिने बड़े पैमाने पर NGO के नाम पर देश के खजाने की लूट हो रही है। उसको नियंत्रण से क्यों बाहर रखेंगे ? क्या वजह है ? महोदय , मैं वही जानना चाहता हूं कि कॉर्परेट सेक्टर पर नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए ? आज इस देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है , चाहे 2जी स्पेक्ट्रम हो या भ्रष्टाचार का दूसरा कोई अन्य मामला रहा हो , उनके अधिकारी आजकहीं न कहीं जेल में पड़े हुए हैं , आज उनका कहीं न कहीं इनवॉल्वमेंट है। उनको बाहर क्यों रखा जाए ? मैं पूछता हूं कि क्या करप्शन के साथ उनका जुड़ाव नहीं है ? उनको इससे बाहर रखने का काम क्यों कीजिएगा ? महोदय , मैं एक बात कहना चाहता हूं , जैसी कि कई माननीय सदस्यों ने चर्चा भी की है कि आज एक साजिश के तहत, कुछ लोगों को इकट्ठा करके बंदूक की नोक पर ये पार्लियामेंट को , सरकार को

झुकाना चाहते हैं , यह अच्छी बात नहीं है। आजकोई आदमी आकर एक लाख लोगों को जुटाता है और अपनी बात रखता है। आपको कतिना परसेंट सपोर्ट है , यह जनता तय करेगी , आने वाला समय तय करेगा। पार्लियामेंट में बहुत जल्द चुनाव आ रहे हैं , आप चाहते हैं कि हमारे अनुरूप कानून बने , तो आप आइए, लोक सभा चुनाव में स्वयं को खड़ा कीजिए और अपने अनुरूप पार्लियामेंट में कानून बनाने का काम कीजिए। हमारे जो चुने हुए सांसद हैं , उनके ऊपर 120 करोड़ की आबादी है। आप एक लाख , दो लाख लोग इकट्ठा करके चाहते हैं कि हम ताकत के बल पर, जबर्दस्ती , पार्लियामेंट को , स्थायी समिति को , लोकतांत्रिक व्यवस्था को , लोकतांत्रिक संस्थाओं को ताल पर रखकर, उनको इग्नोर करके कानून बना लें , तो मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं होगा। ये कहते हैं कि आज पूरा देश हमारे समर्थन में खड़ा हुआ है। आज गालियाँ दी जा रही हैं , लोगों को उकसाने के लिये न जाने क्या-क्या काम किये जा रहा है। आप क्या चाहते हैं ? आप इस चुम्बी हुई संस्था के प्रति लोगों को भड़का कर अपना कानून बनाकर , अपनी डिक्लेशन देकर , इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। महोदय , मैं आपसे नविदन करूँ ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (प्रो . पी . जे . कुरियन) : प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपसे नविदन करूँ कि निश्चित तौर पर हम सब... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude; otherwise, Shri Rajniti Prasad would not get time to speak.

SHRI RAM KRIPAL YADAV: I am concluding, Sir.

श्री राम कृपाल यादव : महोदय , मैं बोल रहा हूँ मैं आपसे नविदन करूँ , आप निश्चित तौर पर सभी कानूनों को बनाइए , पर मर्यादाओं के अनुरूप बनाइए , संस्थाओं को इग्नोर करके नहीं बनाइए। जो संवैधानिक अधिकार मल्लि हुआ है , उसके तहत कानून बनाइए , इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि आज उसी के तहत, संविधान से शासन चलता रहा है , तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों का खयाल रखना पड़ेगा। आज पूरे देश में जो स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है , वह निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिये शुभ संकेत नहीं है , खतरे की घंटी

हैं... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (प्रो . पी . जे . कुरियन) : समाप्त कीजिए। श्री सैफुद्दीन सोज़।

श्री राम कृष्ण यादव : अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट किया जाएगा , तो नश्चित तौर पर हमें और आप सभी लोगों को आने वाली जनरेशन माफ़ नहीं करेगी। इसलिए , मैं समझता हूँ कि आज नश्चित तौर पर कोई नर्णय होगा , जो संविधान के अनुरूप होगा। बहुत -बहुत धन्यवाद।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, when the hon. Prime Minister spoke in the other House extemporaneously, transparently and committed himself - he almost spoke from his heart - not only to Shri Anna Hazare but also to the nation that there will be a strong Lokpal and simultaneously made an appeal to Annaji, I had, at that moment, convinced myself and with relief in my mind, I went home, that Annaji would break his fast that day. But that did not happen because some of his advisors - it was said in the Press - did not allow him to do so. The other day, Shri Rahul Gandhi, made a statement saying that

there will be a strong Lokpal and he also said that this country needed a comprehensive bill by way of response to the menace of corruption in this country. But there was no response from Annaji's advisors and the people around.

But, today, I had a great satisfaction when I listened to hon. Pranab Mukherjee. As usual, he was at his best and he did not mince words when he spoke in the House. There was a situation in his mind that, cutting across party lines, there would be a response. And, I am so happy that the Leader of the Opposition, in his eloquent speech, responded very positively. In fact, the two speeches made other speakers to veer around the secret of those two speeches. I will come later to that; in fact, I wanted, at least, 20 minutes. But I will abide by the ruling from the Chair. Sir, I saw a situation, after a long time, in this august House, that hon. Pranab Mukherjee was lustily cheered, and hon. Arun Jaitley was also lustily cheered by the whole House. It was a heartening situation, and I hope, after some time, we shall reach a consensus. We showed that when it is needed, we are together. And this togetherness is epoch-making; it is historic. Hon. Jaitleyji warned us, cautioned us, that we should have a sense of proportion, a sense of rationality. Now, we should not react, - what is being said in Ramlila Maidan, I think, it is a good advice and it is a workable advice; we shall do that - but, cursorily, I will tell you two or three things about what happened in Annaji's *Andolan*. One of his supporters reminded us that we should look to Tripoli to see the strength of the people's power. It was, wholly, unacceptable to me. India has not wasted 64 years of independence; our achievements are reflection of that. Yesterday, one of his supporters, who wore a scarf - I do not want to name that person - said, "It was a *mukhota*" and characterized it by saying, "The MPs are behind the *mukhota* shirking their responsibility". These are responsible people, educated people! Now, for the grievances which they have suffered because of, maybe, perceived injustice, now they are waging a revenge on the nation and denigrating the Powers. Now, the Civil Society, in future, will have calm movements and correct the course, as it is. And, one of the supporters of Annaji - I read it in one of the newspapers - has said, "Five hundred and forty two VIPs are making fool of 120 crore

people.” Now, you can say to what extent they can go denigrating Parliament, refusing to accept the fact that this House and that House were chosen as representatives of the crores of people of this country. There was a feeling, in my mind, when I read these things – I would not say, ‘frustrated’ but there was a concern – that things were going wrong in this Andolan. And I felt, at that time, that there should be some institution for Parliamentarians, for democratic polity, to seek justice. I remembered Faiz Ahmad at that moment. This is not for Annaji, – he is a sincere man, and he has created the awareness among people – but for many others in that camp, this is correctly referred to them – بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی، منصف بھی

† [بنے ہیں اہل ہوس،

مدعی بھی، منصف بھی]

There is a complaint, and they act as judges. इसलिए फैज ने पाकिستان में कहा था۔

بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی، منصف بھی
کسی وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں

[اس لئے فیض نے پاکستان میں کہا تھا

بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی، منصف بھی

کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں]

We want to explain our case but where is the institution? So, such people have, through their speeches and so many statements, denigrated Parliament. They have refused to believe that we are a vibrant democracy, we have a strong secular base and we are a model of pluralism to the world. We are also a model of democracy to the world.
 اردو میں کہتے ہیں کہ جوش میں ہوش بھی ہونا چاہئے۔

اردو میں کہتے ہیں کہ جوش میں ہوش بھی ہونا چاہئے۔

They completely shut their eyes to the achievements of UPA-I and UPA-II. This is no time for me to count the number of laws that have been brought forward; there is a plethora of laws and our achievements have been spectacular. Many things have been done, and we do agree that

many things are yet to be done. But the way the supporters of Annaji have conducted themselves is unbecoming.

Sir, the hon. Leader of the Opposition, Shri Arun Jaitley, quoted articles from the Constitution of India. Now, I am not a legal luminary. He quoted articles 105, 311, 320 of the Constitution of India, and was giving certain ideas of his to this House. And, we agree with him. That is what Pranabda had also said, that there would be a strong Lokpal. But we shall not create a situation where we have to thwart the laws that are already in existence. Therefore, these articles will ensure that we shall have a strong Lokpal without creating any difficulty for the legal system of the country. Since I have to conclude, I shall quickly make a couple of suggestions. Now, we must have a strong Lokpal.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have only two minutes more.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I will finish by that time, and I have another couplet to offer.

†Transliteration in Urdu Script.

We must have a strong Lokpal, but we must keep the federal structure of the Constitution in mind. And, as far as the Lokayukta is concerned, it must be left to the State Legislature. You may, at best, have a model for them; they may accept it or may not accept it. We must leave it to them. That is our democracy. We have a strong federal base in the Constitution. We have a strong unitary base in the Constitution, but we are a federation of States. So, we must show respect to our States and State Legislatures.

Thirdly, we must have an institution for redressal of grievances. We should have a mechanism for that; we are already late in doing that. Then, we must have a Judicial Commission. On the Judicial Commission, Mr. Chairman – I have a grievance with Mr. Arun Jaitley; unfortunately for me, he is not here; and I crave the indulgence of this House – it was in 2003, when, luckily for me, I had moved a Private Member's Resolution on accountability of the Judiciary and I had proposed that there should be a Judicial Commission. (*Time-bell rings*) Hon. Arun Jaitley had delivered a very good speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes. Please conclude.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: So many lawyers spoke that day. Then he came to my seat and said, "Cutting across Party lines, all Members have agreed with you. Now, if you put it to vote, it will be negated; that is not the sense of the House". So, he convinced me to withdraw the Resolution on that day.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, conclude.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Please, give me two more minutes to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Why don't we have a Judicial Commission? Three Justices...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. Please, conclude.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Justice Khare and Justice Verma lamented the fact that...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. No time now. Please conclude.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: They had no mechanism to punish erring Judges. This is needed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, conclude.

8.00 P.M.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Let me offer a couplet here. But I want to tell you that we are late for a Judicial Commission. Justice Khare and Justice Verma lamented the fact - and it appeared in the Press - that they didn't have any mechanism in the Judiciary to punish erring Judges. Impeachment is a long-drawn affair. Therefore, we are late for a Judicial Commission.

Now, I was telling the House that it had assured me in 2003 that within a month or two there would be a Judicial Commission in place.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

In this direction, we have to take steps; and today, this consensus has been built on a very brilliant speech delivered by hon. Shri Pranab Mukherjee and the powerful and positive response from Shri Arun Jaitley. बात कैसे बनती है, उस पर मैं एक शेर अर्ज करता हूँ ,

کرنا عرض شعر ایک میں پر اس ہے، بنتی کیسے بات

because there is a situation of relief in my mind that this House is together. And, this togetherness is exemplary. This is a historic movement. Through this couplet, Annaji and his colleagues would also receive a hint. How did we come to this consensus? Because, we gave a thinking to this question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

प्रो . सैफुद्दीन सोझ : आप उर्दू से इत्तिफाक रखते हैं ?

चमन में इत्तिफाके रंगो बू से बात बनती है ,

तुम ही तुम हो , तो तुम क्या हो , हम ही हम हैं , तो हम क्या हैं

پروفیسر سیف الدین سوز : آپ اردو سے اتفاق رکھتے ہیں؟

چمن میں اتفاق رنگ و بو سے بات بنتی ہے

تم ہی تم ہو، تو تم کیا ہو، ہم ہی ہم ہیں، تو ہم کیا ہیں

Sir, Annaji has created an awareness. Now, we should not arrogate all powers to him. He should now leave it to Parliament. I am fully confident that Parliament will do its duty to the nation. Thank you.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I would like to express my deep

appreciation for all the 26 hon. Members who have made their contribution in this important discussion. While initiating the discussion on my statement, the hon. Leader of the Opposition raised the level of the debate by saying that this is not an ordinary debate because on the one side of the spectrum is an agitation

†Transliteration in Urdu Script.

of the people led by a very popular leader, through Gandhian way, on a very legitimate concern, of eradicating corruption from every stratum of society with which all of us share, and, on the other hand, to maintain and uphold the Constitutional scheme, principles and norms, and to find out a mechanism through which we can achieve this objective.

Mr. Deputy Chairman, Sir, in my introductory observations, I did not discuss the merits and demerits of the Lokpal Bill. I concentrated on narrating the chronological events how the Government responded to a particular situation, to a particular agitation. I am recalling, rather repeating what I have said in the morning. When he decided to sit on fast for an indefinite period on the issue of corruption on 5th April, recognising the gravity of the issues, the Prime Minister immediately instructed some of our colleagues to establish contact with Annaji and to find out what could be done to ensure that he gives up his fast. As a result of this interaction, the joint mechanism came. Five members nominated by him, including himself; and five members nominated by the Prime Minister. The Committee functioned under my Chairmanship and under co-Chairmanship of Shri Shanti Bhushanji. We were criticized, and rightly so. We were criticized that why we were making a deviation from the normal legislation making process. But, at the same time, most respectfully, I would like to submit this for the consideration of the House, and this is the reason what prompted us to do it. I shared my own perception on this issue when I was in Hanoi, and had a television interview either with the Reuter or BBC, I do not remember exactly, I was confronted with the question: Why have you done it? My response to that was, "Ours is the largest functional democracy. Democracy of 120 crores plus people. It is not static. It is dynamic. It is bringing many changes. Changes are coming through nonconventional way. It does not infringe the rights, does not violate the norms, but it adds a new dimension in the process of consultation." What was the system? The Standing Committees came into existence only in 1993. But this House is functioning from 1952 under the new Constitution. So many legislations have been passed. What was the practice? The Departmental Minister, in consultation with

his Ministerial colleagues, used to tell the Departmental Secretary to draft the legislation, giving him the ideas which the Minister had. And after inter-Ministerial consultation, with the approval of the Cabinet, it was placed in the House. But, even in those days, even from the days of Central Assembly, even from the procedures established under the Montague Chelmsford Reforms of 1919, subsequently under the Government of India Act of 1935, the Parliamentary procedure was, when the Bill was introduced by the Minister, any Member could rise and make a motion that let the Bill be circulated amidst the public for seeking their opinion. But all these used to take place after the Bill has been introduced in the House by the Government, with the Cabinet's approval. This time, we made an exception because the situation was grave. For 40 years, the debate is going on. As the Leader of the Opposition very

correctly pointed out, the first Bill was listed in 1968. The debate took place in 1962-63, where the word "Lokpal" was coined by the illustrious Member of Parliament, Dr. L.M. Singhvi, an eminent Jurist who was our High Commissioner also in U.K." But, somehow or other, in the 70s, in the 80s, in the 90s and in the first decade of this century, we could not get the legislation done. I am not passing any blame to anybody. We were in the Government. I myself was in the Government in 70s, in 80s, in 90s; and again, I am there. We could not do it. The NDA could not do it; the United Front could not do it. It was not done it is a fact. Therefore, when an agitation is taking place by a Gandhian, by an idealist and receiving massive support from the people, if we go out of convention, out of normal straightjacket approach, is it wrong because we have not diluted the Constitutional norms, practice in any way? I made it quite clear that it is with the prior consultation with the Civil Society, after this we will go through the normal legislation making process and exactly we did so. Unfortunately, despite our efforts, nine meetings, series of interactions, we could not have 100 per cent agreement. But as I mentioned, out of 40 basic principles, as many as on 34 we had agreement and all those have been incorporated in the Lokpal Bill which is under consideration of the Standing Committee. A Bill when it is considered in the Standing Committee that is not the final word. Criticism has been made that it is weak, it is vulnerable, it does not reflect the desire of the political parties or their intentions. Maybe, but the final word has not been occurred. The Members of the political parties represented in the Parliamentary Standing Committee can move amendments to strengthen the Bill. When the Bill is being brought after the Cabinet's approval on the recommendations of the Standing Committee, they can move the amendments. It is for the House to decide. But what is the argument when the Bill is burnt is burnt publicly? What is the reason that the Bill be withdrawn? What is the justification of this demand? We are told in the all-party meeting on 3rd July that Government do the legislation, draft the Bill, introduce

the Bill. You may like it or you may not like it. You have every right to criticize it. But what is argument of telling that 'you withdraw the Bill'? What is the logic of burning the copies of the Bill in public? In democracy, there will be dissensions of views, there will be disagreement. In nine meetings we could not arrive at a consensus on 100 per cent basis. Substantially we did. If you have gone through the clauses- these are all on the website of the Department of Personnel, these are in the domain of the public knowledge - you can verify it how many ideas of Jan Lokpal Bill we have incorporated in the Lokpal Bill which is under the consideration of the Standing Committee. Therefore, I am not going into the merits of the Bill because we will have the opportunity of discussing it largely and in one way, I am little bit included in this area. My colleague, Mr. Narayansamy is the appropriate

Minister. But as the Prime Minister instructed me to deal with the Civil Society's representatives, I had to do this job and that is why I have been asked to deal with this issue. The Ministerial responsibility, of course, is with the Minister in charge, Shri Narayanasamy who will do full justice to this. But the third point which I am trying to drive at is, do we seriously believe – any one of us sitting either this side, that side, centre, right – that with the passage of this Bill, all corruptions will be eradicated? One piece of legislation, however complete and fool-proof it maybe, one very powerful independent institution can eradicate corruption from every section of the society or many more efforts are to be made. My respectful submission is, many more efforts have to be made. Many of you have made suggestions, good suggestions. Question of independence of Lokpal has arisen. You pointed out. Yes, we have provided. They will have full independence. They will have the right to select their own people, I mean employees. Their expenditure will not be voted by Parliament, it will be charged. But if we have differences in the area, when they suggest that whatever Search committee will recommend in that order 1,2,3, Selection Committee headed by the Prime Minister of the country will have to pick up from them and if we disagree with it, have dissention, is it an unpardonable offence? Therefore, we are attempting to change the system. The Leader of the Opposition was in Government for quite sometime. He knows. Mr. Shanta Kumarji is also there. They were all in the Government and, particularly, in my Department, the Minister of Finance's constant complaint from the tax payers is about the refund and we have introduced, taking the advantage of modern technology, e-filing, Central processing of Bengaluru. They are using a new term. I did not learn in my school days, that English term, 'Electronisation' of the returns of the system. As a result, in this year, in the first three months, Income Tax Department has given refund of more than 37 per cent. Complaint is not there and not in a single case the tax payer and tax collector had to face each other. Everything was transacted electronically. We are

going to have various social sector programmes. All you are complaining about the leakage. Yes, you do have Ombudsman, you have Lokpal, you have strong vigilance but at the same time, unless we address the system, Rs. 1,85,000 crores through various social sector programmes in this year's Budget which have been allocated will go. If we can, taking the advantage of the new technology, create the appropriate IT platform, use it effectively – whether it is Mahatma Gandhi's NREGA, whether it is old age pension, whether it is widow pension – the leakage could be substantially reduced. Prime Minister has set up a Unique Identity Authority under Nandan Nilekani and we are hoping to provide, give a Unique Identity Number to 20 crores of people by the month of October. In the couple of years, we are going to provide Identity Number to each and every resident of the

country; I am not merely talking of the citizen of the country. These are the major changes taking place. The problem is Herculean. But, we are addressing these problems in the form of systematic changes – changes in the regulatory framework, changes in the laws, establishing the institutions, etc. If you look at between our Government and their Government from 1991 onwards, you will find how much they have reduced the discretionary powers of the Ministers. In 80s, when I was Finance Minister, the entire empire was with me. Except the RBI Governor, there was no other regulator. I was the monarch of all I survey. Banks, insurance and everything was controlled by Minister. Today there are regulators. They are empowered with statutory powers, since Doctor Sahab has introduced the liberalized economy. And, I must appreciate that NDA Government had followed it. The United Front Government also followed that. They had strengthened. But, further strengthening of these is required. Therefore, keeping those objectives in view, we are trying to address the problem.

But, there are certain issues where we have to say, 'Sorry. We cannot go beyond a point.' Legislation is the domain of Legislature and Parliament. So far as the Union List I to the Seventh Schedule is concerned, nobody else, other than Parliament, can make laws. Others can give suggestions, can make recommendations, but law is to be made, as per the Union List I, by Parliament and Parliament alone. The Executive's power of making law is extremely limited through the Ordinance route which is only for a few months. But, they are required to be approved by Parliament as soon as it meets after promulgation of Ordinance. Therefore, I have to convince them on these issues. I admit; I have failed. We could not carry conviction. But, today, when I am speaking, I would not like to expand my observations, because neither I have any intention to score a debating point nor to contradict anybody. The sense of co-operation, which has been built up, during the course of discussion, for which we have tried our best to arrive at national consensus as how to tackle this problem, how to avoid the so-called apparent conflict between civil society and political establishment and political spectra, is quite appreciable.

Keeping that in mind, I understood – if I have not listened to all of you sitting here – and have the privilege of listening to you in my room on television. I obtained copious note from colleagues about the observations which you have made.

Once again, I would congratulate you for raising the level of the debate, and not allowing acrimonious acquisitions and allegations against each other. That is a healthy sign. If we want to get back the confidence of the people, perhaps, we shall have to ensure that these premier institutions function, function as per the norms, rules set up by us. We are in the unique position that we regulate our own functioning. If we do that, I think, many of the issues will be corrected automatically. Taking the sense of the observations of various Members, I would like to place,

Mr. Deputy Chairman, Sir, for the consideration of the House that if we put it in this form, the House discussed various issues relating to setting up of a strong and effective Lokpal Bill, this House agrees, in principal, on the following issues: Citizens Charter; lower bureaucracy also to be under the Lokpal, through an appropriate mechanism; and establishment of Lokayukta in the States, and further resolves to transmit the proceedings of this House of today to the Department-related Parliamentary Standing Committee for its perusal while formulating its recommendations on the Lokpal Bill, which is under their consideration. If it is agreed upon, I feel, on the basis of that we can request Shri Anna Hazare to end his fast and let there be no so-called conflict between the civil society and parliament or political establishments. Thank You, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet on Monday, the 29th August, at 11.00 a.m.

The House then adjourned at twenty-six minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Monday, the 29th August, 2011.